चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित | 20 जून- 26 जून 2016 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

मथुरा-कांड

समाजवादी पार्टी के दो नेताओं की वर्चस्वी-खींचतान में उत्तर प्रदेश की क़ानून-व्यवस्था ध्वस्त

कहां सरकार?

दो अफ़सरों की निर्मम हत्या से भड़के नौजवान सिपाहियों ने विद्रोह करके की सीधी कार्रवाई

जयगुरुदेव की अथाह संपत्ति के उत्तराधिकारी पंकज यादव के सिर पर है शिवपाल का हाथ

जयगुरुदेव आश्रम से बेदख़ल किए गए रामवृक्ष यादव को मिल रहा था रामगोपाल का संरक्षण

दो साल से जवाहरबाग़ पर था रामवृक्ष का क़ब्ज़ा, लीज़ पर देने की हो रही थी साज़िश

रामगोपाल के बेटे को जितवाने में झोंक दी थी ताक़त, बदले में 'पद' मिलने का था वादा

बाग़ और पद नहीं मिलने से गुस्से में था रामवृक्ष, सियासत की बिसात पर ढेर हो गया मुहरा

सूत्रधारों को बचाने के लिए पुलिस और नक्सलियों पर ठीकरा फोड़ने की कोशिशें नाकाम

पुलिस प्रशासन को दो साल से पंगु बना कर रखने के सत्ताई रवैये के ख़िलाफ़ भीषण आक्रोश

प्रभात रंजन दीन

मथुरा में सरकारी उद्यान पर दो साल से कब्जा जमाए सत्ता-संरक्षित असामाजिक तत्वों के हाथों दो पुलिस अधिकारियों का मारा जाना उत्तर प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी के राजनीतिक-चरित्र का आपराधिक-प्रतिफल है. दो साल से जबरन चुप बैठा कर रखी गई पुलिस की अचानक हुई निर्णायक कार्रवाई सत्ताधारी दल के गंदे राजनीतिक चरित्र के खिलाफ खुला विद्रोह है. मथुरा कांड का लब्बोलुबाब यही है. अपने दो अधिकारियों को बेतरह मरता देख कर युवा पुलिसकर्मियों का खून खौल उठा, फिर वे किसी के नियंत्रण में नहीं थे. नौजवान सिपाहियों ने नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और सीधा हमला बोल दिया. नौजवान सिपाहियों का गुस्सा अफसरों और उन पुलिसकर्मियों पर भी था जो दो अधिकारियों को मौके पर छोड़ कर भाग आए थे. जब कार्रवाई पूरी हो गई, तब आला पुलिस अधिकारियों को मौके पर पहुंचने का मौका मिला. पुलिस की इस कार्रवाई से पूरी सरकार और समाजवादी पार्टी के नेता हतप्रभ हैं. यही वजह है कि सत्ता प्रमुख से लेकर दूसरे नेता तक घटना के लिए पुलिस को ही दोषी ठहरा रहे हैं.

उत्तर प्रदेश सरकार आधिकारिक तौर पर यह तथ्य सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही कि मथुरा के जवाहरबाग पर दो साल से कब्जा जमाए रामवृक्ष यादव को सरकारी बाग लीज़ पर देने के अलावा उसे क्या-क्या राजनीतिक आश्वासन दिए गए थे? किस राजनीतिक आश्वासन के पूरा नहीं होने पर रामवृक्ष को गुस्सा आ गया? गुस्साए रामवृक्ष के किन समर्थकों ने दारोगा और एसपी पर गोली चला दी और पुलिस को भड़का दिया? जिन लोगों ने पुलिस के सामने ही एसपी और दारोगा पर प्वाइंट-ब्लैंक गोली चलाई, उन हमलावरों की पहचान क्यों नहीं हुई? अगर उनकी पहचान हुई तो वह सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? हमलावर मारे गए या फरार हो गए? वर्ष 2014 से लेकर 2016 तक यूपी सरकार क्यों चुप्पी साधे रही और सैकड़ों एकड़ के सरकारी बाग को अवैध कब्जे से मुक्त क्यों नहीं कराया? रामवृक्ष यादव के स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह संगठन की गैरकानूनी गतिविधियों को सरकार क्यों तरजीह देती रही? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मथुरा कांड की न्यायिक जांच की घोषणा तो कर दी है और सीबीआई जांच से बचने के लिए यह एक बेहतर चाल भी है, लेकिन इससे यूपी सरकार जनता के सामने बुरी तरह एक्सपोज़ हो गई है. तमाम सियासी साजिशों में उलझे हुए इस मामले की जांच जहां सीबीआई की विशेषज्ञ टीमें करतीं, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के रिटायर्ड जज इम्तियाज मुर्तजा अकेले उसकी गुत्थियां सुलझाएंगे. मतलब, जांच का हश्र क्या होगा, इसके बारे में अनुमान अभी से लगाया जा सकता है. मथुरा कांड प्रकरण के नख से शिख तक समाजवादी पार्टी के अलमबरदारों की भूमिका स्पष्ट है, लिहाजा सरकारी सहयोग के बगैर न्यायिक जांच एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगी. सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार मथुरा कांड की न्यायिक जांच में एक सदस्यीय जांच आयोग के साथ ईमानदारी से सहयोग करेगी? इस सवाल को उसी अनुत्तरित दशा में छोड़ कर हम जल्दी से हालिया घटनाक्रम का जायजा लेते चलें. मथुरा के सरकारी उद्यान जवाहरबाग पर दो साल से कब्जा जमाए रामवृक्ष यादव और उसके समर्थकों को हटाने के लिए दो जून को अचानक पुलिस पहुंच जाती है. बिना किसी तैयारी के जवाहरबाग पहुंचे सिटी एसपी मुकुल द्विवेदी और फराह थाने के प्रभारी संतोष कुमार यादव को पुलिस बल के सामने ही सीधे गोली मारी जाती है. पुलिस को मौके से भाग जाना पड़ता है. लहूलुहान पुलिस अधिकारियों को किसी तरह घसीट कर बाहर निकाला जाता है. उसके बाद पुलिस के नौजवान सिपाही भड़क उठते हैं. वे अब पूरी तैयारी से जवाहरबाग परिसर में दाखिल होते हैं और हिंसक भीड़ को काबू में करने के लिए सीधी कार्रवाई करते हैं. पुलिस की सीधी कार्रवाई और फायरिंग में तकरीबन 30 लोग मारे जाते हैं. शुरुआत में मैदान छोड़ कर भागने पर विवश हुई पुलिस और जवाहरबाग परिसर में मची भारी भगदड़ में असली हमलावर भाग नहीं गए, इसकी क्या गारंटी है? और जब पुलिस तैयारी के साथ जवाहरबाग पहुंची तब असली हमलावर ही मारे गए इसकी क्या गारंटी है? यानी, पूरा मसला जबरदस्त फंसावट में है. देश का यह पहला ऐसा कांड है, जिसमें पुलिस की गोली से या हिंसा में मारे गए लोगों की शिनाख्त सार्वजनिक नहीं की गई. यहां तक कि सरगना रामवृक्ष के बारे में भी फौरी तौर पर बता दिया गया कि वह मारा गया, लेकिन उसकी लाश सार्वजनिक करने में सरकार को शर्म आती रही. लोगों को पेंच तब समझ में आया जब रामवृक्ष के परिवार वालों ने लाश पहचानने और लाश ले जाने से इन्कार कर दिया और उसके वकील समेत कुछ अन्य लोगों ने यह दावा किया कि रामवृक्ष मरा ही नहीं है. इसके बावजूद सरकार ने रामवृक्ष की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं की. विडंबना यह है कि जिस रामवृक्ष को प्रदेश की पूरी सत्ता जानती थी, जो सपाई गलियारे का जाना-पहचाना चेहरा था, जिसे सपा के वरिष्ठ नेता का सीधा संरक्षण मिला हुआ था, उसकी पहचान के लिए हरिनाथ सिंह नाम के एक व्यक्ति को जेल से निकाल कर लाया गया और उससे पहचान की औपचारिकता पूरी कराई गई. हरिनाथ सिंह नक्सली है और यह प्रहसन मात्र इसलिए खेला गया ताकि मथुरा कांड का पूरा ठीकरा अनाम नक्सली संगठनों के मत्थे फोड़ा जा सके और अपनी खाल बचाई जा सके. लेकिन सरकार की यह मंशा पूरी नहीं हो सकी.

मथुरा कांड के जो भी सियासी सूत्रधार हैं, उनके खिलाफ दो पुलिस अधिकारियों और तकरीबन ढाई दर्जन लोगों की हत्या का मुकदमा चलना चाहिए. मथुरा कांड सत्ता के दो केंद्रों को नंगा करने वाला प्रकरण साबित हुआ है. इसमें तीसरा कोण भाजपा का भी है, जिसने घालमेल करने और लोगों में भ्रम पैदा करने की पूरी कोशिश की, जो कम खतरनाक नहीं है. रामवृक्ष यादव को समानान्तर सरकार बनाने की ताकत बनने का मौका देने वाले समाजवादी पार्टी के नेता प्रो. रामगोपाल यादव के ऊपर विशाल छत्र डालते हुए भाजपा ने दिल्ली समेत तमाम जगहों पर आनन-फानन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली और रामवृक्ष को संरक्षण देने के सारे आरोप सपाई सत्ता के दूसरे धुर शिवपाल यादव पर थोप दिए. भाजपा की इस हरकत ने जानने वालों को एक बार फिर से जनवाया कि समाजवादी पार्टी के अंदर के भाजपाई-सहानुभूतिकर्ता रामगोपाल यादव ही हैं, जिन्होंने सपा को महागठबंधन से अलग कराया और देशभर में सपा की फजीहत कराई. महागठबंधन से अलग होने के फैसले का शिवपाल यादव ने कड़ाई से विरोध किया था और अब भी पुराने समाजवादियों की वृहत्तर एकता के लिए वे सक्रिय हैं. यह बात भाजपा को अंदर से चुभती रही है. उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव जब सामने है, ऐसे में सत्ता के दो केंद्रों की भिड़ंत से प्रदेश में अराजकता का फैलाव कहीं न कहीं भाजपा को सियासी नफा के बतौर दिखता है. जयगुरुदेव की अथाह संपत्ति के दो दावेदारों पंकज यादव और रामवृक्ष यादव के बीच उमाकांत तिवारी की भूमिका ठीक वैसी ही रही है, जैसे शिवपाल और रामगोपाल के बीच भाजपा ने निभाई. संघ और भाजपा से जुड़े उमाकांत तिवारी का अब कोई नाम भी नहीं ले रहा.

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल को रामवृक्ष यादव का सरपरस्त बताने की भाजपा ने तथ्यात्मक गलती की है. जयगुरुदेव आश्रम के मौजूदा प्रमुख पंकज यादव के सिर पर शिवपाल का हाथ रहा है. पंकज यादव और रामवृक्ष यादव में जानी दुश्मनी है, क्योंकि पंकज यादव ने ही रामवृक्ष और उमाकांत को आश्रम से बेदखल किया था. जयगुरुदेव आश्रम से बेदखल किए गए रामवृक्ष यादव पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव ने हाथ रखा. केंद्र सरकार को भेजी रिपोर्ट में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मथुरा प्रकरण में राजनीतिक सरपरस्ती और साजिश से इन्कार किया और सारी नाकामी पुलिस पर डाल दी. रामवृक्ष और उसके गिरोह द्वारा जवाहरबाग परिसर में जमा किए गए हथियारों के तथ्य से अखिलेश इन्कार तो नहीं कर सकते थे, लेकिन इसमें पेंच डालते हुए उन्होंने इसका नक्सल-लिंक निकालने की नाकाम कोशिश की.

रामवृक्ष यादव को क्या राजनीतिक आश्वासन दिए गए थे, उसके अमल में नहीं आने की क्या वजहें रहीं, इसे जानने के क्रम में हम उन पहलुओं को जानते चलें जिनकी तरफ अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिलाया. सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के परिवार के दो सदस्यों (शेष पृष्ठ 2 पर)

गुंडे के साथ खड़ी रही सत्ता, औंधे गिरे रहे मुख्य सचिव

मथुरा कांड में उत्तर प्रदेश सरकार और प्रदेश की सत्ताधारी समाजवादी पार्टी ही असली अपराधी है. सरकारी उद्यान जवाहरबाग को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के 20 मई 2015 के फैसले पर समाजवादी पार्टी की सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया. राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ का आदेश भी ठेंगे पर रख दिया. विवश होकर अदालत को सरकार के खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलाना पड़ा. इसके बावजूद सरकार सुधरने का नाम नहीं ले रही. सरेआम गुंडागर्दी पर उतारू रामवृक्ष यादव के साथ सरकार की इस कदर साठगांठ थी कि उसके आगे मुख्य सचिव आलोक रंजन ने भी घुटने टेक दिए. मथुरा के जिलाधिकारी ने 15 अगस्त 2014 को ही मुख्य सचिव आलोक रंजन को पत्र लिख कर सरकारी उद्यान पर कब्जा किए जाने और सरेआम गुंडागर्दी किए जाने के बारे में विस्तार से सूचना दी थी. लेकिन मुख्य सचिव ने सत्ता-शीर्ष के इशारे पर चुप्पी साध ली. आधिकारिक दस्तावेज बताते हैं कि जवाहरबाग पर रामवृक्ष ने एक जनवरी 2014 को ही कब्जा कर लिया था.

आगरा के कमिश्नर ने 18 अप्रैल 2015 को ही मथुरा के जिलाधिकारी और एसएसपी को जवाहरबाग मामले में त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया, लेकिन मथुरा के डीएम और एसएसपी ने कमिश्नर का आदेश नहीं माना. मथुरा के जिला उद्यान अधिकारी ने 17 मार्च 2015 को आगरा के कमिश्नर, मथुरा के डीएम और एसएसपी को यह जानकारी दी थी कि जवाहरबाग पर अवैध कब्जा जमाए बैठे लोगों ने सरकारी बाग के ढाई हजार बेशकीमती फलदार वृक्ष जला डाले हैं. इस पर भी जिला प्रशासन नपुंसक बना बैठा रहा. इस सत्ता-जनित हिंसात्मक के कारण ही दो पुलिस अधिकारी मारे गए और सरकार की इतनी छीछालेदर हुई.

समाजवादी पार्टी के दो नेताओं की वर्चस्वी-खींचतान में उत्तर प्रदेश की क़ानून-व्यवस्था ध्वस्त

कहां सरकार?

पृष्ठ 1 का शेष

रामगोपाल और शिवपाल के बीच उत्तर प्रदेश के पश्चिमी-दक्षिणी हिस्से के अलीगढ़, आगरा, मेरठ और कानपुर मंडल में सियासी वर्चस्व (पर्सनालिटी-कल्ट) स्थापित करने की होड़ अर्से से रही है. मथुरा-दिल्ली रोड पर सैकड़ों एकड़ जमीन पर कब्जा जमा कर आश्रम बनाने वाले इटावा निवासी तुलसी यादव उर्फ जयगुरुदेव बाबा और उनके अनुयाइयों की भारी जमात का समर्थन शिवपाल को मिलता रहा है और यह बात रामगोपाल को हमेशा खलती रही है. जयगुरुदेव की मृत्यु के बाद रामगोपाल ने उनके एक शिष्य रामवृक्ष यादव को अपने संरक्षण में लिया लेकिन जयगुरुदेव के एक अन्य ताकतवर शिष्य व बाबा के वाहन चालक पंकज यादव को शिवपाल यादव पहले से ही अपने आभामंडल में ले चुके थे. दिल्ली-मथुरा रोड आश्रम और उसकी अकूत सम्पत्ति पर कब्जा जमाने में भी शिवपाल बाजी मार ले गए और अपने शिष्य पंकज यादव को आश्रम का प्रमुख और जयगुरुदेव का उत्तराधिकारी बनवाने में कामयाब हो गए. पंकज यादव का लखनऊ आना और शिवपाल का मथुरा जाना या विभिन्न कार्यक्रमों में दोनों का मिलना-जुलना भी रामगोपाल को खटकता रहा. रामगोपाल ने रामवृक्ष की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जगाईं और मथुरा के ही डाई सौ एकड़ के जवाहरबाग उद्यान में आश्रम बनवाने का आश्वासन देकर उसका भरपूर इस्तेमाल किया. सपा के सूत्र यह भी बताते हैं कि जवाहरबाग में आश्रम स्थापित करने के अलावा रामवृक्ष को किसी राजनीतिक पद पर आसीन कराने का भी गुपचुप राजनीतिक स्वप्न दिखाया गया था. रामवृक्ष की राजनीतिक महत्वाकांक्षा काफी पहले से हिलकोरें ले रही थी. उसने गाजीपुर लोकसभा और जहूराबाद विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ा था. रामवृक्ष की महत्वाकांक्षाएं कुरेदकर उसे व उसके जुझारू समर्थकों की पूरी फौज फिरोजाबाद लोकसभा चुनाव में झोंक दी गई थी. रामवृक्ष यादव ने भी रामगोपाल यादव के प्रत्याशी बेटे अक्षय यादव के पक्ष में पूरी ताकत लगा दी. फिरोजाबाद लोकसभा सीट से अक्षय यादव के चुनाव जीतने के बाद रामवृक्ष यादव ने दोनों आश्वासनों को अमल में लाने का दबाव बनाना शुरू किया. जवाहरबाग को आश्रम के लिए 99 साल के लीज़ पर देने का मसला करीब-करीब तय हो गया था. शासनतंत्र को इस बारे में बता भी दिया गया था, लेकिन औपचारिक आदेश जारी करने की सरकारी प्रक्रिया ढीली कर दी गई और इसमें देर होती रही. स्थानीय प्रशासन दो धुरों के द्वंद्व में फंसा रहा. सत्ता के दूसरे धुर की तरफ से सीधा हस्तक्षेप हो उसके पहले ही मामला अदालत में पहुंचवा दिया गया और सरकार को अपने कदम रोकने पड़े. सियासत की बिसात पर भी शिवपाल के आगे रामगोपाल की गोट धड़ाधड़ धराशाई होती रही. उनकी मर्जी के बगैर कई लोग राज्यसभा और विधान परिषद पहुंच गए, यहां तक कि मुलायम के निजी सेवक रहे जगजीवन तक को विधान परिषद की सीट मिल गई, लेकिन रामवृक्ष यादव को कुछ नहीं मिल पाया. इस वादा-खिलाफी ने रामवृक्ष को काफी उग्र कर दिया. इसका नतीजा सामने है. आने वाले विधानसभा चुनाव में रामवृक्ष यादव और उसके मजबूत कैडर के इस्तेमाल की रामगोपाल की रणनीति भी इसके साथ ही ध्वस्त हो गई.

मुक़दमों की लंबी फ़ेहरिस्त तो क्यों नहीं की कार्रवाई?

मथुरा के सरकारी उद्यान जवाहरबाग पर कब्जा जमाए बैठे रामवृक्ष यादव और उसके गुर्गों पर जून 2014 से ही आपराधिक मुकदमे दर्ज होने शुरू हो गए थे. मुकदमों की फेहरिस्त देखेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे कि इतने मुकदमों के बावजूद सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की. तब आप यह भी महसूस करेंगे कि स्थानीय प्रशासन और स्थानीय पुलिस को किस कदर पिछले दो साल से पंगु बना कर रखा गया था. मुकदमों का जायजा आप भी लें...

1. 17 जून 2011 को जयगुरुदेव आश्रम निवासी रवि और सुरेशचंद्र पर हमला. हमलावरों के अगुआ रामवृक्ष यादव समेत 15 लोगों पर जानलेवा हमला, बलवा, मारपीट और धमकी दिए जाने का मुकदमा दर्ज.
2. 7 जून 2014 को मथुरा जिला उद्यान अधिकारी मुकेश कुमार ने रामवृक्ष और उसके 250 गुर्गों पर सरकारी सम्पत्ति पर कब्जा जमाने, क्षति पहुंचाने और विरोध करने पर गाली-गलौज कर धमकी देने की रिपोर्ट थाना सदर बाजार में दर्ज कराई थी.
3. 15 जून 2014 को जवाहरबाग के सरकारी ठेकेदार जयप्रकाश ने बाग के फल तोड़ने, पेड़ काटने और मना करने पर जान से मारने की धमकी दिए जाने की रिपोर्ट थाना सदर बाजार में कराई थी.
4. 24 सितम्बर 2014 को जिला उद्यान अधिकारी मुकेश कुमार ने सरकारी सम्पत्ति पर कब्जा करने, क्षति पहुंचाने और विरोध करने पर गाली-गलौज कर धमकी देने की रिपोर्ट थाना सदर बाजार में दोबारा दर्ज कराई थी.
5. 2 अक्टूबर 2014 को जवाहरबाग के संरक्षण अधिकारी किशन सिंह ने गाली-गलौज करके सरकारी कार्य में बाधा डालना और सरकारी सम्पत्ति पर कब्जा करने का मुकदमा रामवृक्ष व उसके समर्थकों के खिलाफ थाना सदर बाजार में दर्ज कराया था.
6. 29 नवंबर 14 को जिला उद्यान अधिकारी मुकेश कुमार ने फिर से सरकारी सम्पत्ति पर कब्जा करने, क्षति पहुंचाने और विरोध करने पर गाली-गलौज कर धमकी देने की रिपोर्ट थाना सदर बाजार में दर्ज कराई.
7. 22 जनवरी 15 को सदर थाने के प्रभारी प्रदीप कुमार पांडेय ने सरकारी कार्य में बाधा डालने, सरकारी सम्पत्ति पर कब्जा करने, क्षति पहुंचाने और विरोध करने पर गाली-गलौज कर धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
8. 15 जून 2015 को जवाहरबाग के सहायक उद्यान निरीक्षक रामस्वरूप शर्मा ने रामवृक्ष यादव समेत 150 लोगों पर बलवा करने, गाली-गलौज करने, सरकारी सम्पत्ति कब्जा करने और धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
9. 15 जून 2015 को जवाहरबाग के सहायक उद्यान निरीक्षक रामस्वरूप शर्मा ने रामवृक्ष यादव और स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रही के 150 सदस्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.
10. 27 मई 15 को जवाहरबाग में तैनात कर्मचारी जगदीश प्रसाद ने रामवृक्ष यादव, चंदनबोस समेत 20 लोगों को नामजद करते हुए 100-150 लोगों के खिलाफ मारपीट कर जवाहरबाग की सम्पत्ति पर कब्जा करने की रिपोर्ट थाना सदर में दर्ज कराई थी.
11. 16 मार्च 2016 को कलेक्ट्रेट के कर्मचारी देवी सिंह ने रामवृक्ष यादव समेत अन्य लोगों के खिलाफ मारपीट करने और धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
12. 4 अप्रैल 2016 को तहसील सदर के अमीन चंद्रमोहन मीना और मोतीकुंज निवासी अजय प्रताप मीणा ने रामवृक्ष यादव, चंदन बोस समेत 250 लोगों के खिलाफ बलवा करने, अपहरण करने, मारपीट करने, सरकारी कार्य में बाधा डालने और जानलेवा हमला करने की रिपोर्ट थाना सदर बाजार में दर्ज कराई थी.
13. 4 अप्रैल 2016 को अधिवक्ता राकेश कुमार ने रामवृक्ष यादव, चंदनबोस समेत 250 लोगों के खिलाफ बलवा करके तहसील परिसर में लूटपाट करने का मामला थाना सदर में दर्ज कराया था.
14. 4 अप्रैल 2016 को ही तहसील सदर में तैनात लेखपाल नितिन चतुर्वेदी ने तहसील परिसर में घुसकर बलवा करने, लूटपाट और धमकी देने के साथ-साथ सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा रामवृक्ष यादव, चंदनबोस समेत 200-250 लोगों के खिलाफ थाना सदर में दर्ज कराया था.

एक रुपये में 40 लीटर पेट्रोल और 60 लीटर डीजल की अहमक़ी मांग

आजाद भारत विधिक विचारक क्रांति सत्याग्रही एक रुपये में 40 लीटर पेट्रोल और 60 लीटर डीजल देने की मांग कर रहे थे. जवाहरबाग की सैकड़ों एकड़ भूमि पर कब्जा जमाए रामवृक्ष यादव और उसके गुर्गे खुद को नेताजी सुभाषचंद्र बोस का अनुयायी बता कर अहमक मांगें कर रहे थे. उनकी मांगों में भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का चुनाव रद्द करना भी शामिल था. उनकी मांग थी कि देश में चल रही मौजूदा मुद्रा की जगह आजाद हिंद फौज करेन्सी चले.

जांच और मुआवज़े पर बदलता रहा मुख्यमंत्री का निर्णय

मथुरा कांड के बाद शहीदों के आश्रितों को मुआवजा देने और मामले की जांच कराने के प्रसंग में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जल्दी-जल्दी बदलने वाला निर्णय भी चर्चा में रहा. पहले उन्होंने मथुरा कांड की डीजीपी से जांच कराने की बात कही, लेकिन फिर निर्णय बदला और जांच की जिम्मेदारी आगरा मंडल के कमिश्नर को दे दी. मामले की सीबीआई जांच कराने का दबाव बढ़ने पर फौरन न्यायिक जांच की घोषणा कर दी गई. ऐसा ही शहीदों के आश्रितों को मुआवजा देने में भी हुआ. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शहीद एसपी मुकुल द्विवेदी और सब इंसपेक्टर संतोष यादव के आश्रितों को 20-20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की. जब कुंडा के सीओ हत्याकांड में 50 लाख का मुआवजा और परिजनों को सरकारी नौकरी दिए जाने की याद दिलाई गई तो मुख्यमंत्री ने फिर अपना निर्णय बदला. अब उन्होंने शहीद पुलिस अधीक्षक और शहीद थानाध्यक्ष के आश्रितों की सहायता राशि 20 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने की घोषणा की. इसके बाद अखिलेश ने दोनों शहीद अधिकारियों के परिवार को असाधारण पेंशन प्रदान करने और शहीद अधिकारियों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की भी घोषणा की.

जवाहरबाग पर रामवृक्ष और उसके स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह संगठन के कब्जे के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले वकील विजयपाल तोमर कहते हैं कि जवाहरबाग को 99 साल के पट्टे पर देने की प्रदेश सरकार ने पूरी तैयारी कर ली थी. यदि वे समय रहते हाईकोर्ट नहीं जाते तो प्रदेश सरकार इस बेशकीमती सरकारी जमीन का पट्टा मात्र 1 रुपया सालाना प्रति एकड़ के हिसाब से संगठन के नाम कर चुकी होती. तोमर की याचिका पर हाईकोर्ट ने 20 मई 2015 को ही जवाहरबाग खाली कराने का आदेश दिया था, लेकिन प्रशासन के सीधे दबाव में प्रशासन कुछ नहीं कर पाया. 22 जनवरी 2016 को अदालत की अवमानना का मामला शुरू हुआ, फिर भी प्रशासन चार महीने तक पर्याप्त फोर्स की कमी का बहाना बना कर मामले को टालता रहा. गृह विभाग के ही एक आला अधिकारी ने कहा कि अदालत के समक्ष पर्याप्त फोर्स की कमी का जिक्र करना ही यह इंगित करता है कि प्रशासन को जवाहरबाग में जमा हो रहे असलहों और हिंसक तैयारियों की पूरी रिपोर्ट थी, इसके बावजूद पुलिस सत्ता सियासतदानों के कारण नपुंसक बनी रही और अपने दो काबिल अफसर गंवा दिए.

जवाहरबाग पर काबिज रामवृक्ष और उसके समर्थकों के लिए राशन-पानी और प्रशासनिक तीमारदारी की पूरी व्यवस्था कैसे और किसके इशारे पर हो रही थी? इस सवाल का आधिकारिक जवाब कुछ भी नहीं है और अनधिकृत जवाब सर्वज्ञात है. रामवृक्ष भी जवाहरबाग की 280 एकड़ जमीन पर कब्जा कर उसी तरह का आश्रम बनवाना चाहता था जैसा उसके गुरु जयगुरुदेव ने मथुरा के इंडस्ट्रियल एरिया और नेशनल हाईवे नंबर-2 के इर्द-गिर्द की सैकड़ों एकड़ जमीन पर कब्जा जमा कर बनवाई थी. जयगुरुदेव की पृष्ठभूमि भी कोई संतोचित नहीं रही है. इसका असर शिष्यों पर भी था. इटावा जिले में बकेवर थाने के खितौरा गांव निवासी तुलसी यादव उर्फ जयगुरुदेव के पिता का नाम रामसिंह था. जयगुरुदेव पर इटावा समेत लखनऊ में भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज रहे हैं और उनमें सजा भी हुई है. इटावा कोतवाली में दर्ज एक मुकदमे अपराध संख्या-(226) में जयगुरुदेव को छह महीने की जेल भी हो चुकी थी. लखनऊ में भी वजीरगंज थाने में दर्ज मुकदमे (अपराध संख्या-318) में उन्हें डेढ़ वर्ष के सश्रम कारावास की सजा हुई थी.

मनोवैज्ञानिक हताशा में चली गई है यूपी पुलिस

मथुरा कांड ने केवल मथुरा ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की पुलिस पर नकारात्मक मनोवैज्ञानिक असर डाला है. सियासत के कारण होने वाली दुर्गति और विद्रोह जैसी स्थिति का पैदा होना चिंताजनक है. मथुरा कांड में एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और सब इंसपेक्टर संतोष यादव के मारे जाने से पुलिस अधिकारी और कर्मचारी इतने दुखी हैं कि वे देश में ही दोबारा नहीं पैदा होने की प्रार्थनाएं कर रहे हैं. सत्ता सियासतदानों को इससे कोई मतलब नहीं. हम उन अधिकारियों का नाम नहीं छाप रहे, जिनलोगों ने एसपी मुकुल द्विवेदी की हत्या पर पत्र लिखे या सार्वजनिक तौर पर ऐसी निकृष्ट सियासत को धिक्कारा. उन अधिकारियों का नाम छप जाए तो सरकार उनपर कार्रवाई कर देगी. क्योंकि सरकार इतना ही कर सकती है. नेता खुद को सुधार नहीं सकते.

आहत पुलिस अधिकारियों ने जो लिखा है उसे पढ़ कर ही पुलिस संगठन के आक्रोश का अंदाजा लगाया जा सकता है. वे लिखते हैं, पुलिस की मौत पर जश्न मनाने वालों खुश रहो. मुकुल आज हमारे बीच नहीं हैं. पुलिस की नियति ही है अपने ही लोगों द्वारा मारा जाना. पुलिस की मौत पर जश्न मनाने वालों खुश रहो. हम यूं ही मुकुल बन कर मरते रहेंगे. मुकुल किसी आतंकवादी या डकैतों से लड़ता हुआ मारा जाता तो हमें गर्व और दुःख होता लेकिन आज शर्म और

(शेष पृष्ठ 3 पर)

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 08 अंक 16
20 जून- 26 जून 2016

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-42296060, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

समाजवादी पार्टी के दो नेताओं की वर्चस्वी-खींचतान में उत्तर प्रदेश की क़ानून-व्यवस्था ध्वस्त

कहां सरकार?

पृष्ठ 2 का शेष

दुःख है. विदा मुकुल, अब कभी मत मिलना. और आखिरी बात इस देश में फिर कभी पैदा मत होना...

जयगुरुदेव की सम्पत्ति भी तो लुभाती है

जयगुरुदेव भी कानून को अपने जेब में ही रखते थे और सियासतदानों को अपनी मुट्ठी में. बाबा जयगुरुदेव और उनकी धर्मप्रचारक संस्था से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव का नाम खास तौर पर जुड़ा रहा है. शिवपाल यादव समय-समय पर बाबा के पास आते भी रहते थे. बाबा के उत्तराधिकारी के तौर पर उनके ड्राइवर पंकज यादव को काबिज कराने में भी शिवपाल यादव की अहम भूमिका रही है. मथुरा कांड के पीछे सियासी प्रलोभन के साथ-साथ आर्थिक लोभ भी कम नहीं था. जयगुरुदेव की सम्पत्ति तकरीबन 20,000 करोड़ रुपये की बताई जा रही है. जयगुरुदेव के कई भव्य आश्रम मथुरा-दिल्ली हाईवे और इटावा में हैं. जयगुरुदेव के आर्थिक साम्राज्य में हजारों करोड़ रुपये की ज़मीन, सैकड़ों करोड़ की आलीशान गाड़ियां, मसलन मर्सिडीज़, रोल्स रॉयस, ऑडी और प्लाइमाउथ जैसी भव्य कारों का बेड़ा और सैकड़ों करोड़ के बैंक खाते हैं. जय गुरुदेव के आश्रमों में हर दिन करीब लाखों रुपये का चढ़ावा भी चढ़ता है. स्वाभाविक है, नेता इस प्रलोभन से वंचित कैसे रहे.

रामवृक्ष की समानान्तर सरकार

जवाहरबाग में रामवृक्ष यादव की समानान्तर सरकार चल रही थी. परिसर में घुसने की किसी को हिम्मत नहीं थी. दो साल तक कब्जे के दौरान परिसर में पक्के निर्माण तक कर लिए गए थे और जवाहरबाग को सुरक्षा दुर्ग बना लिया गया था. परिसर में अस्पताल था. बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल बना लिया गया था. परिसर की रखवाली के लिए बाकायदा निजी सेना नियुक्त थी. अपने समर्थकों को रामवृक्ष समझाता था कि शारीरिक आजादी तो मिल गई मगर आर्थिक आजादी मिलनी बाकी है. 14 मार्च 2014 से ही जवाहरबाग रामवृक्ष के कब्जे में था. परिसर में तीन हजार से अधिक लोग रहते थे. अस्पताल, स्कूल, बिजली बैक-अप और स्ट्रीट लाइटें सब लगी थीं. बाहर से ट्रकों पर अनाज और अन्य, सामग्रियों के आने का सिलसिला चलता रहता. जवाहरबाग परिसर के पास लग्जरी गाड़ियां खड़ी रहतीं. रामवृक्ष स्थानीय लोगों को भी लुभाने के हथकंडे अपना रहा था. सस्ती कीमत पर चीनी, सब्जियां और फल बेचे जा रहे थे. सब्जी और फल उद्यान में उपजाए हुए थे. जवाहरबाग पर कब्जा जमाए बैठे लोगों के सरगना रामवृक्ष यादव ने जिला उद्यान अधिकारी को खदेड़ कर उनके आवास पर कब्जा जमा लिया था और अपना बेडरूम आलीशान बनवा रखा था. इस आवास में रामवृक्ष के लिए स्विमिंग पूल का भी इंतजाम था. बेडरूम में एसी लगा था, डबल बेड पलंग पर महंगे गद्दे लगे थे. ड्रेसिंग टेबल पर ब्रांडेड तेल, महंगे डियोडॉरेंट और परफ्यूम रखे हुए थे. बेडरूम में कई तरह के आचार के डिब्बे भी पाए गए. रामवृक्ष यादव को धन कहां से मिल रहा था, यह रहस्य बना हुआ है. शासन इसे नक्सली संगठनों पर डाल कर नेताओं को बचाने की कोशिश में है. कहा जा रहा है कि ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के नक्सली संगठनों से उसे पैसा मिल रहा था. शासन जवाहरबाग के अंदर भंडार घर में भीगे मिले एक रजिस्टर का हवाला देता है, जिसमें आर्थिक मदद और खर्च का विवरण दर्ज है. बताया गया कि उसमें ओडिशा के रंगलाल राठौर नामक व्यक्ति से हर माह 22 लाख रुपये, बनारस के नारायण सिंह से 10 लाख रुपये, कन्नौज के मान सिंह से सात लाख रुपये और उन्नाव के एक व्यक्ति से आठ लाख रुपए से अधिक की राशि मिलने का विवरण दर्ज है. ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के उन इलाकों के दर्जनों लोगों के नाम और भंडारे के लिए उनसे मिली लाखों की राशि का ब्यौरा भी दर्ज है. रामवृक्ष यादव के पास महंगी पजेरो गाड़ी थी, इसके अलावा उसके आगे-पीछे पांच से सात गाड़ियों का काफिला चलता था, जिसमें हथियारबंद दस्ता सवार रहता था.

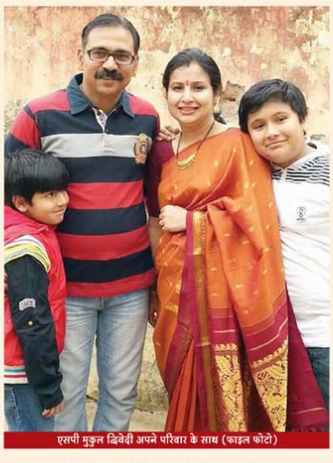
एसपी मुकुल द्विवेदी अपने परिवार के साथ (फाइल फोटो)

शहीद एसपी मुकुल द्विवेदी

शहीद एसआई संतोष यादव

विवशता स्वीकार करती डीजीपी की रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक जावीद अहमद ने सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी वह भी गौर करने लायक है. पुलिस प्रमुख की आधिकारिक रिपोर्ट में स्वीकार किया गया है कि रामवृक्ष और उसके गुर्गे 2014 से ही जवाहरबाग पर कब्जा जमाए बैठे थे. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2015 में ही जवाहरबाग परिसर खाली कराने का आदेश दे रखा था. डीजीपी ने घटना में 22 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की, लेकिन लिखा कि एक भी आदमी पुलिस की गोली से नहीं मरा. जबकि उधर से हमलावरों की गोली से सिटी एसपी और थाना प्रभारी मारे गए. आप भी रिपोर्ट देखें...

1. वर्ष 2014 से रामवृक्ष यादव के नेतृत्व में करीब ढाई-तीन हजार पुरुष महिलाएं एवं बच्चे स्वाधीन भारत विधिक सत्याग्रह के बैनर तले जवाहरबाग में काबिज थे.
2. अनधिकृत कब्जा करने वालों ने उद्यान विभाग के कार्यालयों तथा आवासीय भवनों में कब्जा कर एवं झोपड़ी और टेंट लगाकर अपने आवास बना लिए थे तथा जवाहरबाग की सम्पत्ति को काफी नुकसान पहुंचा रहे थे.
3. वकील विजयपाल सिंह तोमर द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय जनहित याचिका (28807/2015) दाखिल की गई थी, जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 20-05-2015 को इन अवैध कब्जाधारियों से जवाहरबाग को खाली कराने हेतु आदेश जारी किया गया था.
4. दिनांक 02-06-2016 को करीब पांच बजे शाम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कई थानों की पुलिस पीएसी आदि के साथ कार्रवाई के लिए जवाहरबाग के पास एकत्रित हुई थी.
5. उपद्रवियों ने सैकड़ों महिलाओं को लाठी-डंडे के साथ आगे कर दिया तथा पुरुष उपद्रवी नाजायज असलहों के साथ पीछे मोर्चा संभाले रहे.
6. रामवृक्ष यादव व चन्दन बोस, रिंकू, अमित, रामपाल, धीरज सिंह, वीरेश यादव, राकेश गुप्ता, लक्ष्मन पासी, सुन्दरलाल, मुन्नी लाल आदि ढाई-तीन हजार पुरुष एवं महिलाओं ने उत्तेजित होकर पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से ईंट-पत्थर व हथगोले फेंकने शुरू कर दिये व नाजायज असलहों से फायरिंग कर दी.
7. फराह थाने के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव गोली लगने से गम्भीर रूप से घायल हो गए तथा पुलिस अधीक्षक नगर मुकुल द्विवेदी, नगर मजिस्ट्रेट राम अरज यादव व कांस्टेबल भूपेन्द्र, कांस्टेबल पवन कुमार, कांस्टेबल राधाशंकर, कांस्टेबल वीरविक्रम, कांस्टेबल श्रीनिवास, कांस्टेबल बृजेश, कांस्टेबल राजकुमार यादव, कांस्टेबल असेन्द्र कुमार, कांस्टेबल हरीश कुमार पांडेय, कांस्टेबल संजीव कुमार, कांस्टेबल तेजेन्द्र कुमार सिंह, कांस्टेबल विद्याकांत, मुख्य आरक्षी श्रीनिवास, उप निरीक्षक प्रबल प्रताप, उप निरीक्षक विपिन कुमार व अन्य पुलिस कर्मी गम्भीर रूप से घायल हो गए.
8. नगर मजिस्ट्रेट रामअरज यादव एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा चेतावनी दी गई लेकिन उनके द्वारा चेतावनी का कोई असर न होने पर फायर ब्रिगेड द्वारा मौसम के अनुकूल पानी की बौछार कराई गई. लेकिन उनके द्वारा लगातार पथराव व फायरिंग करने पर नगर मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए आत्मरक्षार्थ, अश्रुगैस, रबर बुलेट, एन्टी राइट गन का प्रयोग करते हुए इन लोगों को शांत कराने का प्रयास किया गया लेकिन ये लोग और अधिक उत्तेजित होकर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे. पुलिस बल द्वारा पम्प ऐक्शन गन एवं सरकारी असलहों से हवाई फायरिंग कर उपद्रवियों को तितर-बितर करने का प्रयास किया गया.
9. सूचना पर जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मौके पर अतिरिक्त पुलिस के साथ पहुंचे और उपद्रवियों को दोबारा चेतावनी दी गई. उपद्रवियों के नेताओं ने अपने लोगों को ललकार कर कहा कि झोपड़ियों में आग लगाकर पीछे मोर्चा ले लो. झोपड़ियों में आग लगाते ही विस्फोट होने लगे जिसमें उनके कुछ व्यक्ति झुलस गए.
10. इस घटना के संबंध में थाना सदर बाजार पर मुकदमा अपराध संख्या- 242/16 धारा 147, 148, 149, 307, 302, 332, 333, 353, 186, 188 भादवि और 7 सीएलए एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया.
11. घटना में 22 उपद्रवियों की मृत्यु हुई जिसमें 11 लोग आग में झुलसने एवं 11 लोगों की लाठी डंडों की चोटों से मृत्यु हुई है. मृतकों में एक महिला है.
12. मुकुल द्विवेदी अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं संतोष कुमार यादव थानाध्यक्ष फराह शहीद हुए.
13. 23 पुलिस कर्मियों को फायर आर्म्स एवं लाठी डंडों की चोटें आई हैं. 56 उपद्रवी घायल हुए हैं.
14. अब तक कुल 368 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं जिसमें 58 अभियुक्त अभियोग से सम्बन्धित हैं तथा 310 व्यक्ति शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं. ऑपरेशन के दौरान 45 तमंचे 315 बोर, 02 तमंचे 12 बोर, 01 रायफल 315 बोर, 01 रायफल 12 बोर, 04 रायफल 315 बोर, 80 जीवित एवं खोखा कारतूस 12 बोर, 99 जीवित एवं खोखा कारतूस 315 बोर एवं 05 खोखा कारतूस 32 बोर बरामद हुए हैं.

जारी हैं पुलिस पर हमलों और शहादतों का सिलसिला

मथुरा कांड में एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी और सब इंस्पेक्टर संतोष यादव की निर्मम हत्या उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की लगातार हो रही शहादतों का सिलसिला है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा. सरकार पर सियासत इतनी हावी है कि वह पुलिसकर्मियों की बेतहाशा कुर्बानियां ले रही है.

शहादतों का आंकड़ा इतना भयावह है कि किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं. इतने पुलिसकर्मी आतंकवाद प्रभावित राज्यों में भी नहीं मरते जितने यूपी में मर रहे हैं. प्रदेश में हर साल सौ से डेढ़ सौ पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान जान गंवा रहे हैं. इनमें अधिकारी से लेकर सिपाही तक शामिल हैं. सरकारी आंकड़ों के अनुसार एक सितम्बर 2012 से 31 अगस्त 2013 के दौरान कुल 117 पुलिसकर्मियों ने शहादतें दीं. 2013-2014 में 126 और 2014-2015 में 108 पुलिसकर्मियों की शहादत हुई. एक सितम्बर 2015 से अब तक सौ से अधिक पुलिसकर्मियों की जान जा चुकी है.

एक सितम्बर 2012 से 31 अगस्त 2013 के दौरान जो 117 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, उनमें एक अपर पुलिस अधीक्षक, दो डीएसपी, 11 सब इंस्पेक्टर, चार एएसआई, एक एसआईएम, तीन एएसआई एम, 13 हेड कांस्टेबल, 79 सिपाही, एक लीडिंग फायरमैन, एक महिला कांस्टेबल और एक हेड ऑपरेटर शामिल थे. एक सितम्बर 2013 से 31 अगस्त 2014 के दौरान हुई 126 शहादतों में तीन इंस्पेक्टर, एक कंपनी कमांडर, दो एसआई (एम लिपिक), एक एसआईएम, सात सब इंस्पेक्टर, एक एसआई रेडियो, तीन एएसआईएम, चार एएसआई, 13 हेड कांस्टेबल, 85 सिपाही, चार सिपाही चालक, एक फायरमैन और एक महिला सिपाही की मौत शामिल है. एक सितम्बर 2014 से 31 अगस्त 2015 तक हुई 108 शहादतों में एक डीएसपी, एक इंस्पेक्टर, चार एसआई, चार एसआईएम, एक एसआईएम (लिपिक), 26 हेड कांस्टेबल, 67 सिपाही, एक लीडिंग फायरमैन और एक फायरमैन की मौत शामिल है.

पुलिस पर हमलों का आंकड़ा भी उतना ही भयावह है. विधानसभा में सरकार द्वारा रखे गए आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2010-2011 के दौरान पुलिस पर हमलों की कुल 124 घटनाएं दर्ज हुईं. 2011-2012 के दौरान पुलिस पर हमलों की 144 घटनाएं हुईं. 2012-2013 के दौरान पुलिस पर हमलों की कुल 202 घटनाएं दर्ज हुईं. 2013-2014 के दौरान पुलिस पर हमले की कुल 265 घटनाएं घटीं. 2014-2015 के दौरान पुलिस पर हमले की कुल 300 घटनाएं घटीं और वर्ष 2015 से अब तक पुलिस पर हमले की कुल 278 घटनाएं घट चुकी हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

बिहार

मुसहरों को सता रहा बिल्डरों का ख़ौफ़

अफ़रोज़ आलम साहिल

बिहार की राजधानी पटना में मुसहर जाति के लोग इन दिनों संकट में हैं. मुसहरों की जमीन पर एक बिल्डर की नज़र है. रोज़ी-रोटी को तरसते ये लोग पीढ़ियों से इस ज़मीन पर रह रहे हैं. उनके पास जमीन के जरूरी कागजात हैं और रिहाइश के पक्के सबूत भी. उनका कहना है कि शहर का एक बड़ा बिल्डर रामप्रसाद यादव फर्जी दस्तावेज़ों के सहारे उन्हें उनकी जमीन से बेदख़ल करने पर तुला है.

यह मामला पटना के प्रसिद्ध बेली रोड स्थित जगदेव पथ के निकट बसे मुसहर टोला का है. स्थानीय लोगों का कहना है कि प्राइम लोकेशन पर होने के कारण बिल्डरों की नज़र हमेशा इस बस्ती पर रही है. स्थानीय लोगों ने बताया कि ज़मीन के इस खेल में दो साल में मुसहर जाति के 6 लोगों की जान जा चुकी है. उनकी मौतों का सिलसिला भी बेहद ख़ौफ़नाक है. किसी को दिनदहाड़े गोली मार दी गई तो किसी को रात के साए में ट्रैक्टर के नीचे कुचल दिया गया.

स्थानीय निवासी पप्पू कुमार (उम्र 38 साल) बताते हैं, मेरे दादा-परदादा यहीं रहते आए हैं. 1989 में इंदिरा आवास योजना के तहत यहां 100 घर बनाए गए थे. हमारे पास ज़मीन के सारे कागज़ात मौजूद हैं. इसके बावजूद बिल्डर हमें लगातार परेशान करते रहे हैं. उनकी नजर हमारे ज़मीन पर हमेशा रही है.'

वे बताते हैं कि जमीन के इस खेल में पुलिस-प्रशासन भी बिल्डरों का खुलकर साथ देता है. प्रशासन ने कहा था कि उन्हें इस ज़मीन के बदले पास के क़ब्रिस्तान में ज़मीन दी जाएगी, लेकिन वह ज़मीन भी अब बिल्डरों के क़ब्ज़े में है. क़ब्रिस्तान की इस ज़मीन को लेकर जून, 2014 में मुसहर समाज के लोगों ने विरोध-प्रदर्शन भी किया था. उनका आरोप है कि तब बिल्डरों ने भुट्टी देवी को सबके सामने गोली मार दी थी. जब यह संवाददाता सिद्धार्थ नगर स्थित क़ब्रिस्तान को देखने पहुंचा, तो वहां क़ब्रिस्तान के नाम पर कुछ भी नहीं था. कंपाउंड के अंदर कुछ काम चल रहा था. स्थानीय लोगों ने इस बारे में कुछ भी बताने से साफ़ इंकार कर दिया. इतना ही नहीं, वहां मौजूद एक-दो लोगों ने फोटो लेने पर भी रोक लगा दी. मुसहर टोला के एक स्थानीय निवासी ने बताया कि वे सभी बिल्डर के आदमी थे.

लोगों ने बताया कि कभी यहां क़ब्रिस्तान हुआ करता था. इस संबंध में पूछताछ करने और शिकायत दर्ज कराने हम शास्त्रीनगर थाने गए, लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने थानाध्यक्ष के छुट्टी पर जाने की बात बताई. पुलिसकर्मियों ने इस क़ब्रिस्तान के संबंध में पूछे जाने पर अपनी अनभिज्ञता जताई. थानाध्यक्ष ने फोन पर बताया कि यह मामला दूसरे थानाक्षेत्र के अंतर्गत आता है.

यहां रहने वाली 32 साल की मालती देवी बताती हैं, प्रशासन भी बिल्डरों के साथ मिला है. उन्हें यहां से ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है. बिल्डरों की बात तो दूर, खुद प्रशासन भी लोगों को बरगला कर निकालने में लगा है. हमसे कहा गया कि आप लोगों को क़ब्रिस्तान की ज़मीन पर बसाया जाएगा, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो बिल्डरों ने पहले से ही उस ज़मीन को भी अपने क़ब्ज़े में ले रखा था.' दौलत देवी अपने घर के कागज़ात दिखाते हुए कहती हैं, हमारे पास जमीन के तमाम कागज़ात हैं. इसके बावजूद हमें लगातार धमकी दी जा रही है. हमारे 6 लोगों को मार दिया गया. हमें बार-बार मारने की धमकी दी जा रही है. हमारे यहां के मर्दों को पुलिस अकारण जेल में डाल देती है, ताकि हम औरतों को निकालने में आसानी हो.'

राजू (34 साल) बताते हैं, इस संबंध में हम लोगों ने कई जगहों पर शिकायत की है. हमारी बिरादरी के जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री थे, तब हम लोगों ने जाकर उनसे मुलाक़ात की, लेकिन उनका आश्वासन भी झूठा निकला.' बिहार महादलित आयोग के चेयरमैन डॉ. हुलेश मांझी बताते हैं, मुझे भी इस संबंध में वहां के स्थानीय लोगों ने शिकायतपत्र दिया था. शिकायत मिलते ही मैंने उस इलाक़े का दौरा किया. वहां के डीएम व संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए, लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई है.'

वे बताते हैं, इस बस्ती में क़रीब 100 घर हैं, जिनमें 150 परिवार बसते हैं. लालू राज में उन्हें जमीन का पर्चा दिया गया था. सरकारी योजना के तहत उनके आवास बने हैं. लेकिन प्राइम लोकेशन पर होने के कारण बिल्डर उन्हें यहां से किसी भी हालत में निकालना चाहते हैं.' हुलेश मांझी को भी जानकारी है कि इस मामले में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है. कई लोगों के हाथ-पैर तोड़ डाले गए हैं. वे आश्वासन देते हैं,' मैं इस संबंध में जल्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाक़ात करूंगा, ताकि इस संबंध में उचित कार्रवाई की जा सके.' वहीं इस इलाक़े में काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता सविता अली बताती हैं, यह सब प्रशासनिक मिलीभगत से हो रहा है. पटना के एक पॉश इलाक़े के बग़ल में होने के बावजूद यह बस्ती बुनियादी सुविधाओं से महरूम है. चारों तरफ बिखरी गंदगी से यहां बीमारियां फैल रही हैं और लोग मर रहे हैं. अब तक एक दर्जन से अधिक बच्चे अनाथ हो गए हैं.'

सविता पूछती हैं कि विकास का दावा करने वाली सरकार क्या दलित बस्ती होने के कारण इस इलाक़े की अनदेखी कर रही है? दहशत और डर के साए में जी रहे ये ग़रीब लोग अधिकारी से लेकर नेताओं तक हर किसी का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, लेकिन आलम ये है कि हर बार मध्यवस्था का चाबुक' उनकी पीठ पर ही पड़ता है. हाल में पांच अप्रैल को इस बस्ती के कुछ लोग सड़क किनारे सो रहे थे, तभी रात के क़रीब 2 बजे बालू से लदे एक ट्रैक्टर ने चार लोगों को कुचल दिया. इस घटना में कारू मांझी, कनौली मांझी और जीतू मांझी की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं फेकन मांझी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है. इस घटना को जहां प्रशासन एक सड़क दुर्घटना मान रहा है, वहीं स्थानीय लोग इसे बिल्डर वाले मामले से जोड़कर देख रहे हैं. उनका कहना है कि घटना के दो दिन पहले बिल्डर ने उन्हें मारने की धमकी दी थी.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन्हीं दलितों का वोट लेकर गद्दी पर आसीन हैं और उन्हीं के राज में मुसहर जाति के लोग अब लाचार नजर आ रहे हैं. इन लोगों पर बिल्डर के आतंक का साया गहराता जा रहा है. अपनी ज़मीन छिन जाने के बाद ये क्या करेंगे? ये सवाल उनकी आंखों में ख़ौफ़ बनकर तैर रहा है. परेशानी ये है कि न तो इस मर्ज का कोई इलाज उन्हें नजर आता है और न ही पुलिस-प्रशासन और सरकार से उन्हें मदद की कोई उम्मीद है.■

feedback@chauthiduniya.com

छोटे मोदी का इम्तिहान बाक़ी है

सरोज सिंह

राज्यसभा चुनाव में सुशील कुमार मोदी की जगह गोपाल नारायण सिंह का नाम सामने आते ही मोदी विरोधियों की बाछें खिल गईं. राजनीतिक विश्लेषकों ने कहना शुरू कर दिया कि बिहार में अब मोदी युग का अंत हो गया. वहीं सत्ता के गलियारों में चर्चा होने लगी कि आलाकमान ने बिहार विधानसभा चुनाव हारने की सजा सुशील मोदी को दी है. भाजपा सांसद भोला प्रसाद ने तो यहां तक कह दिया कि जैसे मुलायम सिंह के लिए अमर सिंह हैं, वैसे ही नीतीश कुमार के लिए सुशील मोदी हैं. हद तो तब हो गई जब जदयू के प्रवक्ताओं ने भी सुशील मोदी के लिए सहानुभूति भरे बयान जारी करने शुरू कर दिए. लेकिन क्या सही में सुशील मोदी का कद भाजपा और बिहार में घटा है. आज की तारीख में यह ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढने के लिए भाजपा और सुशील मोदी दोनों की कार्यशैली और राजनीति को समझना जरूरी है. बिहार और भाजपा की राजनीति की समझ रखने वाले कुछ राजनीतिक पंडितों का मानना है कि दरअसल राज्यसभा और विधान परिषद के लिए हुए चुनावों में सुशील मोदी भले कमजोर दिख रहे हों, लेकिन सच्चाई यह है कि सुशील मोदी का कद बढ़ा है, घटा नहीं है. सुशील मोदी के विरोधियों का कहना है कि मोदी दिल से चाहते थे कि वे राज्यसभा के मार्फत दिल्ली की नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री बन जाएं. ऐसा इसलिए भी कि मोदी सोच रहे थे, सामान्य हालात में फिलहाल पांच साल तक तो बिहार में सत्ता बदलनी नहीं है. जहां तक लोकसभा की बात है तो पिछली बार भी उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था. विरोधी अनुमान लगाते हैं कि शायद सुशील मोदी ऐसा चाहते थे कि दो तीन साल तक केंद्र में मंत्री रहते अपनी पैठ दिल्ली की राजनीति में भी मजबूत कर ली जाए, ताकि अगले विधानसभा चुनाव में कोई परेशानी न हो. प्रदेश की राजनीति में अब पहले वाली बात नहीं रही. नेता विपक्ष प्रेम कुमार अब हर घटना पर बयान देते हैं और घटनास्थल पर भी जाते हैं. यही काम फिर सुशील मोदी करते हैं. ऐसी स्थिति से बचने के लिए ही सुशील मोदी की दिली इच्छा दिल्ली जाने की थी, लेकिन कई कारणों से वे पटना में ही रह गए. जानकार सूत्र बताते हैं कि दिल्ली में बैठे आलाकमान को बताया गया कि विधान परिषद में अभी मोदी के दो साल बचे हैं इसलिए उनको मौका देना ठीक नहीं होगा. मौका दिया गया तो फिर खाली सीट पर प्रत्याशी देना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि सुशील मोदी इसके लिए हर हाल में अपने समर्थक का नाम आगे करेंगे. दूसरा तर्क यह दिया गया कि विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के लिए ज्यादातर कार्यकर्ता सुशील मोदी को जिम्मेदार ठहराते हैं इसलिए अगर उन्हें राज्यसभा का लॉलीपॉप दिया गया तो कार्यकर्ताओं के बीच सही संदेश नहीं जाएगा. दूसरी तरफ गोपाल नारायण सिंह ने अपनी दिल्ली की किलाबंदी बेहद मजबूत कर ली थी. चुनाव हारने के बाद वे अपने इसी एजेंडे पर काम कर रहे थे. जानकार बताते हैं कि सिंह ने भाजपा के राज्यसभा सांसद आरके सिन्हा के रास्ते को अपनाया और कामयाबी हासिल कर ली. उन्होंने चाक-चौबंद रणनीति से अपने पुराने विरोधी सुशील कुमार मोदी को चारों खाने चित्त कर दिया. भाजपा के सूत्र बताते हैं कि शिकस्त खाने के बाद सुशील मोदी के समर्थक यह अफवाह फैला रहे हैं कि वे कभी इस रेस में थे ही नहीं. लेकिन अगर रेस में नहीं थे या फिर दिल्ली जाने की इच्छा नहीं थी तो मोदी का नाम राज्यसभा के संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट में कैसे आ गया. उन्होंने उस सूची का कभी खंडन क्यों नहीं किया. हकीकत यह है कि सुशील मोदी की इस चुनाव में नहीं चली और वे गोपाल नारायण सिंह से पिछड़ गए. लेकिन इन बातों से अलग सुशील मोदी के समर्थक कुछ और तर्क देते हैं. भाजपा में सुशील मोदी समर्थकों का कहना है कि दरअसल दिल्ली जाने जैसी कोई बात थी ही नहीं. मोदी के एक समर्थक नेता ने ही उनका नाम प्रस्तावित कर दिया था. सुशील मोदी को जानने वाले यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि वे कोई हल्की बात न कहते हैं और न करते हैं. सूत्र बताते हैं कि सुशील मोदी पटना में ही रहकर अपनी पकड़ पहले से ज्यादा मजबूत बनाने में लगे हैं. जदयू और राजद के बीच कभी-कभी होने वाली तनातनी से वे काफी उत्साहित हैं. उन्हें लगता है कि बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं. मोदी समर्थक बताते हैं कि परिषद की दोनों सीटों पर अपने लोगों को भेजने में सुशील मोदी सफल रहे हैं. जानकार बताते हैं कि राज्यसभा और परिषद से कहीं अधिक ध्यान वे प्रदेश अध्यक्ष के मामले में दे रहे हैं. वे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मंगल पांडेय को ही दूसरा मौका दे दिया जाए. तर्क यह है कि यूपी चुनाव को देखते हुए मंगल पांडेय को हटाना ठीक नहीं होगा. इससे ब्राह्मण वोटरों में ठीक संदेश नहीं जाएगा. वहीं, विरोधी कहते हैं कि मंगल पांडेय के अध्यक्ष रहते भाजपा की बिहार में बुरी हालत हुई इसलिए उन्हें हटाना जरूरी है. एक हारा हुआ सेनापति अपनी सेना का नेतृत्व कैसे कर सकता है. गौरतलब है कि बिहार में विधानसभा और विधान परिषद में नेता विपक्ष की कमान पिछड़े और अतिपिछड़े के पास होने के कारण प्रदेश की कमान किसी सवर्ण को देने की कवायद जारी है. सुशील मोदी खेमा चाहता है कि अगर मंगल पांडेय पर बात नहीं बनी तो फिर सुधीर शर्मा विनोद नारायण या फिर राजनीति सिंह के हाथों में कमान सौंप दी जाए. ये तीनों सुशील मोदी के खासमखास माने जाते हैं, लेकिन उनका विरोधी खेमा चाहता है कि हर हाल में यह कोशिश हो कि सुशील मोदी के किसी चहेते को पार्टी की कमान नहीं मिले. इसमें जनार्दन सिंह सीग्रीवाल और सीपी ठाकुर का नाम सबसे आगे है. ये दोनों नेता खुद अपनी दावेदारी मजबूती से जता रहे हैं. चर्चा गिरिराज सिंह और राधामोहन सिंह की भी है पर जोर नहीं पकड़ रही है. कहा जा रहा है कि मानसून सत्र के बाद बिहार के प्रदेश अध्यक्ष के बारे में फैसला ले लिया जाएगा. यही वजह है कि सभी दावेदार दिल्ली में डेरा जमा अपनी अपनी दावेदारी मजबूत करने में लगे हैं. राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि सुशील मोदी की ताकत का असली आकलन अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव में होगा. अगर सुशील मोदी अपने किसी समर्थक को प्रदेश की कमान दिलाने में सफल रहे तो यह मान लिया जाएगा कि बिहार भाजपा में उनका जादू बरकरार है. लेकिन अगर किसी कारण से ऐसा नहीं हो पाया तो मौटे तौर पर यह राय बनाने में आसानी होगी कि बिहार भाजपा में सुशील मोदी का कद घट रहा है.■

feedback@chauthiduniya.com

खनन के लिए ख़त्म होगी ग्राम सभा की सहमति!

शशि शेखर

दी पीपुल ऑफ इंडिया के मूल में पीपुल यानी जनता है. देश, व्यवस्था, संविधान सब कुछ जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाई गई है. भारतीय लोकतंत्र का मूल भी यही है. ऐसे में, जब संविधान सम्मत संस्था ग्राम सभा की बात की जाती है तो इसकी स्थिति किसी भी सूरत में लोकसभा या विधानसभा से ऊपर है. इसलिए, क्योंकि यह कभी भंग न होने वाली संस्था है, जिसके सदस्यों का चुनाव नहीं होता बल्कि एक खास गांव के सभी मतदाता अपने-आप इसके सदस्य होते हैं. स्वशासन का इससे बेहतरीन उदाहरण कोई दूसरा नहीं हो सकता. संविधान से ग्राम सभा को अधिकार भी मिले हुए हैं. यह अधिकार कितने महत्वपूर्ण हैं, इसका अंदाजा नियामगिरी मामले में पूरे देश को हो चुका है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक ने नियामगिरी में वेदांता द्वारा खनन मामले में यह व्यवस्था दी कि संबंधित ग्राम सभा यह तय करें कि खनन हो या न हो. इसके बाद 12 ग्राम सभाओं ने जो फैसला दिया, वह पूरे देश के लिए नजीर बन गया. जाहिर है, कॉरपोरेट ताकतों और सरकार को भी यह एहसास हुआ कि ग्राम सभाएं उनके फैसलों के रास्ते में एक बड़ी रुकावट बन सकती हैं, इसलिए अब ऐसी चर्चा जारी है कि खनन के लिए क्यों नहीं ग्राम सभा की सहमति को ही समाप्त कर दिया जाए या फिर इसमें और अधिक ढील दे दी जाए. कुल मिला कर ऐसी आशंका जताई जा रही है कि आने वाले समय में खनन के लिए ग्राम सभा की सहमति को खत्म किया जा सकता है या इस प्रावधान को कमजोर किया जा सकता है.

पिछले दिनों एनडीए सरकार के दो मंत्रालयों के बीच आधिकारिक पत्रों का आदान-प्रदान हुआ. पत्रों का यह आदान-प्रदान जनजातीय मामलों के मंत्रालय और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच हुआ. इन पत्रों से जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)अधिनियम, 2006 (एफआरए) के प्रावधानों से पीछा छुड़ाने का मन बना लिया है, ताकि वन क्षेत्रों में निजी भूमिगत खनन की अनुमति दी जा सके. इन पत्रों का आदान-प्रदान जून 2015 और दिसंबर 2015 के बीच किया गया. ये पत्र वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में दोनों मंत्रालयों के बीच की रस्साकशी को जाहिर करते हैं. जबकि जन जातीय मामलों के मंत्रालय ने बार-बार अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा है कि वनभूमि को औद्योगिक परियोजनाओं को आवंटित करने से पहले एफआरए के प्रावधानों के मुताबिक ग्राम सभा की सहमती लेनी आवश्यक है. वहीं ऐसा लगता है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, सहमति के इस क्लॉज़ को हटाए जाने पर अड़ा हुआ है.

ये पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के इस विचार की तरफ भी इशारा करते हैं कि एफआरए विकास परियोजनाओं में बाधक का काम कर रहा है. दोनों मंत्रालयों के बीच बहस की शुरुआत अप्रैल 2015 में शुरू हुई जब पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पीएमओ और कैबिनेट सचिवालय के निर्देशों के तहत एफआरए से सहमति के क्लॉज़ समाप्त करने का एकतरफा मसौदा तैयार किया. उसके बाद जन जातीय मामलों का मंत्रालय जो एफआरए को लागू करने का नोडल मंत्रालय है, ने इस ड्राफ्ट आदेश के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की है और इस मसौदे को अवैध करार देते हुए इसे न्यायपालिका और विधायिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप की संज्ञा दी.

उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने जन जातीय मामलों का मंत्रालय और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच चल रहे विवाद में हस्तक्षेप किया और मसौदे की समीक्षा के लिए कानून मंत्रालय की सलाह मांगी. बहरहाल, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून से अगस्त महीने के दौरान कई बार कानून मंत्रालय से अपना रुख स्पष्ट करने का अनुरोध किया, लेकिन इसके बावजूद कानून मंत्रालय ने अपना रुख साफ नहीं किया. अख़बारों में छपी रिपोर्टों के मुताबिक 18 नवंबर 2015 को पर्यावरण मंत्रालय ने दोनों मंत्रालयों के सचिवों की बैठक बुलाई ताकि एफआरए के तहत खनन के लिए वनभूमि के इस्तेमाल के लिए पूर्व सहमति लेने की जरूरत न हो. हालांकि, इन मीटिंग्स के मिनट्स जिसे जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने तैयार किया है और जिस पर जनजातीय मामलों के मंत्रालय के उपसचिव रुपक चौधरी के हस्ताक्षर हैं. उसके मुताबिक, ग्राम सभा की सहमति को समाप्त करने को लेकर मंत्रालय ने आपत्ति दर्ज कराई है. यानी, जनजातीय मंत्रालय ग्राम सभा की सहमति को हटाने के पक्ष में नहीं है. हालांकि, अभी इस मामले पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है. सरकार इससे इंकार भी कर रही है. लेकिन, विभिन्न राज्य सरकारों के द्वारा पिछले कुछ समय में जिस तरह से ग्राम सभा की अनदेखी करने की कोशिशें हुई हैं, केंद्र सरकार भी खुद जिस प्रकार से यह मान रही है कि विकास की राह में कई क़ानून बाधा बने हुए हैं, तो इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में ग्राम सभा, वन अधिकार कानून, पर्यावरणीय मंजूरी से संबंधित क़ानूनों, खनन से जुड़े क़ानूनों को बदला जाए या कमजोर करने की कोशिश की जाए.

सबसे पहले दो-तीन घटनाओं पर गौर करना चाहिए, जिसकी वजह से सरकारों को लगता है कि ग्राम सभाएं क्यों उनके कथित विकास योजनाओं की राह में बाधा बन रही हैं. हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने सरगुजा जिले के घटबर्रा गांव में आदिवासियों के उनके पारंपरिक भूमि पर वन अधिकार को खत्म कर दिया है. यहां परसा इस्ट और कैंटे बेसन कोयला ब्लॉक राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड और अदानी खनिज प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित किए गए हैं. 8 जनवरी 2016 को पारित एक आदेश में सरकार ने वन अधिकार अधिनियम के तहत दिए गए गांव में आदिवासियों के समुदाय भूमि अधिकार रद्द कर दिए. सरकार के आदेश में कहा गया है कि ग्रामीण वन अधिकार क़ानून का उपयोग कर गांव पास के कोल ब्लॉक खनन नहीं होने दे रहे थे. जाहिर है, वन अधिकार क़ानून के तहत आदिवासियों को जो अधिकार प्राप्त हैं. यह उसका सीधा-सीधा उल्लंघन है. आदिवासियों की वनभूमि को ग्राम सभा के आदेश या फैसले से ही किसी और उपयोग में लाया जा सकता है.

दूसरी खबर यह है कि ओडिशा सरकार ने बाक्साइट खनन के लिए वेदांता की तरफदारी करते हुए सर्वोच्च न्यायलय के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसके तहत पारंपरिक वन्य भूमि पर खनन हो या नहीं, इस निर्णय का संवैधानिक अधिकार उस क्षेत्र के आदिवासियों को दिया गया था. सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ओडिशा सरकार ने कहा कि यदि सरकार को लगता है कि जनता के अधिकारों के साथ न्याय किया गया है तो खनन के लिए ग्राम सभाओं की अनुमति की आवश्यकता नहीं है. ओडिशा सरकार ने यह भी तर्क दिया है कि लांजीगढ़ बॉक्साइट खनन को अस्वीकृति देने वाली ग्राम सभा के प्रस्ताव सदैव लागू नहीं रह सकते हैं. गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 2013 के फैसले में यह आदेश दिया था कि डोंगरिया कोंध, कुटिया कंधा और अन्य आदिवासी समुदाय की 12 ग्राम सभाएं यह तय करेंगी कि ओडिशा के नियामगिरी पर्वतों पर उनके धार्मिक तथा अन्य अधिकार हैं कि नहीं. नियामगिरी पर्वत की चोटी के नीचे लांजीगढ़ में बॉक्साइट के खनन से उनके धार्मिक अधिकार प्रभावित तो नहीं होते हैं. 12 की 12 ग्राम सभाओं ने वेदांता के खनन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था.

छत्तीसगढ़ के सरगुजा के हसदेव अरण्य क्षेत्र की करीब 20 ग्राम सभाओं ने एक प्रस्ताव पारित कर यह साफ कर दिया था कि वे अपने क्षेत्र में होने वाले को ब्लॉक आवंटन और कोयला खनन का विरोध करेंगी. गौरतलब है कि पिछली बार जब कोयला ब्लॉक आवंटन हुआ था तब 218 कोल ब्लॉक में 30 फीसदी सिर्फ छत्तीसगढ़ में आवंटित हुए थे. छत्तीसगढ़ के सरगुजा और कोरबा में फैले हसदेव अरण्य में करीब 30 कोल ब्लॉक हैं. इनमें तीन कोल ब्लॉक ऐसे थे, जहां अदानी की कंपनी ज्वाइंट वेंचर के तहत खनन का काम कर रही थी. नई प्रक्रिया के तहत फिर से कोल ब्लॉक आवंटन का काम हुआ, लेकिन, हसदेव अरण्य क्षेत्र के गांव वालों ने पहले से ही अपना विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया था. इस क्षेत्र में आने वाली करीब 20 ग्राम पंचायतों ने ग्राम सभा की बैठक कर एक प्रस्ताव पारित किया. इस प्रस्ताव में गांव वालों ने स्पष्ट रूप से इस क्षेत्र में खनन कार्य का विरोध किया. यहां के निवासियों का कहना है कि चूंकि हमारे क्षेत्र में पेसा एक्ट(पंचायत एक्सटेंशन टू शिड्यूल एरिया एक्ट. यह आदिवासी इलाकों को विशेषाधिकार देता है) लागू है, इसलिए किसी भी कोल ब्लॉक के लिए जमीन अधिग्रहण करने से पहले सरकार के लिए यहां की ग्राम सभाओं की अनुमति लेना आवश्यक है. हसदेव अरण्य क्षेत्र में भी पेसा कानून लागू है. ग्राम सभा के इस प्रस्ताव के मुताबिक़ कोल ब्लॉक के आवंटन से पर्यावरण प्रभावित होगा, आदिवासी विस्थापित होंगे. यह प्रस्ताव कहता है कि किसी भी खनन परियोजना के आवंटन या नीलामी से पहले ग्राम सभा से पूर्व सहमति प्राप्त लेनी जरूरी है. ■

ग्राम सभा और वन अधिकार क़ानून

8 दिसंबर 2006 को सर्वसम्मति से अनुसूचित जाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) क़ानून 2006 पारित किया गया था. इस क़ानून के तहत किसी दावेदार को यह साबित करना है कि वह वनों में रहने वाले हैं और जीविकोपार्जन के लिए वनों तथा वनभूमि पर निर्भर हैं. दूसरा ये कि उन्हें यह साबित भी करना है कि उपर्युक्त स्थिति पिछले 75 साल से बनी हुई है और वे वनवासी अनुसूचित जनजाति के हैं. इस क़ानून के तहत तीन बुनियादी अधिकारों को मान्यता दी गई है. विभिन्न प्रकार की जमीन, जिसकी निर्धारण की आधार तिथि 13 दिसंबर 2005 है. पारंपरिक रूप से लघु वनोत्पाद, जल निकायों, चरागाहों आदि का उपयोग कर रहा हो. क़ानून की धारा 6 के अनुसार यह तय किया जाएगा कि किसे अधिकार मिले. सबसे पहले ग्राम सभा सिफारिश करेंगी कि कितने अरसे से कौन उस जमीन को जोत रहा है, किस तरह का वनोत्पाद वह लेता रहा है, आदि. यह जांच ग्राम सभा की वनाधिकार समिति करेगी, जिसकेनिष्कर्ष को ग्राम सभा पूरी तरह स्वीकार करेगी. इस क़ानून केतहत स्वीकृत जमीन न बेची जा सकेगी और न उसका अधिकार दूसरे को हस्तांतरित किया जा सकेगा. ■

लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा

वन अधिकार क़ानून के तहत किसी भी वन भूमि को खनन के लिए देने से पहले ग्राम सभा की सहमति की आवश्यकता होती है. आईए, जानते हैं कि ग्राम सभा होती क्या है और इसके मायने क्या हैं? किसी ग्राम की मतदाता सूची में जो नाम दर्ज होते हैं उन व्यक्तियों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहा जाता है. ग्राम सभा में 200 या उससे अधिक की जनसंख्या का होना आवश्यक है. ग्राम सभा की बैठक वर्ष में दो बार होनी आवश्यक है. इस बारे में सदस्यों को सूचना बैठक से 15 दिन पूर्व नोटिस से देनी होती है. ग्राम सभा की बैठक को बुलाने का अधिकार ग्राम प्रधान को है. वह किसी समय असामान्य बैठक का भी आयोजन कर सकता है. ज़िला पंचायत राज अधिकारी या क्षेत्र पंचायत द्वारा लिखित रूप से मांग करने पर अथवा ग्राम सभा के सदस्यों की मांग पर प्रधान द्वारा 30 दिनों के भीतर बैठक बुलाई जाएगी. यदि ग्राम प्रधान बैठक आयोजित नहीं करता है, तो यह बैठक उस तारीख़ के 60 दिनों केभीतर होगी, जिस तारीख़ को प्रधान से बैठक बुलाने की मांग की गई है. ग्राम सभा की बैठक के लिए कुल सदस्यों की संख्या 5वें भाग की उपस्थिति आवश्यक होती है. किंतु यदि गणपूर्ति (कोरम) के अभाव की वजह से बैठक न हो सके, तो इसके लिए दोबारा बैठक का आयोजन किया जा सकता है. दरबार बैठक के लिए 5वें भाग की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है. प्रत्येक ग्राम सभा में एक अध्यक्ष होगा, जो ग्राम प्रधान, सरपंच अथवा मुखिया कहलाता है तथा कुछ अन्य सदस्य होंगे. ग्राम सभा में 1000 की आबादी तक 1 ग्राम पंचायत सदस्य (वार्ड सदस्य), 2000 की आबादी तक 11 सदस्य तथा 3000 की आबादी तक 15 सदस्य होंगे. ■

feedback@chauthiduniya.com

आम आदमी की जान आफ़त में, सुरक्षा पर हो रहा बेतहाशा ख़र्च

केवल लखनऊ पर ख़र्च हो रहा है एक करोड़ हर रोज़

नेताओं की हिफ़ाज़त और तीमारदारी में लगी रहती है पुलिस

पूर्वी गणपति

आम से लेकर खास आदमी की सुरक्षा पुलिस के हवाले रहती है. जाम से निजात दिलाना हो या समाज को अपराध मुक्त बनाने की कवायद. सुरक्षा का दायित्व सिर्फ पुलिस विभाग का ही है. लेकिन इस सुरक्षा की कीमत जानेंगे तो अवाक रह जाएंगे. लखनऊ जनपद की एक दिन की सुरक्षा करने की कीमत पुलिस विभाग एक करोड़ रुपये लेती है. यानि एक करोड़ रुपये प्रतिदिन के खर्च पर लखनऊ की सुरक्षा होती है. हालांकि एक करोड़ रुपये प्रतिदिन के खर्च पर आम आदमी की सुरक्षा कितनी होती है, यह समीक्षा का विषय है. इस एक करोड़ रुपये का आधा हिस्सा खास लोगों (वीआईपी हस्तियों) की सुरक्षा पर ही खर्च हो जाता है.

लखनऊ शहर में पुलिस लोगों की सुरक्षा में तत्पर रहने का दावा करती है. लखनऊ जनपद में आगजनी हो या फिर जाम की शिकायत, चौराहे पर सरेआम लूट और हत्या का मामला हो या राहजनी या छेड़खानी-गुंडागर्दी का, हर मामले में पुलिस आम और खास की सुरक्षा का दावा करती है. लेकिन पुलिस इस पर कितना खरा उतरती है, यह सभी जानते हैं.

पुलिस का आंकिक विभाग कहता है कि लखनऊ जनपद में तैनात पुलिसकर्मी और अधिकारियों के वेतन मद में सालाना 3,46,12,36,051 रुपये खर्च हुए. इस आंकड़े को 12 माह में बांटा जाए तो एक दिन का वेतन 96,14,544.58 रुपये आता है. इस वेतन के अलावा पुलिस विभाग का पेट्रोल खर्च, स्टेशनरी सहित कई ऐसे कार्य हैं जिसका भुगतान सरकार हर माह करती है. लखनऊ जनपद में 17 पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी), 58 निरीक्षक (इंसपेक्टर), ट्रैफिक और सिविल पुलिस मिला कर करीब 550 दारोगा (सब इंसपेक्टर), 1082 मुख्य आरक्षी (हेड कांस्टेबल)और 5205 सिपाहियों की तैनाती है. इसके अलावा एक दर्जन से अधिक एडीशनल एसपी और एक एसएसपी हैं.

प्रोटोकॉल महकमे के एक आला अधिकारी के मुताबिक, वीआईपी ड्यूटी में प्रतिदिन का आंकड़ा निकालना कठिन है, क्योंकि शहर में वीआईपी की संख्या बढ़ती जाती है. एक अनुमान के मुताबिक प्रतिदिन लगभग 20 एस्कॉर्ट वीआईपी ड्यूटी में लगे रहते हैं. एक एस्कॉर्ट में एक जिप्सी वाहन, एक चालक, एक हेड कांस्टेबल और दो सिपाही तैनात होते हैं. इसके साथ ही लगभग पांच पीएसओ लगाए जाते हैं. पीएसओ में एक दारोगा होता है. पुलिस लाइन के प्रतिसार निरीक्षक बताते हैं कि तकरीबन छह सौ सिपाही वीआईपी हस्तियों की सुरक्षा में लगे हैं. इनमें से अधिकतर नेताओं की सुरक्षा फ्री में होती है, यानी उसका खर्चा सरकार उठाती है. इसके साथ ही प्रतिदिन तीन सौ सिपाहियों की ड्यूटी कोर्ट में कैदियों की पेशी कराने में लग जाती है. कुल मिलाकर प्रतिदिन डेढ़ हजार से अधिक पुलिसकर्मी आम आदमी की सुरक्षा से दूर ही रहते हैं. इसमें दर्जनों दारोगा भी शामिल हैं. लब्बोलुबाव यह है कि आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए आधे पुलिसकर्मी ही जनपद में मौजूद होते है. इसमें भी कुछ पुलिसकर्मियों की ड्यूटी रात में तो कुछ की ड्यूटी दिन में लगाई जाती है. यह हाल है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का. प्रदेश के जिलों का हाल तो और भी बदतर है.

वीआईपी और वीवीआईपी ड्यूटी में पुलिसकर्मियों की अत्यधिक संख्या में तैनाती को लेकर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर कोई नेता ध्यान क्यों दे! यहां तक कि एनएसजी कमांडो को भी नेताओं की सुरक्षा में लगाया जाता है. जेड प्लस कैटेगरी में संबंधित व्यक्ति की सुरक्षा में 40 पुलिसवाले लगाए जाते हैं. साथ ही 10-10 की संख्या में कमांडो की टीम होती है. एक बार में पांच कमांडो तैनात रहते हैं. इनमें से एक इंचार्ज होता है. बाकी चार कमांडो संबंधित व्यक्ति को घेरे रहते हैं. जिस वीवीआईपी को यह सुरक्षा दी जाती है, उसके साथ एक सब-इंस्पेक्टर और चार सिपाही की टीम वैन में काफिले के आगे-पीछे चलती है. केंद्र सरकार की ओर से संबंधित व्यक्ति को नेशनल सिक्युरिटी गार्ड (एनएसजी) के 10-10 कमांडो उपलब्ध कराए जाते हैं. साथ ही, पीएसी के कोबरा कमांडो भी तैनात किए जाते हैं. सुरक्षा की इस श्रेणी के अलावा जेड, वाई और एक्स श्रेणी भी हैं. इन श्रेणियों की सुरक्षा में भी बड़ी तादाद में पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं. प्रदेश में वीआईपी सुरक्षा पाने वालों में मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद, नौकरशाह, पूर्व नौकरशाह, जज, पूर्व जज, व्यापारी, क्रिकेटर, सिनेमा कलाकार, साधु-संत, मुल्ला-मौलवी से लेकर सत्ता तक पहुंच वाले माफिया और दलाल भी शामिल हैं. ■

यूपी में गनर-फैशन के मारे सबसे अधिक

यूपी में सुरक्षा मुहैया कराने और हथियारबंद गनर की मांग लगातार बढ़ती जा रही है. छुटभैये इसे ही स्टेटस-सिम्बल मानते हैं. मौजूदा सरकार में तो गनर पाने के लिए किसी बड़े नेता या नौकरशाह की सिफारिश ही काफी है. सत्ता व सामर्थ्यवानों की सुरक्षा पर 25 करोड़ रुपये प्रति माह खर्च करने वाली सरकार तो अब किश्तों में भी गनर मुहैया करा रही है. यह बात भी उजागर हो चुकी है कि गृह विभाग को सिर्फ एक सिफारिशी फोन मिलने पर संबंधित व्यक्ति को गनर दे दिया जाता है. नियमत: एक महीने के लिए सरकारी गनर मिलता है, लेकिन सरकार के चहेतों के लिए यह तीन-चार साल तक बेरोक-टोक जारी रहता है. ऐसे डेढ़ हजार तथाकथित वीआईपी हैं, जिनकी सुरक्षा में तीन हजार से अधिक गनर लगे हैं. जिन लोगों की सुरक्षा-अवधि (गनर अवधि)खत्म भी हो गई, उन्हें भी सत्ता-लाभ प्राप्त हो रहा है. अब इससे ही अंदाजा लगा लीजिए कि इन्फोर्समेंट निदेशालय की जांच और आयकर छापों की मार झेलने वाले विवादास्पद बिल्डर संजय सेठ जैसे लोगों को भी सरकारी सुरक्षा मिली हुई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट के सख्त निर्देश पर गृह विभाग के प्रमुख सचिव, डीजीपी और डीजी (सिक्युरिटी) की सदस्यता वाली विशेष कमेटी बनी हुई है जो गनर के लिए दिए जाने वाले आवेदनों की जांच करती है. गनर देने से पहले आवेदक के इलाके की स्थानीय खुफिया इकाई (एलआईयू) से जांच रिपोर्ट प्राप्त करने और उसकी गहन समीक्षा जरूरी है. लेकिन यह नियम जमीन पर कहीं नहीं दिखता. अब तो वीआईपी छोड़िए, मायावती के मुख्यमंत्रित्वकाल में राजधानी में बनी तमाम मूर्तियों और पत्थर-पार्कों की सुरक्षा में भी सुरक्षाबल लगे हैं. आम आदमी क्या करे!

feedback@chauthiduniya.com

भुखमरी, प्यासमरी और बिजलीमरी का शिकार बुंदेलखंड

बिजली-पानी नहीं तो क्या, नेतागीरी तो है!

सूफी यायावर

सूखा, भुखमरी और प्यासमरी से आक्रांत बुंदेलखंड बिजलीमरी का भी शिकार है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड को 24 घंटे बिजली मुहैया कराए जाने का निर्देश दे रखा है. लेकिन वहां 20-20 घंटे बिजली नहीं दी जा रही. लोग त्राहिमाम हैं. बिजलीमरी के खिलाफ लोग धूप में धरना दे रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों से लेकर शासन-प्रशासन तंत्र के नुमाइंदों का लोगों की त्रासदी से कोई लेना-देना नहीं है. यहां तक कि महोबा दौरे पर आए मुख्यमंत्री ने भी इस मामले में कोई सुध नहीं ली, अपना ही वादा कार्यान्वित हो रहा है कि नहीं इस बारे में कोई खोज-खबर भी नहीं ली. मुख्यमंत्री के इस रवैये से क्षेत्र में लोगों के बीच घनघोर निराशा और गुस्सा है. लोगों की नाराजगी है कि मुख्यमंत्री ने भयंकर गर्मी में भीषण बिजली कटौती व बिजली जुल्म का शिकार जनता को राहत देने के लिए दो शब्द भी नहीं बोले.

बुंदेलखंड के हृदयस्थल महोबा में आजकल भीषण कटौती व तेज गति से भाग रहे घटिया मीटरों से गरीब जनता में हाहाकार मचा हुआ है. यहां 15 से 20 घंटे की बिजली कटौती चल रही है. लेकिन हर उपभोक्ता का मासिक बिल पांच से 10 हजार रूपये आ रहा है. गांवों में जहां मुश्किल से कुछ देर के लिए बिजली आती है, वहां भी लोगों के बिजली बिल हर महीने हजारों रुपये के आ रहे हैं. लोगों की नींद उड़ी हुई है. ग्राम धरौनमाफ के सुरेश प्रजापति कहते हैं कि अभी तक हम पानी के लिए परेशान थे, अब मनमाने बिजली बिलों ने हमारी नींद उड़ा दी है. बिजली आती नहीं, लेकिन हर महीने डेढ़ हजार का बिल जरूर आ जा रहा है. बड़ी संख्या में लोगों को लगने लगा है कि उन्होंने बिजली लगवाकर बड़ी गलती कर दी. वे मानते हैं कि इससे बेहतर तो वे पहले थे. जनता अब मांग कर रही है कि बिजली के कनेक्शन काट दो. उन्हें अब बिजली नहीं चाहिए.

अंधेरे में डूबे हैं सैकड़ों गांव

महोबा के पनवाड़ी विकास खंड क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बिल्कुल ही ठप्प है. इस वजह से सैकड़ों गांव अंधेरे में डूबे हुए हैं. ग्रामीणों का बुरा हाल है. बिजली न आने से पेयजल संकट और बढ़ गया है. ब्लॉक पनवाड़ी के ग्राम महोबकंठ, नकरा, वैदां, मसूदपुरा, नगारा घाट, दिदवारा, बहादुरपुरा, किल्हौवा, पहाड़िया, भरवारा, तेइया, जखा, तुर्रा, सुगिरा सहित कई की बिजली आपूर्ति ठप्प पड़ी है. कस्बे के बैल बाजार और मुल्लनपुरा मोहल्लों में कई दिनों से ट्रांसफार्मर फुंके पड़े हैं. बिजली महकमा ट्रांसफार्मर बदलवाने की सुध नहीं ले रहा है. बिजली विभाग के एक्सईएन, एसडीओ और जेई को कई बार सूचना देने के बावजूद ट्रांसफार्मर नहीं बदलवाए जा रहे हैं.

भूखे-प्यासे महोबा में अखिलेशी बौछार

भूख और प्यास के शिकार बुंदेलखंड में प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अब तालाब खोदवा रहे हैं. जब सारे तालाब खनन माफियाओं ने खोद डाले तब अखिलेश यादव आठ तालाबों के लोकार्पण का चुनावी प्रहसन खेल रहे हैं. पिछले दिनों मुख्यमंत्री समाजवादी जल संचय योजना के तहत तालाबों की खुदाई की जमीनी हकीकत जानने के लिए चरखारी पहुंचे. जो लोग जमीनी हकीकत जानते हैं, वे सब मुख्यमंत्री से बहुत दूर रखे गए और चाटुकार-भांड नजदीक. कुछ तालाबों के पुनर्जीवन निर्माण कार्यों का उन्होंने निरीक्षण करने की औपचारिकता निभाई और जयसागर, कोठीताल, बंसिया ताल, मलखान तालाब, रपट तलैया, गुमान बिहारी तालाब, रतनसागर और गोलाघाट तालाब को फिर से जनता को अर्पित कर दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण के लिए समाजवादी सरकार ने एक दिन में पांच करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है. एक दिन में पांच करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य खुद ही बताता है कि यह लक्ष्य कागजों पर कैसे पूरा हो जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी सरकार संकट की घड़ी में बुंदेलखंड के लोगों के साथ खड़ी है, लेकिन उन्होंने बिजली से बेहाल जनता के बारे में कोई सुध ही नहीं ली.

महोबा के सभी 18 हजार उपभोक्ताओं के बिल एक महीने में उत्पीड़न बंद नहीं किया तो उनको मजबूरन यह कदम उठाना पड़ेगा. गौरतलब है कि अनशनकारी बुंदेली समाज व बिजली विभाग के अफसरों के बीच दो बार समझौता हो चुका है. सही करने का वादा किया गया, लेकिन बाद में फर्जीवाड़ा खुलने के डर से उसे टाल दिया गया. अकाल के दौर में सरकार यहां की भूखी प्यासी जनता को आटा भाटा बांटकर राहत पहुंचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस भ्रष्टाचार जनित समस्या से जनता को उबारने का काम नहीं कर रही. सरकार ने सभी राजस्व वसूली रोकने की घोषणा कर रखी है, लेकिन महोबा में तेज गति से भाग रहे घटिया मीटरों से बिल भेजकर बिजली विभाग गरीब जनता का खून चूसने में जुटा हुआ है. बिल जमा न होने पर इस भीषण गर्मी में उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं. लोगों में सरकार के इस रवैये से भारी नाराजगी का माहौल है. महोबा के 18 हजार बिजली उपभोक्ता इस कारण सदमे में चले गए हैं.

बुंदेली समाज के संरक्षक सुखनंदन सिंह यादव ने बताया कि यहां बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं. उनका व संयोजक तारा पाटकर का कोई बकाया नहीं था. हम लोग हर महीने आ रहे बिल जमा करते हैं. लेकिन धरना देने के कारण बौखलाए अफसरों ने बदले की भावना से हमारी बिजली काट दी. भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी करके लगवाए गए खराब मीटरों से आ रहे अनाप-शनाप बिजली बिलों को माफ किए जाने को लेकर धरनारत लोगों ने अनोखा किंतु दर्दनाक धूप सत्याग्रह भी किया. इसमें अनशनकारी चिलचिलाती धूप में आल्हा चौक पर बड़ी संख्या में एकत्र होकर दिनभर नंगे पांव खड़े रहे.

बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर ने कहा कि समूचे बुंदेलखंड में इस वक्त प्राकृतिक आपदा के साथ बिजली आपदा भी आई हुई है, जिसमें फंसकर यहां की 90 फीसदी जनता कराह रही है. यह आपदा बिजली विभाग के अफसरों और दलालों द्वारा पैसे एंठने के लिए भेजे जा रहे लाखों के बिजली बिलों से आई है. इन उल्टे-सीधे बिलों को निरस्त कर बिजली शुल्क की माफी ही अब इस समस्या का समाधान है. पाटकर ने कहा कि बिजली दलालों और बिजली अफसरों के गठजोड़ को तभी तोड़ा जा सकता है. उन्होंने कहा कि जब तक बुंदेलखंड में बिजली बिल माफ नहीं किए जाते, बुंदेली समाज का अनशन जारी रहेगा. पाटकर ने कहा कि बिजली विभाग के भ्रष्टाचार के खिलाफ महोबा की जनता के सड़क पर उतर आने से विभाग के भ्रष्ट अधिकारी बौखला गए हैं और इस बौखलाहट में विरोध प्रदर्शनों को नेतृत्व देने वाले लोगों को दलाल और बिचौलिया और तमाम ऐसे संबोधनों से विभूषित कर रहे हैं, जिसके वे खुद योग्य हैं. लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों की इन हरकतों से जनता का आंदोलन और गहराता ही जा रहा है.

feedback@chauthiduniya.com

मणिपुर की हालत

जो दिल्ली से नहीं दिखती

एस. बिजेन सिंह

दिल्ली की सड़कों पर घूमता एक मणिपुरी देश के बाकी लोगों के लिए कभी नेपाली होता है, कभी नॉर्थ-ईस्ट का रहने वाला तो कभी-कभी उसे ऐसे संबोधनों से गुजरना पड़ता है, जिसे यहां नहीं लिखा जा सकता है. देश का पूर्वोत्तर हिस्सा हमारे प्रधानमंत्री की नजर में भले देश की भुजा हो या मणिपुर देश का एक मणि हो, लेकिन हकीकत इसके ठीक उलट है. पूरे नॉर्थ-ईस्ट की बात छोड़ सिर्फ मणिपुर की ही बात करें तो यह खूबसूरत पहाड़ी राज्य आज अशांत है. सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी. राजनीतिक अस्थिरता, इनर लाइन परमिट का मसला हो, अफस्पा या फिर पहाड़ बनाम तराई के निवासियों की आपसी लड़ाई. इन सब ने मिलकर इस खूबसूरत राज्य को स्थानीय लोगों के लिए एक दुस्वप्न में बदल दिया है. जाहिर है, देश के सुदूर हिस्से में होने के कारण ये खबरें राष्ट्रीय मीडिया के एजेंडे में शामिल नहीं हो पातीं. इस स्टोरी के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मणिपुर के अंतर्कलह और अंतर्विरोध की वजहें क्या हैं?

पिछले साल 31 अगस्त को राज्य विधानसभा में मणिपुर जन संरक्षण विधेयक-2015, मणिपुर भू-राजस्व एवं भूमि सुधार (सातवां संशोधन) विधेयक-2015 और मणिपुर दुकान एवं प्रतिष्ठान (दूसरा संशोधन) विधेयक-2015 पारित हुआ था. मणिपुर जन संरक्षण विधेयक-2015 बाहरी लोगों के आने और वहां रहने के लिए परमिट पर बल देता है, ताकि कोई बाहरी स्थाई तौर पर यहां न बस सके. दूसरा मणिपुर भू-राजस्व एवं भूमि सुधार (सातवां संशोधन) विधेयक-2015, मणिपुर के किसी भी क्षेत्र में जमीन खरीद-फरोख्त में बाहरी लोगों का हक न हो, से संबंधित है. स्थानीय लोगों को कहीं भी जमीन खरीद-फरोख्त में समान अधिकार प्राप्त हो. तीसरा मणिपुर दुकान एवं प्रतिष्ठान (दूसरा संशोधन) विधेयक-2015 में बाहर से आए लोगों को दुकान और मकान किराये पर लेने के लिए एक लिखित पत्र देना होगा जिसपर जिलाधिकारी का हस्ताक्षर हो.

दरअसल, मणिपुर भू-राजस्व एवं भूमि सुधार (सातवां संशोधन) विधेयक-2015 पर झमेला खड़ा हो गया है. पहाड़ पर रहने वाले लोग नहीं चाहते कि राज्य के सभी निवासियों को जमीन खरीदने का समान अधिकार मिल जाए. उन्हें इस बात का डर है कि इससे उनकी जमीन पर तराई में रहने वाले लोग कब्जा कर लेंगे. इस बिल के विधानसभा में पास होते ही मणिपुर की जनता दो हिस्सों में बंट गई. जेसीआईएलपी (ज्वाइंट कमेटी ऑफ इनर लाइन परमिट), जो इनर लाइन परमिट की मांग करने वाली संस्था है और जिसमें घाटी में रहने वाले मैतै समुदाय के लोगों की संख्या ज्यादा है, उनका कहना है कि राज्य में बाहरी लोगों की संख्या बढ़ने से मैतै समुदाय अल्पसंख्यक हो जाएगा. उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए इनर लाइन परमिट जरूरी है. राज्य में मैतै बहुसंख्यक समुदाय है. वे हिंदू धर्म मानते हैं. लेकिन उनकी इस मांग से पहाड़ी क्षेत्र के लोग नाखुश हैं. वे उनकी इस मांग का विरोध करते हैं. पहाड़ी क्षेत्र के लोग ईसाई धर्मावलंबी हैं. वे नहीं चाहते कि मैतै को भी जमीन खरीदने का समान अधिकार मिले. इसी विरोध की आग में प्रदेश जल रहा है. जेसीआईएलपी (ज्वाइंट कमेटी ऑफ इनर लाइन परमिट) के नेतृत्व में राज्य के छात्र-छात्राएं समेत कई सामाजिक संगठन राज्य सरकार के विरोध में सड़क पर उतर आए. छात्र-छात्राओं पर लाठी चार्ज, आंसू गैस, रबर बुलेट और वाटर कैनन की बौछार से कई घायल हो गए. संपूर्ण राज्य में बंद का एलान किया गया. राज्य में कई जगहों पर इस बंद के समर्थन में लोग सड़कों पर उतर आए. यातायात बंद होने से लोगों की जिंदगी नरक बन गई है.

दरअसल राज्य की 60 विधानसभा सीटों में से सिर्फ 20 आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं, जबकि राज्य की जनसंख्या में आदिवासी 40 से 45 प्रतिशत हैं. गौरतलब है कि छठी अनुसूची के तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्रों को ऐसे मामलों का निपटारा करने के लिए ज्यादा स्वतंत्रता मिली है. हालांकि मणिपुर में पहले से छह ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कार्यरत हैं. इसके अलावा एक पहाड़ी क्षेत्र कमेटी का भी गठन किया गया है. लेकिन स्थानीय पहाड़ी लोगों का कहना है कि यह पर्याप्त नहीं है. वे कहते हैं कि जब विधेयक पारित हो रहा था तब पहाड़ी क्षेत्र के ज्यादातर विधायक चुप रहे. वे आदिवासियों की आवाज उठाने में नाकाम रहे. इन विधेयकों के विरोध में जनजातीय छात्र संगठनों का कहना है कि मणिपुरी निवासी सुरक्षा विधेयक 2015 (प्रोटेक्शन ऑफ मणिपुर पीपुल्स बिल-2015) और अन्य दो संशोधन विधेयक राज्य के उन पहाड़ी जिलों में जमीन की खरीद और बिक्री की इजाजत देते हैं, जहां नगा और कुकी रहते हैं.

इन आदिवासियों को डर है कि नया कानून आने के बाद पहाड़ी क्षेत्र में गैर आदिवासी बसने लगेंगे. जबकि वहां जमीन खरीदने पर अब तक पाबंदी थी. सरकार द्वारा लाए गए तीनों विधेयकों के विरोध में चल रहे आंदोलन की अगुवाई कर रही ज्वॉइंट एक्शन कमेटी के संयोजक एच मांगचिनखुप गाइते का मानना है कि पहले विधेयक से हमारी आदिवासी पहचान का उल्लंघन होता है. यह विधेयक भूमि संबंधी हमारे अधिकारों की अवहेलना करता है जबकि तीसरा हमारे जीवनयापन को नुकसान पहुंचाता है. पहाड़ी क्षेत्र को सरकार ने कभी मणिपुर का हिस्सा नहीं माना. हमारा विकास नहीं किया. हमेशा पहाड़ के लोगों के साथ भेदभाव किया गया, जो अब भी जारी है. इन विधेयकों को देखने के बाद यह बात साफ हो जाती है कि अब घाटी में जमीन को लेकर बढ़ता दबाव इस कानून को पास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा है. इस विधेयक में मणिपुर के मूल निवासी को सही तरीके से परिभाषित नहीं किया गया है.

वास्तव में देखें तो मणिपुर का यह मामला भावनात्मक और संवेदनशील होने के साथ जटिल भी है. घाटी में रह रहे मैतै समुदाय का तर्क है कि जनसंख्या का सारा दबाव उनकी जमीन पर है. उनके अनुसार घाटी में संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में जमीन खरीदने पर मनाही है. साथ में बाहर से आए लोगों की इतनी भीड़ बढ़ गई कि वहां रहना मुश्किल हो गया है. वहीं पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समुदाय के नुमाइंदे आरोप लगाते हैं कि सरकार ने कभी आदिवासियों से इस बारे में बात कर उनका भरोसा जीतने की कोशिश नहीं की है और विधेयक पास कर लिया.

मणिपुर के चूराचांदपुर, चंदेल, उखूल, सेनापति और तमेंगलोंग जिले पहाड़ी क्षेत्र में आते हैं. वहीं थौबाल, इंफाल ईस्ट और इंफाल वेस्ट जिले घाटी में आते हैं. लैंड बिल में कहा गया है कि क्षेत्रफल के हिसाब से मणिपुर का 10 फीसदी हिस्सा घाटी का है. हालांकि राज्य की 60 प्रतिशत जनता घाटी में रहती है. इस कारण मैतै समुदाय पहाड़ी क्षेत्र में जमीन दिए जाने की मांग करता रहा है. मणिपुर के साथ समस्या यह है कि करीब 90 प्रतिशत जमीन पहाड़ी क्षेत्र में है और 60 प्रतिशत आबादी घाटी में रहती है. अब घाटी में रहने वाले मैतै समुदाय को पहाड़ी क्षेत्र में जमीन खरीदने की अनुमति नहीं है जबकि घाटी में किसी को भी जमीन खरीदने की अनुमति है. मैतै समुदाय को लगता है कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है. इसी तरह पहाड़ी क्षेत्र की आबादी, जो राज्य की कुल आबादी का 40 प्रतिशत है, चाहती है कि बाहरी लोगों को पहाड़ी क्षेत्र में जमीन खरीदने की अनुमति न दी जाए. इससे उनकी आबादी में बदलाव आएगा साथ ही उनकी निजता का हनन होगा.

राज्य में नगा-कुकी जाति के अलावा मैतै, मणिपुरी मुस्लिम (पांगल), ईसाई आदि जातियां भी रहती हैं. मैतै मणिपुर राज्य का बहुसंख्यक समुदाय है. राज्य में सबसे बड़ी समस्या है असुरक्षा की भावना. चाहे बात मैतै, नगा, कुकी या किसी और समुदाय की हो. इस विधेयक का मैतै समुदाय समर्थन कर रहा है जबकि कुकी और नगा इसके विरोध में हैं. हालत यह है कि पहाड़ी क्षेत्र के लोग कुछ कहते हैं तो घाटी के लोग उसका विरोध करते हैं और अगर घाटी के लोग कुछ कहते हैं तो पहाड़ी क्षेत्र के लोग उसका विरोध करते हैं. इस मामले में दोनों पक्षों को बातचीत के टेबल पर लाकर ही समाधान निकाला जा सकता है. दूसरी बात, इस समस्या को सुलझाने में केंद्र सरकार और राष्ट्रपति की भी अहम भूमिका है. क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र और घाटी के लोगों के लिए यह संभव नहीं है वे इस मामले को अपने स्तर पर सुलझा सकें. वैसे मणिपुर में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. इसके बावजूद राज्य सरकार व विपक्षी दल गतिरोध दूर करने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं. सरकार को इस मामले को आदिवासी बनाम गैर आदिवासी, पहाड़ी क्षेत्र बनाम घाटी, हिंदू बनाम ईसाई या फिर फायदे नुकसान से ऊपर उठकर देखना होगा. ■

sbijensngh@gmail.com

वास्तव में देखें तो मणिपुर का यह मामला भावनात्मक और संवेदनशील होने के साथ जटिल भी है. घाटी में रह रहे मैतै समुदाय का तर्क है कि जनसंख्या का सारा दबाव उनकी जमीन पर है. उनके अनुसार घाटी में संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में जमीन खरीदने पर मनाही है. साथ में बाहर से आए लोगों की इतनी भीड़ बढ़ गई कि वहां रहना मुश्किल हो गया है. वहीं पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी समुदाय के नुमाइंदे आरोप लगाते हैं कि सरकार ने कभी आदिवासियों से इस बारे में बात कर उनका भरोसा जीतने की कोशिश नहीं की है और विधेयक पास कर लिया.

क्या है तीन विधेयक और क्यों है विवाद ?

31 अगस्त 2015 को मणिपुर विधानसभा में मणिपुर जन संरक्षण विधेयक-2015, मणिपुर भू-राजस्व एवं भूमि सुधार (सातवां संशोधन) विधेयक-2015 और मणिपुर दुकान एवं प्रतिष्ठान (दूसरा संशोधन) विधेयक-2015 पारित किए गए थे. लेकिन इन विधेयकों के पास होने के बाद मणिपुर के आदिवासी समूह असंतुष्ट हो गए. जनजातीय छात्र संगठनों का दावा है कि मणिपुरी निवासी सुरक्षा विधेयक-2015 (प्रोटेक्शन ऑफ मणिपुर पीपुल्स बिल-2015) और अन्य दो संशोधन विधेयक राज्य के उन पहाड़ी जिलों में जमीन की खरीद और बिक्री की इजाजत देते हैं जहां नगा और कुकी रहते हैं. उनका कहना है कि इन विधेयकों के कुछ प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 371 (सी) और मणिपुर हिल पीपुल एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशन एक्ट-1947 का हनन करते हैं, जिन्हें मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में बसने वाले जनजातीय लोगों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था. इनके तहत राज्य के पहाड़ी जिलों को विशेष क्षेत्र का दर्जा मिला है यानी गैर-अनुसूचित जातियां यहां जमीन नहीं खरीद सकतीं. बाहरी लोगों के आने के कारण कुल आबादी में मूल निवासियों की तेजी से घटती संख्या की वजह से उन्हें अपनी पुश्तैनी जगह से बेदखल होने का डर पैदा हो गया है. इन तीनों विधेयकों में साल 1951 की समय सीमा ने जनजातियों में डर का एक माहौल पैदा कर दिया कि इस तारीख के बाद राज्य में आने वाले नगा और कुकी जनजातियों को अपनी जमीन छोड़नी पड़ेगी. नए कानून के मुताबिक मणिपुर में जो लोग 1951 से पहले बसे हैं उन्हें ही संपत्ति का अधिकार होगा. इसके बाद बसे लोगों का संपत्तियों पर कोई हक नहीं होगा. ऐसे लोगों को राज्य से जाने के लिए भी कहा जा सकता है. नया कानून बनाने की मांग मणिपुर के बहुसंख्यक मैतै समुदाय ने की थी. आदिवासी समूह इसका विरोध कर रहे हैं. आदिवासियों को आशंका थी कि उन्हें नए कानून का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. यह अलग बात है कि नया कानून बनने के बाद बाहरी राज्यों से मणिपुर आने वाले लोगों के लिए परमिट लेना जरूरी होगा.

हर दिन, हर पल मनाएं विश्व पर्यावरण दिवस

साध्वी भगवती सरस्वती

यह ख़ुशी की बात है कि हमने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया. हमारे लिए हर दिन, हर लम्हा, हर क्षण विश्व पर्यावरण दिवस होना चाहिए. पर्यावरण के बिना एक पल, एक लम्हा भी जीना मुश्किल है. लिहाज़ा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 जून को पर्यावरण दिवस घोषित किया है. अगर वे इस दिन को विश्व जीवन दिवस घोषित करते तो भी कुछ गलत नहीं होता, क्योंकि पर्यावरण ही हमें जीवन देता है. हम अक्सर पर्यावरण और पृथ्वी की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन रक्षा की ज़रूरत दरअसल मानव जाति को है. पृथ्वी का अस्तित्व तब भी रहेगा जब यहां ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी और कार्बन का स्तर ऊंचा हो जाएगा. पृथ्वी पेड़-पौधों, ध्रुवीय हिमखंडों और हिमनदों के बगैर भी अपना अस्तित्व बचाए रखेगी. लेकिन, कार्बन और ऑक्सीजन का नाज़ुक संतुलन धरती पर जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है. दरअसल ध्रुवीय क्षेत्रों के हिमखंडों और हिमनदों से जल की आपूर्ति इंसानों की जरूरतों को पूरा करती है. इंसान को पेड़ों की आवश्यकता है, क्योंकि जो सांस हम छोड़ते हैं उसे पेड़ पुनः इस्तेमाल योग्य बनाते हैं. लिहाज़ा मनुष्य पृथ्वी का संरक्षण नहीं कर रहा है, बल्कि पृथ्वी का संरक्षण कर वह खुद अपनी रक्षा कर रहा है.

अब इससे संबंधित चुनौतियों और अपनी जिम्मेदारियों की बात करते हैं. सच्चाई यह है कि हमारे सामने उतनी चुनौतियां नहीं हैं जितनी हम समझते हैं. हमें चुनौतियां बड़ी इसलिए लग रही हैं, क्योंकि हमने अपनी जिम्मेदारियों को भुला दिया है. यदि हम पृथ्वी और एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें तो ये चुनौतियां दूर हो जाएंगी. ये स्थितियां हमारे अंदर अलगाव और अपराजेय होने के भ्रम के कारण बनी हैं.

समुद्र में एक नौका पर सवार तीन लोगों की एक बहुत खूबसूरत कहानी है. एक नौका पर सवार तीन लोग बीच समुद्र में घिर गए थे. जैसा कि तनावपूर्ण स्थिति में होता है वे तीनों आपस में झगड़ने लगे. झगड़ा निपटाने और स्वस्थ माहौल बनाने के लिए उन्होंने नाव को तीन बराबर हिस्सों में बांट लिया. अब नाव पर मौजूद तीनों लोगों के पास नाव का एक तिहाई हिस्सा था, लेकिन बटवारे की रेखा काल्पनिक और अदृश्य थी. कुछ दिनों बाद नाव पर सवार दो लोगों ने देखा कि तीसरे के हिस्से वाले नाव में एक सुराख़ हो गया है और उससे पानी रिस कर नाव के अंदर जमा हो रहा है. दोनों में से एक ने कहा कि हमें पानी के रिसाव को रोकना चाहिए, नहीं तो हम सभी डूब जायेंगे. तब दूसरे व्यक्ति ने कहा, फ़िक्र करने की कोई बात नहीं रिसाव तीसरे व्यक्ति के हिस्से में हो रहा है. वे यह समझ नहीं पा रहे थे कि रिसाव नाव के किसी भी हिस्से में हो, अगर उसे बंद नहीं किया गया तो वह समूचे नाव को डुबो देगा. इसके बावजूद हमने अपने और दूसरे राष्ट्रों के बीच काल्पनिक रेखाएं खींच रखी हैं. हाल में परमार्थ निकेतन आश्रम (ऋषिकेश) में ब्राज़ील से एक ग्रुप आया था, उन्होंने बताया कि यह साल इतिहास का सबसे मुश्किल साल है. उनके इस बयान से किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि यह पूरी दुनिया में सबसे गर्म साल रहा है. हालात ये हैं कि साओ पाउलो (ब्राज़ील) में पानी की कमी के कारण शहर को ही खाली कराने की बात चल रही है.

पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें पुराने प्रतिमानों को बदलना होगा. सबसे पहले सूचना की बात. हम सभी की जेब में एक मशीन है, जिसने दुनिया भर की सूचनाओं को हमारी हथेली पर लाकर रख दिया है. परंतु हम यह भूल गए हैं कि इसके परे भी एक दुनिया है. हम एक दूसरे की तस्वीरें पसंद करते हैं, उन्हें साझा करते हैं. हम अपने डिनर में हैमबर्गर, चिकन खाते हैं, मनोरंजन के लिए एंटरटेनमेंट सेंटर जाते हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियां ख़रीदते हैं. हम नई-नई वस्तुओं की तस्वीरें शेयर करते हैं, जो उन फैक्ट्रियों में बनती हैं, जो हवा और पानी को ज़हरीला बना रही हैं.

दुनिया का 20 प्रतिशत ऑक्सीजन अमेज़न के वर्षा वन से प्राप्त होता है. यह वन कार्बन उत्सर्जन के 20 प्रतिशत हिस्से का अवशोषण करता है. विश्व का 20 प्रतिशत साफ़ पानी भी यहीं से मिलता है. इसके बावजूद जब तक आप यह लेख पढ़ रहे होंगे तब तक कई एकड़ वर्षा वन काटे जा चुके होंगे. एक अनुमान के मुताबिक प्रति सेकंड एक से दो एकड़ भूमि पर वन की कटाई हो रही है. यह केवल अमेज़न की सच्चाई नहीं है, बल्कि वर्ष 2000 के बाद से दुनिया के हर क्षेत्र में वनों की कटाई हो रही है. इस अवधि में हमने अपने देश के क्षेत्रफल के बराबर वनों को नष्ट कर दिया है. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? इसलिए न कि हम अपने मवेशियों को चारागाह उपलब्ध करा सकें जो हमारे लिए हैमबर्गर में इस्तेमाल हों. जिनके पास पैसे हैं उनके लिए, टीक और महोगनी के टेबल और दरवाज़े बनवा सकें और जीवाश्म ईंधन के लिए पाइपलाइन बिछा सकें.

आज दुनिया में हमारे जंगलों के साथ जो हो रहा है, उसके कारण हमें अधिक गर्मी और प्यास झेलनी पड़ रही है. आने वाला कल और अधिक कठिनाइयों से भरा होगा, जब हमारे बच्चों का दम शुद्ध हवा के अभाव में घुटने लगेगा. दुनिया को देखने या यहां रहने के दो नजरिए हैं. या तो हम दुनिया को एक बाज़ार की तरह देखें जिसका मुख्य उद्देश्य प्रतिस्पर्धा है और छीना-झपटी है. यह दुनिया हमारी है, हम जैसे चाहें इसका इस्तेमाल करें और जैसे चाहें इसका तिरस्कार करें. या फिर हम दुनिया को एक दूसरे नज़रिए से देखें, जिसमें वह बाज़ार नहीं बल्कि एक परिवार है. जब हम दुनिया को एक परिवार की तरह देखते हैं तब हम इसके सहभागी बन जाते हैं. तब यह स्वीकार्यता बढ़ जाती है कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और पीने के लिए पानी पर सबका समान अधिकार है. हम वसुधैव कुटुम्बकम में विश्वास करते हैं. हम विश्व को बाज़ार नहीं, बल्कि परिवार मानने वाले लोग हैं.

पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें पुराने प्रतिमानों को बदलना होगा. सबसे पहले सूचना की बात. हम सभी की जेब में एक मशीन है, जिसने दुनिया भर की सूचनाओं को हमारी हथेली पर लाकर रख दिया है. परंतु हम यह भूल गए हैं कि इसके परे भी एक दुनिया है. हम एक दूसरे की तस्वीरें पसंद करते हैं, उन्हें साझा करते हैं. हम अपने डिनर में हैमबर्गर, चिकन खाते हैं, मनोरंजन के लिए एंटरटेनमेंट सेंटर जाते हैं, बड़ी-बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं. हम नई-नई वस्तुओं की तस्वीरें शेयर करते हैं, जो उन फैक्ट्रियों में बनती हैं, जो हवा और पानी को ज़हरीला बना रही हैं.

लिहाज़ा हमें सूचना की ज़रूरत तो है, लेकिन उस सूचना से प्रेरणा लेकर आवश्यक कदम उठाने की ज़रूरत है. हमें तकनीक में इनोवेशन लाने की ज़रूरत है. हमें ऐसे टूल्स की आवश्यकता है जो सही विकल्प चुनने में हमारी मदद करे. हमें पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने की जरूरत है ताकि हमें अपनी सफलता व लाभ-हानि का पता चल सके. यह लाभ और हानि पैसे की नहीं है, बल्कि पर्यावरण को, पृथ्वी को, हमारे अभिकों को कितना नुकसान हुआ, उसकी लाभ और हानि है. विश्व पर्यावरण दिवस हमें यह सोचने का मौका देता है कि हम पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुम्बकम के रूप में स्वीकार करें. और यह सोचें कि हमें क्या खाना है, क्या पहनना है, हमें क्या खरीदना है और हमें कैसे रहना है. दरअसल विश्व पर्यावरण दिवस केवल पर्यावरण दिवस नहीं बल्कि इस धरती पर रहने वाले हमारे सभी भाई-बहनों के लिए विश्व जीवन दिवस है. ■

(लेखिका ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन से जुड़ी हुई हैं)

feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

ख़ुफ़िया एजेंसियों की नाकामी

चौथी दुनिया का 23-29 मई 2016 का अंक पढ़ा. अखबार में खबरों का संकलन व प्रस्तुतिकरण बेहतर तरीके से किया गया है. देश की खुफिया एजेंसी रॉ की असफलता पढ़कर दुख होता है. एजेंसी के अफसरों और कर्मचारियों में कोई तालमेल नहीं है जिसकी वजह से सूचनाएं लीक होती हैं. उनको शर्म आनी चाहिए कि उनकी शिक्षा-दीक्षा, प्रशिक्षण, वेतन भत्तों, सुख-सुविधाओं पर देश के करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, लेकिन वे देश का कर्ज समझकर अपने कार्यों को नहीं करते हैं. उल्टा दूसरों पर अपना रौब जमाते हैं. इन अधिकारियों को अमेरिका और यूरोपीय खुफिया एजेंसियों से सीखना चाहिए जिनकी सूचनाएं सौ प्रतिशत सत्य होती हैं. देश में लोकतांत्रिक सरकार है जो देश की जनता द्वारा चुनी जाती है. क्या उनका कोई कर्तव्य नहीं है जो सिर्फ प्रधानमंत्री के इशारे का इंतजार करते हैं. देश की सभी खुफिया एजेंसियों से गुजारिश है कि देश की प्रतिष्ठा मिट्टी में न मिलाएं. हमारे यहां कभी प्रतिभाओं की कमी नहीं रही, अतीत में भी और वर्तमान में भी.

-कजोड़ राम निखिल नागर,
दक्षिण पुरी, नई दिल्ली.

इंटरनेट का स्याह पक्ष

संचार क्रांति के फलस्वरूप बीते 20 वर्षों से जब से टीवी चैनल शुरू हुए हैं, तब से सभी चैनलों पर कोई न कोई बाबा, साधु-संत, महंत या गुरु जीवन की शिक्षा देते दिखाई देते हैं. कुछ विशेष चैनलों पर, तो 24 घंटे सत्संग के साथ धर्मगुरु उपदेश देते रहते हैं, इसके बावजूद समाज में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है. इसकी वजह है इंटरनेट पर पोर्न साइट्स का होना. स्मार्टफोन की सुलभता की वजह से 10-12 साल के बच्चे भी पोर्न वीडियो ऑनलाइन देख रहे हैं. ये बच्चे स्त्री-पुरुष के रिश्तों की बारीकियों से परिचित नहीं होते हैं. यही वजह है कि रिश्ते बनाने के लिए सहमति न मिलने पर जबरदस्ती करने लगते हैं. यही जबरदस्ती हैवानियत में बदल जाती है. साधु-संतों और बाबाओं का इन पर कोई असर नहीं हो रहा.

-सत्य प्रकाश शिक्षक,
लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.

अधिकार नहीं, कर्तव्य पर जोर

हमारी भारतीय जीवन पद्धति में अधिकार से अधिक कर्तव्य को महत्व दिया गया है. अगर हम स्वयं मर्यादा के अनुरूप आचरण नहीं करते तो हमारे कथन का दूसरों पर प्रभाव नहीं पड़ता. राजनेता ईश्वर या सत्यनिष्ठा की शपथ लेकर संविधान के अनुरूप अपने दायित्व के निर्वहन करने की शपथ लेते हैं लेकिन क्या वास्तविक जीवन में वे वैसा करते हैं? सत्ता का दुरुपयोग कर संपत्ति अर्जित करने वालों को दंडित करने की जरूरत समय की मांग है. चाहे वे कितने भी ताकतवर और बड़े पद पर क्यों न हों. नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने और अच्छे दिनों की आशा में लोगों ने मतदान किया था. नीतीश का वादा था कि वे बिहार को एक सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाएंगे जिसे उन्हें पूरा करना चाहिए. नीतीश कुमार अभी से 2019 के एजेंडे पर कार्य कर रहे हैं और संघ मुक्त भारत बनाने की बात कर रहे हैं. लेकिन पहले नीतीश कुमार को बिहार को भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, जातिवाद मुक्त बनाना चाहिए जिसके लिए जनता ने उन्हें चुना है. नई पीढ़ी के लोग भी सब देख और सुन रहे हैं और नीतीश कुमार के बारे में अपनी एक धारणा बना रहे हैं. इसलिए नीतीश कुमार को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए. बिहार इस समय भ्रष्टाचार से सबसे अधिक त्रस्त है. शराबबंदी की तर्ज पर भ्रष्टाचार पर भी रोक लगनी चाहिए.

-अशोक निर्मोही, *दरभंगा, बिहार.*

जल ही जीवन है

कवर स्टोरी-विनाश की तरफ, पानी के पदचिन्ह (06 जून- 12 जून 2016)पढ़ा. बेहद प्रभावित किया. शशि शेखर ने बिल्कुल सही कहा है कि देश में पानी पर सिवाए मन की बात के और कोई चर्चा होती नहीं दिख रही है. पानी की बर्बादी रोकने के लिए हमें कड़े कदम उठाने होंगे. हमें बरसात के पानी को सहेजने की जरूरत है. अगर हम आज पानी नहीं बचाते हैं, तो आने वाले समय में और पानी की किल्लत होने वाली है. जिस प्रकार भूजल का दोहन हो रहा है, वह खरतनाक साबित होगा. जल ही जीवन है और जब जल ही नहीं बचेगा, तो जीवन कहां बचेगा. सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है, वह केवल बड़ी-बड़ी बातें करती है और बातों के सिवाय धरातल पर कुछ काम नहीं दिखता है. इसलिए हमें खुद जल को सहेजना और भविष्य के लिए बर्बाद होने से बचाना होगा.

-रामबिलास यादव, *गया, बिहार.*

जश्न में मशगूल सरकार

जब तोप मुकाबिल हो-प्रचार नहीं, लोगों का सपना पूरा कीजिए (06 जून- 12 जून 2016) में संतोष भारतीय ने सही कहा है देश का हर व्यक्ति इस जश्न में शामिल होना चाहता है, लेकिन जश्न में शामिल होने की परिस्थितियां अनुकूल नहीं दिखाई दे रही हैं और यह स्थिति हमारे लिए दुखदायी है. मोदी सरकार के दो साल बीत गए, लेकिन सरकार ने जो वादे किए थे, वे पूरे होते नहीं दिख रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो साल में कई योजनाओं की शुरुआत की, लेकिन उन योजनाओं का कोई असर धरातल पर नहीं दिख रहा है. सरकार दो साल पूरे होने पर जश्न मना रही है, वह किस बात का जश्न मना रही है? देश में किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, युवा रोजगार न मिलने से निराश हैं और देश के 13 राज्यों में भीषण सूखे की वजह से लोगों के पास पीने तक के लिए पानी नहीं है. लेकिन सरकार जश्न मना रही है और टेलीविजन, अखबार, रेडियो के माध्यम से प्रचार कर रही है. सरकार प्रचार के बजाए जनता से किए गए वादों को पूरा करे और उनकी समस्याएं को दूर करे.

-कौशलेंद्र मिश्रा, *भोपाल, मध्य प्रदेश.*

पाठकों से...

सुधी पाठक, चौथी दुनिया में प्रकाशित रिपोर्ट्स-आलेखों पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं. आप अपनी बेबाक राय, सुझाव हमें डाक/ईमेल द्वारा भेज सकते हैं. आप हमारी आंख-कान-नाक हैं. जहां तक आपकी पहुंच है, वहां तक हमारी नज़र जाना संभव नहीं है. अख़बार को बेहतर बनाने में आपके सुझाव-विचार हमारी मदद करेंगे. हमें आपके पत्रों की प्रतीक्षा रहेगी.

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11,
गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)-201301, उत्तर प्रदेश.
Email: feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

उत्तर प्रदेश में भाजपा का चेहरा कौन होगा

कौन होगा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जो पार्टी को नंबर दो या नंबर तीन की स्थिति से निकाल कर प्रथम श्रेणी में ला सके यानी चुनाव जिता सके. बहुत सारे नाम चर्चा में हैं और उत्तर प्रदेश में कई ऐसे लोग हैं जो अपना नाम आगे लाना चाहते हैं. सबसे पहला नाम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्या का सामने रखते हैं, लेकिन उनके हाथ में तो अभी उत्तर प्रदेश की पूरी कमान भी नहीं मिली है. इसलिए जैसे ही उनका नाम लेते हैं, वैसे ही हवा में कपूर की तरह उनका नाम गायब हो जाता है. वरुण गांधी की बहुत दिनों से ख्वाहिश थी और उन्होंने उत्तर प्रदेश में घूम-घूमकर अपने को स्थापित करने की कोशिश भी की, इलाहाबाद जैसी जगहों पर पोस्टर-बैनर भी लगे, लेकिन वरुण गांधी को संभवत: संघ नहीं चाहता और न भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता चाहते हैं. इसके बाद दिनेश जी का नाम आता है जो संघ से जुड़े हैं, लेकिन वे भी जनता के बीच के चेहरे नहीं हैं. इसलिए उन्हें भी किसी मुकाबले में नहीं माना जा सकता.

अब नाम बचता है योगी आदित्यनाथ और स्मृति ईरानी का. स्मृति ईरानी चूंकि अमेठी से चुनाव लड़ना चाहती हैं इसलिए उनका नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए उछालकर उनके समर्थक भविष्य में उन्हें उत्तर प्रदेश से लोकसभा में बड़े नेता के तौर पर पेश करना चाहते हैं ताकि वो स्मृति ईरानी के ग्लैमर के सहारे उन्हें राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान दिलवा सकें. लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद के लिए स्मृति ईरानी का नाम भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी हास्यास्पद बन गया है. सबसे गंभीर नाम योगी आदित्यनाथ का है. योगी आदित्यनाथ महंत अवैधनाथ के शिष्य हैं, जो कभी लोकसभा का चुनाव नहीं हारे. गोरक्षपीठ के अधीश्वर हैं वे भी लोकसभा का चुनाव कभी नहीं हारे. उन्होंने पूर्वांचल में हिंदू वाहिनी सेना बना रखी है जिसकी जनता में गहरी पैठ है, लेकिन जिसका अंतर्द्वंद्व हमेशा भारतीय जनता पार्टी से चलता रहता है. योगी आदित्यनाथ का व्यक्तित्व भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच सख्त किस्म का रहा है और पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जीत दरअसल मोदी के करिश्मे की जीत थी. उत्तर प्रदेश में उपचुनावों के दौरान योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद को मुद्दा बनाया था. उत्तर प्रदेश की जनता ने उनके इस नारे पर कोई ध्यान नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी को इसका कोई फायदा नहीं मिला. अगर योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बनते हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी पुरानी रणनीति पर चलने का फैसला करेगी. इसमें कार्यकर्ताओं की सोच होगी कि तेजी से धार्मिक ध्रुवीकरण हो और सारे हिंदू भारतीय जनता पार्टी की तरफ आएं. मुसलमानों को जिधर जाना हो, उधर जाएं.

राजनाथ सिंह के बारे में शुरू से अफवाहों के दौर चलते रहे. राजनाथ सिंह के बारे में जितनी भी अफवाहें रहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के भीतर से निकलीं, जिससे लोगों को ये लगा कि राजनाथ सिंह को दिल्ली में सत्ता चलाने वाले खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आस-पास के लोग, जिनमें वित्त मंत्री अरुण जेटली का नाम प्रमुख है, पसंद नहीं करते. अगर दिल्ली में मंत्रिमंडल का परिवर्तन हो चुका होता तब शायद स्थिति ज्यादा साफ होती. लेकिन राजनाथ सिंह मजबूरी में ही उत्तर प्रदेश आना चाहेंगे.

उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव और मायावती दो बड़े चेहरे हैं, जो लोगों के सामने अपनी बात खुलकर रखते हैं और उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश भी करते हैं. अब तक उत्तर प्रदेश में कमोबेश इन्हीं दोनों की सरकारें अदल-बदलकर बनती रही हैं. इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की वजह से प्रमुख प्रतिस्पर्धी के तौर पर सरकार बनाने की इच्छाशक्ति के साथ चुनाव में उतरना चाहती है. उसे अपने बीच ऐसा चेहरा तलाशना होगा जो मुलायम सिंह और मायावती की टक्कर का हो. ऐसे सिर्फ दो चेहरे भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, एक देश के गृहमंत्री राजनाथ सिंह और दूसरे राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह. कल्याण सिंह अपने को राजस्थान में बहुत सुरक्षित मानते हैं और वे राजस्थान की राजनीति के साथ घुल-मिल भी गए हैं. इसलिए वे शायद वहां से उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करने न आना चाहें. उत्तर प्रदेश के पिछड़े समाज के भीतर भारतीय जनता पार्टी के पास कल्याण सिंह का कोई विकल्प नहीं है. इसलिए उनका नाम उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करने वालों की चर्चा के दौरान बार-बार उछलता रहता है. राजनाथ सिंह देश के गृहमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सज्जन पुरुष हैं और इनके अलावा आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई दूसरा चेहरा दिखाई नहीं देता.

दरअसल राजनाथ सिंह के बारे में शुरू से अफवाहों के दौर चलते रहे. राजनाथ सिंह के बारे में जितनी भी अफवाहें रहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के भीतर से निकलीं, जिससे लोगों को ये लगा कि राजनाथ सिंह को दिल्ली में सत्ता चलाने वाले खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आस-पास के लोग, जिनमें वित्त मंत्री अरुण जेटली का नाम प्रमुख है, पसंद नहीं करते. अगर दिल्ली में मंत्रिमंडल का परिवर्तन हो चुका होता तब शायद स्थिति ज्यादा साफ होती. लेकिन राजनाथ सिंह मजबूरी में ही उत्तर प्रदेश आना चाहेंगे. उन्हें मालूम है कि उत्तर प्रदेश की लड़ाई कितनी कठिन है. अगर राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश आते हैं और वो यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने में अपने नेतृत्व की कुशलता साबित कर देते हैं, तो फिर राजनाथ सिंह को वैसा ही सम्मान मिलेगा जैसा नरेंद्र मोदी को देश का चुनाव जीतने के बाद मिला था.

दरअसल, उत्तर प्रदेश में सामाजिक वर्गों का भी एक गणित काम कर रहा है. ब्राह्मण कांग्रेस के साथ बुनियादी तौर पर रहा करता था, लेकिन ब्राह्मण समाज कांग्रेस के बाद मायावती के पास चला गया. पिछली बार ब्राह्मण समाज मायावती से हटकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ चला गया. इस बार फिर लगता है कि ब्राह्मण समाज का एक हिस्सा मायावती के पास जाएगा. उसे अब अपने लिए भारतीय जनता पार्टी में कोई आकर्षण नहीं दिखता. कलराज मिश्र उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के अकेले बड़े नेता हैं, लेकिन उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो स्थान मिला है, उससे ब्राह्मण समाज संतुष्ट नहीं है. पिछड़े वर्ग बड़े पैमाने पर मुलायम सिंह यादव, मायावती और भारतीय जनता पार्टी के बीच बंटे हैं. अब दो वर्ग बचते हैं जिनमें एक राजपूत हैं और दूसरे मुसलमान. मुसलमान समाज उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के साथ है, लेकिन पिछले दो-तीन साल से उनमें थोड़ी बेचैनी है. इस बेचैनी ने उत्तर प्रदेश चुनाव में किसी विकल्प के अभाव में कोई निश्चित तस्वीर नहीं बनाई है. जहां मायावती मुस्लिम उम्मीदवार देंगी, वहां मुसलमान मायावती के साथ जाएंगे लेकिन आम तौर पर मुसलमान मुलायम सिंह के साथ ही रहेंगे. यही राजनाथ सिंह के लिए सबसे कठिन परिस्थिति होगी. उन्हें ठाकुरों या राजपूतों का कितना साथ मिलेगा, यह भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन बाक़ी वर्गों को मायावती और मुलायम सिंह से तोड़कर अपने साथ लाना किसी युद्ध से कम नहीं है. इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के भीतर राजनाथ सिंह का अकेला ऐसा चेहरा है जिसे मुलायम सिंह और मायावती के समक्ष खड़ा किया जा सकता है और उत्तर प्रदेश के सामान्य वोटरों को कहा जा सकता है कि एक ईमानदार, अपेक्षाकृत कम साम्प्रदायिक, मृदुभाषी और सौम्य चेहरे वाला, नेतृत्व कर सकने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के पास है. भारतीय जनता पार्टी के लिए यह चुनाव जीने और मरने के समान है. अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के हर बूथ पर 20 से 30 लोगों की फ़ौज बनाने की मुहिम शुरू कर दी है. वैसे उन्होंने यह मुहिम बिहार में भी की थी, लेकिन वहां जो उम्मीदवार चुनाव जीते उन्हें कहीं यह फ़ौज बूथ लेवल पर नहीं दिखी. उत्तर प्रदेश में चूंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत दिनों से काम कर रही है, इसलिए हो सकता है कि इस बार उनकी बूथ सेना कुछ काम आए. पर सबसे बड़ा सवाल आखिर में फिर वही रह जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अगर कोई एक चेहरा नहीं हुआ तो यह सारी क़वायद धरी रह जाएगी. वैसे भारतीय जनता पार्टी चाहे तो बिहार जैसे प्रयोग को फिर दोहरा सकती है. वह उत्तर प्रदेश में किसी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार न घोषित करे और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाए. ■

editor@chauthiduniya.com

राज्यसभा किस लिए?

मेघनाद देसाई

राज्यसभा की सदस्यता के लिए नामांकन की होड़ एक अजीब दृश्य पेश करता है. आदर्श रूप से राज्यसभा को एक ऐसा सदन होना चाहिए जहां संविधान का संघीय (फेडरल) गुण नज़र आए. राज्यसभा के सदस्य उस राज्य के प्रतिनिधि होने चाहिए जिस राज्य का वे प्रतिनिधित्व कर रहे हों. अगर ऐसा हुआ तो लोकसभा वास्तव में एक राष्ट्रीय सदन बन जाएगी और उसके सदस्य संपूर्ण देश के लोगों के संदेश वाहक बन जायेंगे और राज्यों की ज़िम्मेदारी राज्यसभा के ऊपर छोड़ दी जायेगी.

कम से कम 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की यही मंशा थी. इस एक्ट के प्रावधान के मुताबिक कौंसिल ऑफ़ स्टेट ऐसा सदन था जिसमें देशी रियासतों को अपने प्रतिनिधियों को भेजना था, जबकि शेष ब्रिटिश इंडिया को अपने सदस्यों को निचले सदन के लिए चुनना था. चूंकि 1935 के एक्ट के संघीय भागों को कभी लागू नहीं किया गया, इसलिए मूल कौंसिल ऑफ़ स्टेट्स कभी वजूद में आया ही नहीं. इसके बावजूद स्वतंत्र भारत के संविधान में राज्यसभा को शामिल किया गया.

समय के साथ राज्यसभा, ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह विकसित हुई, जिसके सदस्य पार्टी नामांकन द्वारा चुने जाते हैं (उन सदस्यों को छोड़ कर जो एक स्वतंत्र प्रक्रिया द्वारा चुने जाते हैं). हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सदस्यों की संख्या की कोई अंतिम सीमा नहीं होती है. यह विसंगति ब्रिटेन के अलिखित संविधान के कारण पैदा हुई है. आम सहमति के मुताबिक, कोई भी पार्टी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बहुमत नहीं रख सकती, और यदि किसी बिल में संशोधन को लेकर हाउस ऑफ कॉमन्स के साथ कोई असहमति होती है तो ऐसे मामलों में हाउस ऑफ़ कॉमन्स का फैसला आखिरी होता है.

समय के साथ राज्यसभा, ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह विकसित हुई, जिसके सदस्य पार्टी नामांकन द्वारा चुने जाते हैं (उन सदस्यों को छोड़ कर जो एक स्वतंत्र प्रक्रिया द्वारा चुने जाते हैं). हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सदस्यों की संख्या की कोई अंतिम सीमा नहीं होती है. यह विसंगति ब्रिटेन के अलिखित संविधान के कारण पैदा हुई है. आम सहमति के मुताबिक, कोई भी पार्टी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बहुमत नहीं रख सकती, और यदि किसी बिल में संशोधन को लेकर हाउस ऑफ कॉमन्स के साथ कोई असहमति होती है तो ऐसे मामलों में हाउस ऑफ़ कॉमन्स का फैसला आखिरी होता है.

राज्यसभा की चुनावी प्रक्रिया उम्मीद के मुताबिक ही होती है. ज़्यादातर राज्यों में पार्टियों को मालूम होता है कि उनके कितने प्रत्याशी निर्वाचित हो सकते हैं. मामला वहां फंसता है जहां एक पार्टी को दूसरी पार्टियों से मामूली मदद की ज़रूरत होती है. जिस सीट पर पार्टी की जीत सुनिश्चित होती है वहां से ऐसे उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं, जिनकी संसद में उपस्थिति पार्टी के लिए ज़्यादा अहमियत रखती है.

अपने हस्तांतरित (वर्शीश्रींश) सांसदों के बावजूद ग्रेट ब्रिटेन एक संघ नहीं है. ब्रिटिश पीअरेज के सदस्य न तो अपने निवास स्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं और न ही अपने चुनाव क्षेत्र का. वे अपनी दूसरी योग्यताओं के कारण चुने जाते हैं. लेकिन भारत का उच्च सदन आदर्श रूप से अमेरिकी सीनेट जैसा है जिसके सदस्य राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं.

चुनावी आंकड़ों का पूर्वानुमान पार्टी नेतृत्व को अधिक शक्ति देता है. अजित सिंह को एक शक्तिशाली पार्टी के नेता की तलाश थी जो उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत करे, लेकिन वे भाग्यशाली साबित नहीं हुए. कपिल सिब्बल के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें पार्टी एक ऐसी सीट ही दे सकती थी जिसपर उन्हें दूसरों की मदद की ज़रूरत हो. जिन मंत्रियों के कार्यकाल समाप्त हो गए हैं उन्हें ऐसे राज्यों में भेज दिया गया है, जहां से वे आसानी से चुनाव जीत सकते हैं. वहीं दूसरी तरफ लालू यादव अपनी अनुभवहीन बेटी को राज्यसभा की सीट दे सकते हैं.

इसके लाभ भी हैं. डॉ. मनमोहन सिंह असम और राम जेठमलानी बिहार से राज्यसभा में जा सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह है कि राष्ट्रीय स्तर के व्यक्तित्व की उपस्थिति में असम और बिहार के हित को उतना महत्व हासिल नहीं होगा. दरअसल, यह कहा जा सकता है कि जो लोग चुनाव नहीं जीत सकते उनके लिए राज्यसभा संसद पहुंचने की गारंटी देता है. वहीं दोनों सदनों के पारस्परिक अधिकारों का मुद्दा सामने है. बहरहाल, ब्रिटेन में जिस तरह किसी बिल पर हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स के लिए हाउस ऑफ़ कॉमन्स का फैसला अंतिम होता है, उस तरह भारत में राज्यसभा के लिए लोकसभा का फैसला अंतिम नहीं होता. क्या यह ठीक है? ■

feedback@chauthiduniya.com

विकास कार्यों पर भारी पड़ रहे नक्सली

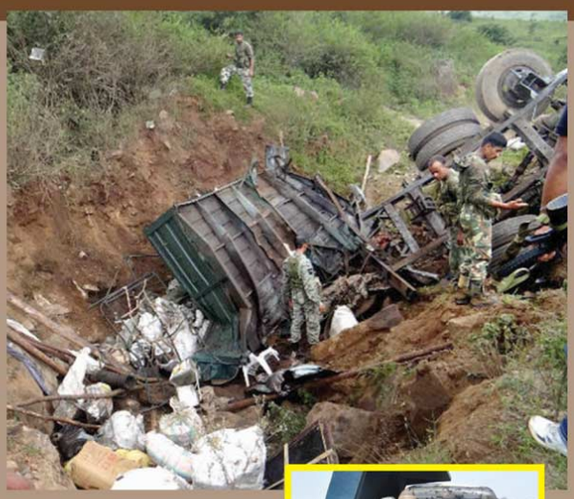

सुनील सौरभ

बिहार में प्रतिबंधित नक्सली संगठनों का कहर जा रही है. तमाम प्रयासों के बाद भी सुरक्षाबल नक्सलियों पर नकेल नहीं कस पा रहे हैं. सुरक्षाबलों को नक्सलियों पर कार्रवाई करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. नक्सली अपने सिद्धांतों को छोड़कर और आंतक फैलाकर लेवी वसूलने का धंधा करने लगे हैं. मगध के क्षेत्र में सड़क से लेकर अन्य विकास कार्यों का ठेका लेने वाली कम्पनियां इस नक्सलियों की सॉफ्ट टारगेट हैं जिसकी वजह से मगध की कई बड़ी परियोजनाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं. यही हाल तिरहुत और उत्तर बिहार के इलाकों का भी है.

पिछले कई वर्षों में कई नक्सली संगठनों ने निर्माण कार्य स्थलों पर कंस्ट्रक्शन कम्पनियों के बेस कैम्पों पर हमला कर लेवी वसूलने का काम किया है. अभी कुछ दिनों पहले ही प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई ने ठेके पर काम कर रहीं कम्पनियों के चार बेस कैम्पों पर हमला किया था और कम्पनियों को चेतावनी दी कि अगर लेवी नहीं दिया, तो काम नहीं होने दिया जाएगा. जबकि इस वर्ष के शुरुआत में ही पटना के जोनल आईजी कुंदन कृष्णानंद और गया की एसएसपी गरिमा मलिक ने कंस्ट्रक्शन कम्पनियों से जुड़े ठेकेदारों को सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया था. लेकिन अधिकारियों का यह आश्वासन कोई काम नहीं आया. गया जिले में विकास कार्यों में लगी ठेका कम्पनियों में नक्सलियों का भय व्याप्त है जिसकी वजह से कई योजनाएं अधूरी पड़ी हैं.

10 मई 2016 की रात गया जिले के बेलागंज-खिजसराय सड़क के कार्य में लगी बाबा हंस कंस्ट्रक्शन कम्पनी के बेस कैम्प पर हमला कर नक्सली संगठन पीएलएफआई ने चार हाईवा, दो अर्थमुहर, एक जीप, एक डीजल टैंक और तीन बाइक को फूंक डाला. इस हमले से कम्पनी को लगभग एक करोड़ का नुकसान हुआ है. इसी प्रकार 20 मई 2016 की रात गया जिले के डोभी थाना क्षेत्र के पीड़ासीन गांव में संचालित ईंट भट्टा पर नक्सलियों ने हमला किया और नक्सलियों ने 60 हजार रुपये की लेवी न देने पर ईंट-भट्टा के मुंशी, फायर मैन और मजदूरों की जमकर पिटाई की. इस घटना में भी प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई का ही हाथ था. इसी प्रकार 29 मई 2016 की रात डुमरिया से पटना तक जाने वाले राज्य मार्ग के निर्माण में लगी राकेश कंस्ट्रक्शन कम्पनी के कपसिया-मधुरापुर स्थित बेसकैम्प पर पीएलएफआई के नक्सलियों ने हमला कर कर्मचारियों की पीटाई की और लेवी न देने पर बेसकैम्प को उड़ाने की धमकी दी. 1 जून 2016 की रात नक्सलियों ने एक साथ दो स्थानों गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र एवं बांके बाजार थाना क्षेत्र में निर्माण कार्य में लगी कंस्ट्रक्शन कम्पनियों के बेस कैम्प पर हमला कर कई वाहनों को फूंक डाला. पीएलएफआई नक्सली संगठन ने बाराचट्टी थाना क्षेत्र के पतलुका पंचायत के इटवां गांव के पास सोभ-धनगाई रोड निर्माण में लगी रमिया कंस्ट्रक्शन कम्पनी के बेसकैम्प पर हमला कर 15 लाख रुपये की लेवी के रूप में मांग की. ज्ञात हो कि यह कम्पनी जमानत रिहा हुई एमएलसी मनोरमा देवी के पति बिंदेश्वरी प्रसाद यादव उर्फ बिंदी यादव की है. बिंदी यादव अपने बेटे के द्वारा एक युवक की हत्या के मामले में जेल में बंद हैं. नक्सलियों ने अपने छोड़े हुए पर्चे में कहा कि लेवी नहीं मिली, तो मोहनपुर थाना क्षेत्र के गणेशचक गांव में स्थित बिंदी यादव के घर को बम से उड़ा दिया जाएगा.

1 जून की रात को ही बांके बाजार थाना क्षेत्र के खजूरिया गांव स्थित पुल निर्माण में लगी ठेका कम्पनी के अस्थायी कैम्प को पीएलएफआई के नक्सलियों ने केन बम से विस्फोट कर उड़ा दिया. कैम्प को उड़ाने के बाद नक्सलियों ने कम्पनी के मिक्सर मशीन और एक जेनरेटर को आग के हवाले कर दिया. घटना को अंजाम देने के पूर्व मंडावर नदी पर पुल निर्माण में लगी कंस्ट्रक्शन कम्पनी के मजदूरों को नक्सलियों ने अपने कब्जे में ले लिया और उनके हाथ-पांव बांध दिए. बाद में नक्सलियों ने काम बंद करने की चेतावनी देकर मजदूरों को छोड़ दिया. इससे पहले परैया थाना क्षेत्र में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के द्वारा 60 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण किया जा रहा है. पुल निर्माण का काम राकेश कंस्ट्रक्शन कम्पनी कर रही है. नक्सलियों ने लेवी न देने पर पुल का निर्माण कार्य बंद रखने चेतवानी दी है.

हाल के दिनों में माओवादियों से जुड़े नक्सली संगठन पीएलएफआई बहुत तेजी से गया जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सक्रिया हुआ है. पीएलएफआई ने अपने हथियारबंद दस्ते को मजबूत करने के लिए आतंक फैलाने का काम शुरू कर दिया है. नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों में लगीं कंस्ट्रक्शन कम्पनियों की मुश्किल यह है कि कई तरह के नक्सली संगठनों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है. किसी भी नक्सली संगठन के द्वारा विकास कार्यों में 10 से 20 प्रतिशत तक लेवी वसूली जाती है. कम्पनियों की परेशानी यह है कि एक संगठन को मैनेज करती हैं, तो दूसरी ओर दूसरे संगठन के द्वारा भी लेवी वसूलने का कार्य किया जाता है. नक्सलियों के विकास विरोधी रवैये और लेवी वसूलने की वजह से ठेके पर काम करने वाली कई कंस्ट्रक्शन कम्पनियां कार्य छोड़कर बिहार से चली गई हैं. सुरक्षाबलों की स्थिति भी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अच्छी नहीं है. सुरक्षाबलों के तमाम प्रयासों के बावजूद कंस्ट्रक्शन कम्पनियों को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है. जोनल आईजी कुंदन कृष्णानंद ने ठेके पर काम कर रहीं कंस्ट्रक्शन कम्पनियों से कहा था कि आप सब को डरने की कोई जरूरत नहीं है. सुरक्षा के तमाम उपाय किए जा चुके हैं और आप लोग निडर होकर कार्य करें. लेकिन पुलिस-पदाधिकारियों का यह आश्वासन हवा-हवाई साबित हुआ. हाल में हुई घटनाओं के बाद सभी क्षेत्रों में काम बंद है. वहीं नक्सली अपनी सफलता पर जगह-जगह जश्न मनाने में लगे हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

राजगीर की पहचान गर्म कुंड का अस्तित्व संकट में

गंगा-यमुना कुंड की धार हुई बंद

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

अन्तरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर पूरी दुनिया में अपने प्राकृतिक रूप और ऐतिहासिक महत्व के लिए चर्चित रहा है. कभी दुनिया के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध की राजधानी होने का गौरव राजगीर को प्राप्त है. राजगीर की एक महत्वपूर्ण पहचान गर्म जल का कुंड भी है. इस गर्म जल कुंडों की मान्यता यह है कि इसमें कुछ दिनों तक लगातार स्नान कर लेने से कैसा भी चर्म रोग हो ठीक हो जाता है. ठंड के मौसम में देश के विभिन्न हिस्सों से पर्यटक आते हैं और इस गर्म जल कुंड में स्नान का आनंद उठाते हैं. पर्यटन के मौसम में हजारों की संख्या में विदेशी पर्यटक भी राजगीर आकर गर्म जल के कुंड में स्नान का आनंद लेते हैं. राजगीर प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक धरोहर एवं गर्म जल के कुंड की वजह लोगों

के आकर्षण का केंद्र है. ऐसे तो पूरे वर्ष देश और विदेश से लाखों पर्यटक आते रहते हैं, लेकिन ठंड के मौसम में अधिक संख्या में पर्यटक राजगीर आते हैं. पश्चिम बंगाल के पर्यटक सबसे अधिक राजगीर आते हैं और पहले यह पर्यटक महीनों राजगीर में रहकर स्वास्थ्य लाभ उठाया करते थे. पश्चिम बंगाल के समृद्ध परिवारों ने राजगीर में अपने बंगले भी बनवाए थे और उसी में आकर रहते थे. पहले राजगीर में होटल नहीं थे. केवल एक या दो धर्मशाला थे.

लेकिन आज राजगीर की पहचान गर्मकुंड का अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है. ब्रह्मकुंड परिसर में स्थित गंगा-यमुना कुंड की धार पूरी तरह बंद हो गई है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों के साथ-साथ वहां का पंडा समाज भी काफी परेशान और चिंतित है. जबकि पहले इन दोनों कुंडों में मोटी धार बहती थी और लोग उसमें स्नान करते थे. गर्म कुंड पर भी खतरा मंडराने लगा है. अनंत कुंड, मार्कंडेय कुंड, व्यास कुंड और सप्तधारा सहित अन्य कुंडों की धार भी प्रभावित हो गई है. राजगीर के युवा समाजसेवी अनूप दांगी बताते हैं कि पाण्डु पोखर स्थित सात बोरिंग हुई है जिससे पानी निकाला जा रहा है. इसी वजह से कुंड की धारा प्रभावित हो रही है और गंगा-यमुना कुंड की धार बंद हो गई है. जबकि पाण्डु पोखर स्थित बोरिंग से पानी न निकालने की हिदायत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद पोखर से पानी निकाला जा रहा है. उन्होंने बताया कि पाण्डु पोखर की बोरिंग को बंद नहीं किया गया तो राजगीर के इस विश्व प्रसिद्ध धरोहर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा.

गर्म पानी के इस कुंड की वजह से ही राजगीर की विश्व स्तर पर पहचान है. हालांकि नालंदा के जिला पदाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस मोहनराम ने बताया कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पाण्डु पोखर की एक बोरिंग बंद कर दी गई है. वैकल्पिक व्यवस्था करने के बाद अन्य बोरिंग भी बंद कर दी जाएगी. लेकिन मामला जब बहुत ज्यादा गंभीर होने लगा तो राज्य सरकार ने जल संसाधन एवं पीएचईडी के उच्च अधिकारियों और अभियंताओं को निरीक्षण करने के लिए राजगीर भेजा. इन अधिकारियों ने उन सभी कुंडों का निरीक्षण किया, जो सूख गए हैं या जिनका जल स्तर कम हो चुका है. इन अधिकारियों ने बंद पड़ी धाराओं को भी देखा और इस पर चिंता जाहिर की. जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने निरीक्षण के बाद बताया कि गर्म जल के चार कुंडों की धाराएं बंद हो गई हैं. यह धाराएं क्यों बंद हो गई हैं, उसकी पड़ताल की जा रही है. जांच के बिना यह कहना मुश्किल है कि पाण्डु पोखर पार्क की बोरिंग की वजह से यह समस्या खड़ी हुई है या जल स्तर नीचे जाने की वजह से. उन्होंने सेंट्रल ग्राउंड वाटर की टीम से भी बंद पड़े कुंडों का सर्वेक्षण कराने की बात कही. साथ ही वैभार गिरि पर्वत पर स्थित भेलवा डोही तालाब को देखने और गंधक की कितनी मात्रा है उसका भी पता लगाने को कहा है. इस मामले को लेकर नालंदा जिला प्रशासन भी गंभीर है और विशेषज्ञों की एक टीम बनाकर कुंडों की धार बंद होने की वजहों को पता करने में लगा है. गर्म जल के कुंडों के बंद होने से विदेशी पर्यटक भी चिंतित हैं. बोधगया आए म्यामार के प्रोफेसर दोपा और प्रोफेसर कुंछाग को जब जानकारी मिली कि राजगीर में गर्म जल कुंड की धारा बंद हो गई है, तो दोनों लोग राजगीर पहुंचे. उन्होंने कुंड का निरीक्षण करने के बाद बताया कि यह प्रकृति से छेड़छाड़ का परिणाम है जिसकी वजह से जल के गर्म कुंड की धारा बंद हो गई है. राजगीर स्थित गर्म जल कुंडों की धारा बंद होने की वजह से पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों में भी निराशा है.■

Mob. : 9386745004, 9204791696
www.iiher.org,
Email : anilsulabh6@gmail.com

INDIAN INSTITUTE OF HEALTH EDUCATION & RESEARCH
Health Institute Rd, Beur (Near Central Jail), Patna -2.
(Recongnised by Govt. of Bihar, RCI, Govt. of India, IAP & ISPO)
AFFILIATED TO MAGADH UNIVERSITY, BODHGAYA

POST GRADUATE COURSES :

Name of Courses		Eligibility	Duration
MPT	Master of Physiotherapy	BPT	2yrs.
MOT	Master of Occupational Therapy	BOT	2yrs.
DEGREE COURSES			
BPT	Bachelor of Physiotherapy	I.Sc (Bio)	4yrs.+6 Months of Internship
BOT	Bachelor of Occupational Therapy	I.Sc (Bio)	4yrs.+6 Months of Internship
BPO	Bachelor of Prosthetic & Orthotic	I.Sc	4yrs.+6 Months of Internship
BASLP	Bachelor of Audiology & Speech Language Pathology	I.Sc	3yrs.+1 year of Internship
BMLT	Bachelor of Medical Laboratory Technology	I.Sc	3yr.+6 Months of Internship
BMRIT	Bachelor of Radio Imaging Technology	I.Sc	3yrs.+6 Months of Internship
B.Ophth.	Bachelor of Ophthalmology	I.Sc	4yr.+6 Months of Internship
B.Ed.	(Special Education)	Graduate	1yr.
1 YEAR ABRIDGED DEGREE FOR DPT / DOT			
DIPLOMA COURSES :			
DPT	Diploma In Physiotherapy	I.Sc (Bio)	3yrs.+6 Month of Internship
D-X-Ray	Diploma In X-Ray Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DMLT	Diploma In Medical Laboratory Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DECG	Diploma In E.C.G.	I.Sc (Bio)	2yr.
DOTA	Diploma In O.T. Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DHM	Diploma In Hospital Management	Graduate	1yr.
CMD	Certificate in Medical Derssing	Matirc with Science & English	1yr.

ADMISSION OPEN

Form & Prospectus -
Can be obtained from the office against a payment of Rs. 500/-. only by cash. Send a DD of Rs. 550/- only in the favour of Indian Institute of Health Education & Research, Patna, for postal delivery.

डॉ. अनिल सुलभ
निदेशक प्रमुख

दालकोला चेक पोस्ट पर करोड़ों के राजस्व की चोरी

नीरज सिंह

शराबबंदी की वजह से बिहार को पहले ही चार हजार करोड़ रुपये के उत्पाद राजस्व से वंचित होना पड़ रहा है. दूसरी ओर बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित चेक पोस्ट के माध्यम से बिहार सरकार को प्रत्येक महीने करोड़ो रुपये के राजस्व का चुना लगाया जा रहा है. दालकोल चेक पोस्ट समेत पश्चिम बंगाल से जुड़े सीमांचल के अलग-अलग इलाकों से कई राज्यमार्ग गुजरते हैं. इन राज्यमार्गों पर विभागीय कर्मी एवं इंट्री माफियाओं की मिलीभगत से करोड़ों की लूट हो रही हैं. वाणिज्य कर परिवहन, उत्पाद, खनन एवं वन समेत कई तरह के राजस्वों की चोरी को रोकने के लिए बिहार सरकार ने पश्चिम बंगाल से लगने वाली अन्तर्राज्यीय सीमा दालकोला में 2007 में जांच चौकी(चेक पोस्ट) का निर्माण कराया था. उपरोक्त विभाग से संबंधित कर्मियों को सरकारी राजस्व वसूलने के लिए इस कार्य में लगाया गया, लेकिन ठीक इसके विपरीत विभागीय कर्मियों, अधिकारियों एवं इंट्री माफियाओं के द्वारा सरकार को हर महीने मिलने वाले राजस्व के रूप करोड़ों रुपये का चुना गया जा रहा है. सीमांचल के पूर्णियां, कटिहार, किशनगंज एवं अररिया जिले की सीमा अन्तर्राज्यीय के साथ अन्तरराष्ट्रीय सीमा से भी लगती है. यह पूर्वोत्तर राज्यों का प्रवेश द्वार भी कहलाता है.

यहीं से राष्ट्रीय मार्ग 31, 57 एवं 327ई राज्य मार्ग गुजरता है. इन्हीं मार्गों के माध्यम से ट्रकों के द्वारा वस्तुओं की आवाजाही पुर्वोत्तर, पश्चिम बंगाल, नेपाल समेत बंग्लादेश तक होती है. असम का कोयला, चायपत्ती, पश्चिम बंगाल से धनिया, सरसो तेल, चॉकलेट, रेडीमेड कपडों समेत कई वस्तुओं का आना दालकोला चेकपोस्ट के माध्यम से ही बिहार में होता है. इनमें से अधिकतर ट्रक अररिया एवं जोगबनी होते हुए नेपाल भी जाते हैं. राज्य मार्ग 327ई पश्चिम बंगाल की चक्कमारी से बिहार के गलगलिया(किशनगंज) में प्रवेश करता है और अररिया में फोरलेन राष्ट्रीय मार्ग 57 में मिल जाता है.

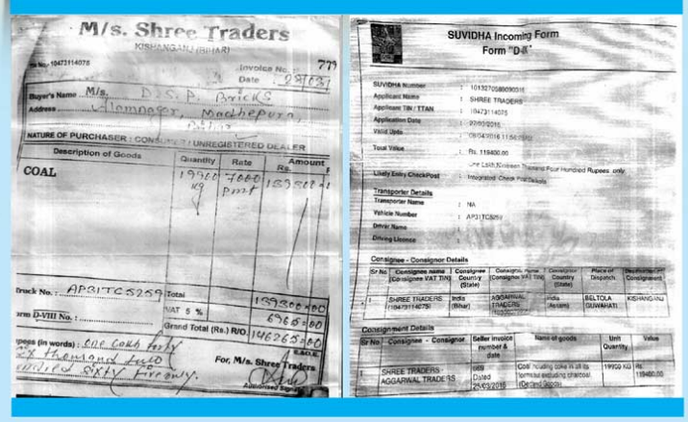

गुलाबबाग के एक व्यवसायी ने बताया कि हम लोंगों की सेटिंग चेक पोस्ट के वाणिज्य कर विभाग से है जिससे सामान को लेकर आसानी से चेक पोस्ट पार कर लिया जाता है. वहीं काला पत्थर, कोयला, स्टील सीट आदि जैसे सामान रात के अंधेरे में चेक पोस्ट पार कर अपने स्थानों तक पहुंच जाते हैं.

इस राज्यमार्ग से दिल्ली समेत अन्य राज्यों से सामान पश्चिम बंगाल होकर पूर्वोत्तर के राज्यों तक पहुंचता हैं. राज्य मार्ग 327ई पर अक्सर ओवरलोडेड ट्रकों को देखा जा सकता है जिसे बिहार में पास कराने को लेकर चक्कमारी में इंट्री माफियों का ग्रुप सक्रिय रहता है. ठाकुरगंज एवं बहादुरगंज में सैकड़ों ईंट भट्ठे हैं. जहां से ओवरलोडेड ट्रकों के द्वारा ईटों को सिल्लीगुड़ी, दार्जिलिंग समेत पूर्वोत्तर के राज्यों तक भेजा जाता है. ईंटों से भरे ओवरलोडेड ट्रकों का संचालन स्थानीय थानों की मदद से वर्षों से चल रहा था. लेकिन वर्तमान में पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्र के द्वारा थानेदारों के ऊपर सख्त तेवर की वजह से इस धंधे पर कुछ हद तक लगाम लगी है. गलगलिया में राज्य मार्ग 327ई पर कोई चेकपोस्ट नहीं है और दालकोला में चेक पोस्ट है. दालकोला चेक पोस्ट पर इंट्री माफियाओं का जमावड़ा शाम होते ही बढ़ने लगता है जिसका मुख्य केंद्र वाणिज्य कर विभाग रहता है. इनमें से कई ऐसे इंट्री माफिया हैं जिन पर दर्जनों मामले पूर्णियां के बायसी, डगरूवा, पूर्णियां सदर समेत कई थानों में दर्ज हैं, लेकिन पुलिस द्वारा उनके खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है. विगत वर्षों में दर्जनों ऐसे इंट्री माफिया हैं जो अधिकारियों की मिलीभगत से मालामाल हो चुके हैं. राज्य मार्ग 327ई अररिया, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, होते हुए गलगलिया के रास्ते दार्जिलिंग जिले में मिलता है. इस पथ पर पश्चिम बंगाल सीमा के पास कोई चेक पोस्ट नहीं है और इसी मार्ग पर बड़े पैमाने पर इंट्री टैक्स की चोरी होती है. वहीं दालकोला में चेक पोस्ट होने के बावजूद दिन के उजाले से लेकर रात के अंधेरे में वाणिज्य कर चोरी होती है. यहां चिप्स स्टोन, हार्डवेयर, चायपत्ती, स्टील, पलास्टिक, वनस्पति तेल, समेत अनेक सामानों पर टैक्स की चोरी होती है. सिलिगुड़ी, कोलकाता एवं मालदा से बिहार आने वाली अधिकांश बसों की छतों पर चायपत्ती, दालमोट, चॉकलेट, बिस्कुट, हार्डवेयर, प्लास्टिक, श्रृंगार प्रसाधन, धनियां, इलायची, मसाले समेत कई तरह के सामान लदे होते हैं. इस बारे में नाम न छापने की शर्त पर गुलाबबाग के एक व्यवसायी ने बताया कि हम लोंगों की सेटिंग चेक पोस्ट के वाणिज्य कर विभाग से है जिससे सामान को लेकर आसानी से चेक पोस्ट पार कर लिया जाता है. वहीं काला पत्थर, कोयला, स्टील सीट आदि जैसे सामान रात के अंधेरे में चेक पोस्ट पार कर अपने स्थानों तक पहुंच जाते हैं. पुर्णिया के गुलाबबाग, कटिहार, अररिया, जोगबनी एवं फारबिसगंज में दर्जनों ऐसे ट्रांसपोर्टर हैं जिनके गोदामों में सामान को रात में ही उतार लिया जाता है. यहां तक कि गुलाब बाग के पीएस कोल्ड स्टोर को भी गोदाम का रूप दे दिया गया है. इसी प्रकार की राजस्व चोरी के एक मामले की जानकारी(डॉक्यूमेंट) चौथी दुनिया को मिली है. चौथी दुनिया को जो डॉक्यूमेंट मिला है उसके अनुसार श्री ट्रेडर्स किशनगंज टिन नंबर 10473114075 इनवॉयस नंबर 779, ट्रक नंबर AP31TC5259 के द्वारा दिनांक 28.03.2016 को 19,900 किलोग्राम कोयला डी.एस.पी ब्रिक्स आलमनगर मधेपुरा को भेजा गया. जिसका कुल मूल्य 7000 रुपये प्रति मैट्रिक टन की दर से 1,39,300 रुपये हुआ और इसका वैट चार्ज 5 प्रतिशत की दर 6,965 रुपये हुआ. इस तरह से इनवॉयस में कुल 1,46,265 रुपये दर्ज हैं. इनवॉयस पर फार्म डी-8 का नंबर नहीं है. दूसरी तरफ इनटिग्रेटेड चेक पोस्ट दालकोला के वाणिज्य कर विभाग द्वारा जो सुविधा इनकमिंग फार्म डी-9 पर निर्गत किया गया है उसमें आवेदक का नाम श्री ट्रेडर्स सुविधा नंबर 1013270589090316, टीन नंबर 10473114075, आवेदन की तिथि 27.03.2016, वैलिडिटी दिनांक 08.04.2016, गुड्स कोयला, कुल मात्रा 19,900 किलोग्राम और कीमत 1,19,400 रुपये दर्ज है. कनसिजनर का नाम अग्रवाल ट्रेडर्स, टीन नंबर 18300079220, इनवॉयस नंबर 669 दिनांक 25.03.2016, डिसपैच स्थान बेलटोला गुवाहाटी असम और कनसिजनी का नाम श्री ट्रेडर्स किशनगंज का उल्लेख है. फार्म डी-9 में ट्रांसपोर्टर, ड्राइवर, लाइसेंस का स्थान खाली है जबकि ट्रक संख्या AP31TC5259 है. यहां वाणिज्य कर की चोरी को लेकर जो सवाल खड़ा हो रहा है वह अपंजीकृत डीलर श्री ट्रेडर्स के इनवॉयस पर 19,900 किलोग्राम कोयले का मूल्य 1,39,300 रुपये और 5 प्रतिशत इंट्री टैक्स जोड़ने पर 1,46,265 रुपये का उल्लेख है, तो वहीं सुविधा इनकमिंग डी-9 पर 19,900 किलोग्राम कोयले का मूल्य 1,19,400 रुपये वाणिज्य की तरफ से दिखाया गया है. इसे देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि चेकपोस्ट पर विभागीय और इंट्री माफियाओं की मिलीभगत से राजस्व की चोरी का खेल चल रहा है. इस संबंध में जब हमने दालकोला चेकपोस्ट पर तैनात प्रभारी डीसी प्रेम रंजन से बात करने की कोशिश की तो वह अपने सहयोगियों का साथ हमसे ही उलझ पड़े. परिवहन विभाग के कर्मियों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ. पूर्णिया स्थित वाणिज्य कर उपायुक्त से कई बार इस संबंध में बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी.■

M/s. Shree Traders
KISHANGANJ (BIHAR)
Invoice No. 779
Date 28/03/16
Buyer's Name M/s. D.S.P. Bricks
Address Alamnagar, Madhepura
NATURE OF PURCHASER : CONSUMER / UNREGISTERED DEALER

Description of Goods	Quantity	Rate	Amount Rs.
COAL	19900 kg	7000 PMT	139300.00

Truck No. : AP31TC5259 — Total 139300.00
VAT 5 % — 6965.00
Form D-VIII No. : — Grand Total (Rs.) R/O. 146265.00
Rupees (in words) : one lakh forty six thousand two hundred sixty five only.
For, M/s. Shree Traders
Authorised Signatory

SUVIDHA Incoming Form
Form "D-9"
Applicant Name: SHREE TRADERS
Applicant TIN / TAN: 10473114075
Transporter Details
Consignee - Consignor Details

Sr No	Consignee name (Consignee VAT TIN)	Country (State)	Consignor name	Country (State)	Place of Dispatch	Destination
1	SHREE TRADERS (10473114075)	India (Bihar)	AGGARWAL TRADERS	India (Assam)	BELTOLA GUWAHATI	KISHANGANJ

Consignment Details

Sr No	Consignee - Consignor	Seller invoice number & date	Name of goods	Unit Quantity	Value
1	SHREE TRADERS - AGGARWAL TRADERS	669 Dated 25/03/2016	Coal including coke in all its forms but excluding charcoal (Declared Goods)	19900 KG	Rs. 119400.00

feedback@chauthiduniya.com

समस्या आपकी समाधान Dr. Advice से

प्रश्न : डॉ. साहब मेरी उम्र 62 साल की है। उठने बैठने में काफी परेशानी होती है, जोड़ों में अकड़न रहता है। कोई आर्युवेदिक दवा बतायें। दीनानाथ सिंह, रांची

उत्तर : आप REPL निर्मित ऑर्थोविट कैप्सूल एक कौप्सूल सुबह और एक कैप्सूल रात को सोते सम लें और ऑर्थोविट ऑयल से प्रभावित जोड़ों की मालीश करें काफी लाभ होगा।

प्रश्न : मेरी उम्र 21 वर्ष है, काम क्रीड़ा में जबरदस्त उल्लास उठता है। मगर स्पर्श मात्र से ही स्खलित हो जाता हूँ। अंग भी छोटी है-मैं क्या करू? प्रभात, औरंगाबाद

उत्तर : गलत संगत या बुरी आदत के कारण अक्सर ये सब होता है। आप अपने काम पर ध्यान दें और विगोरा 2000 की 7 शीशी का कोर्स करें और विगोरा ऑयल से मालिश करें, निश्चित फायदा होगा।

प्रश्न : मेरी उम्र 32 वर्ष है कुछ दिनों से शिघ्रपतन से परेशान हूँ और एक बार सम्बन्ध स्थापित करने के बाद दोबारा मन नहीं करता और आलस्य बना रहता है। अरूण सिन्हा, नोयडा

उत्तर : आप REPL निर्मिता विगोरा 5000 दिन में 3 बार) कप पानी में लें और विगोरा ऑयल से अंग पर मालिस करें। आपकी परेशानी दूर हो जायेगी।

प्रश्न : मैं 42 वर्षीय दो बच्चों का पिता हूँ मेरी समस्या यह है कि मुझे पत्नी से सहवास की इच्छा नहीं होती। यदि होती है तो मुश्किल से 15 सेकेन्ड के लिए। मैं क्या करू? शंकर तिवारी, गुरगांव

उत्तर : बढ़ती उम्र में अक्सर ऐसा होता है। तनाव, भागदौड़ एवं किशोरावस्था की गलती बहुत से कारण हो सकते हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है आप विगोरा हाई पावर का 90 दिन का कोर्स करें एवं हाई पावर मुसली ऑयल से दिन में दो बार मालिश करें। निश्चित फायदा होगा।

प्रश्न : उम्र 64 वर्ष है। संभोग की तिव्र इच्छा होती है मगर शिशन में कोई हरकत नहीं होती है। इसलिए मन मारकर रह जाता हूँ। सुनील मेहरा वर्धमान

उत्तर : इस उम्र में ऐसा होता है। आप विगोरा 5 X का 5 शीशी का कोर्स करें और साण्डह ऑयल से दिन में दो बार मालिश करें।

प्रश्न : डॉ. साहब मैने टी.वी. पर विज्ञापन देखकर वासनोउत्पति के लिए एक हलवा तरह की दवा मंगवाया उस दवा से फायदा तो कुछ नहीं हुआ उलटा पूरी रात सिर दर्द से छटपटाता रहा। कोई आर्युवेदिक और हानिरहित दवा बताएं। ईश्वरी राय, गाजियाबाद

उत्तर : ईश्वरी जी, कुछ दवा निर्माता बड़े-बड़े विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं को अपने भ्रम जाल में फंसाते हैं और अपने दवा में सिर्फ सिल्डेनाफी मिलाकर बेचते हैं जो शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। मेरे सुझाव से आप REPL निर्मित सुपर सोनिक कैप्सूल समय से दो घंटा पहले लें। यह दवा पूर्णतः आर्युवेदिक है एवं इसका कोई भी साइड इफैक्ट नहीं है।

प्रश्न : मैं 24 वर्षीया एक अविवाहित युवती हूँ मेरे स्तनों का विकास अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। जिससे मैं काफी परेशान रहती हूं, आशा है कि आप मुझे सही मार्गदर्शन करायेंगे। स्नेहलता वर्मा, नोयडा।

उत्तर : स्तनों का का संपूर्ण विकास नहीं होने के अनेक कारण हैं, जैसे हार्मोन्स की कमी अनुवांशिक। आप चिन्ता मन से निकाल दें एवं REPL का Breastrim Oil स्तनों पर सुबह-शाम दिये गये निर्देश के अनुसार 3 माह तक मसाज करें। इसके नियमित इस्तेमाल से स्तन में उभार आयेगा एवं आप आकर्षक नजर आयेंगी।

प्रश्न : मैं 36 वर्षीय विवाहित स्त्री हूँ पिछले एक वर्ष से पानी गिरने की समस्या है और मेरी जननांग भी काफी ढीली हो गई है। कोई हानिरहित उपचार बतायें। आभा दिल्ली।

उत्तर : आभा जी आप विगोरा 1000 दिन में 2 बार 15-15 बूँद आधा कम पानी मिलाकर पियें और Virgin Oil का अंदरूनी हिस्से पर लगाएं। यह बिल्कूल ही हानिरहित दवा है।

प्रश्न : मैं 38 वर्षीय पुरूष हूँ। समस्या यह है कि शरीर में हर वक्त आलस बना रहता है काम में भी मन नहीं लगता है एवं सहवास की भी इच्छा नहीं होती है। कोई आयुर्वेदिक दवा बताये। शम्भु सिंह, देहरादून

उत्तर : शम्भु जी! आप हाईपावर मुसली कैप्सूल का 1 कैप्सूल प्रत्येक दिन रात में सोते वक्त दूध के साथ लें और हाई पावर मुसली ऑयल दो बार 45 दिनों तक इस्तेमाल करें आपके शरीर में शक्ति आयेगी एवं आलस भी दूर रहेगा।

चिकित्सीय परामर्श के लिए स्वपता लिखित डाक लिफाफा, निम्न पते पर भेजें : REPL प्लाजा, तीसरा तल्ला फेडरल, पटना - 801505

Contact : 9304792851,9386880107 & 0612-2251189, (10 AM to 5 PM)
E-mail : customercare@replpharma.com, Visit us at : replpharma.com

डिस्ट्रीब्यूटर: दिल्ली/हरियाणा/पंजाब : निशा मेडिकोज 8860206755, 9988532909, जयपुर: आर.के. डिस्ट्रीब्यूटर 0141-2315071, उत्तर प्रदेश-कानपुर : खरया मेडिकल एजेंसी 0512-2372347, 9415127822, मुगलसराय: प्रकाश होमियो स्टोर 253078, मध्य प्रदेश-जबलपुर : मनीष फार्मा 0761-4004863, 9425157379, छत्तीसगढ़-भिलाई : सिंह होमियो हॉल 0788-403828, 9302839666, रायपुर : जर्मन होमियो 0771 4095630, बिहार: मॉर्डन डिस्ट्रीब्यूटर 9304018193, नॉर्थईस्ट आसाम- बोरिक होमियो रेमेडिज 03672 225340, 09435061793, पश्चिम बंगाल : एम एस ट्रेर्डस 9903175579, देव मार्केटिंग 033-30221018, सिलिगुड़ी : कलकत्ता होमियो 9593313011, झारखंड: सिंघानियां डिस्ट्रीब्यूटर 9431164318, उड़ीसा-भुवनेश्वर डायनेमिक होमियो हॉल 9437110810 कर्नाटक -विजापुर 9341610592 गुलवर्गा:9343834519

डायबिटिज से रहता है किडनी आंख और हृदयरोग का खतरा

ariskon Pharma Pvt.Ltd
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.
रमजान की आप सभी को हार्दिक बधाई

डॉ. इरशाद आलम (MD)
General Physician, BEGUSARAI

अलसिफा मल्टी स्पेशलिटि हॉस्पीटल बेगूसराय के डॉ. इरशाद आलम ने वर्तमान समय में लोगों के लाइफ स्टाइल के बारे में बात करते हुए चिंता जाहिर की। उन्होंने बताया कि आजकल मधुमेह रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। भारत में करीब 5 करोड़ से अधिक लोग इससे पीड़ित हैं इसके लक्षणों में डॉ. इरशाद ने बताया कि ज्यादा प्यास लगना, भूख ज्यादा लगना, पैर के घुटना से नीचे दर्द रहना, थकावाट महसूस होना। रात के समय पेशाब ज्यादा महसूस होना।

उपरोक्त लक्षणों में एक भी यदि आप महसूस कर रहे हैं तो आप तुरन्त नजदीकी डॉक्टर से मिलें। इसके कारणों पर चर्चा करते हुए डॉ. इरशाद आलम ने बताया कि यह जेनेटिक अर्थात बाप-दादा से तो होता ही है साथ ही एक कारण ब्लडप्रेशर की दवाईयां लेना भी है। लेकिन आज के दौर में इसकी मुख्य वजह आज का लाइफ स्टाइल है। हार्ड वर्किंग नहीं करना तथा शरीर से पसीना नहीं निकलना, इसकी वजह हो सकती है। ज्यादा टी.वी. देखना और सिटिंग जॉब लाइफ स्टाइल वाले लोगों को भी मधुमेह होने का खतरा होता है। शरीर में कई ऑर्गन होते हैं उसमें एक है पेनक्रियाज है जिसका काम पर्याप्त मात्रा में इन्सूलिन डिस्चार्ज करना होता है जब इन्सूलिन सही मात्रा में डिस्चार्ज नहीं होता है तो डायबिटिज या मधुमेह होता है। ज्यादा जंक फूड खाने वाले और मोटे व्यक्तियों में यह ज्यादा पाया जाता है। मधुमेह वाले रोगियों को आंख, किडनी, और हार्ट रोग का खतरा ज्यादा रहता है। यदि किन्हीं को बी.पी. है तो उसे सामान्य रखने का प्रयास करें। क्योंकि बी.पी. और सुगर का प्रभाव हृदय पर पड़ता है। इसलिए संदेह होने पर बी.पी. सुगर की जांच नियमित करायें तथा अपने लाइफ स्टाइल को अवश्य सुधारें ■ -भारती

URSLIV Tab. Ursodeoxycholic Acid 300 mg
Carbo - XT Ferrous Ascorbate with Folic Acid Tab.
AREX Dextromethorphan, Guaiphenesine Ammonium chloride Cough Syp.
Siliplex Cap Syp. Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus
ARIZOL -D Cap Omerprazole 20 mg & Domperidone 10 mg

NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd. A Division of AriskonPharma

उम्मीदों का प्रदेश. उत्तर प्रदेश.

युवा मुख्यमंत्री का मिशन नौजवान

उत्तर प्रदेश समृद्धि की ओर

लखनऊ, (राज्य ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने प्रदेश के नौजवानों का दुख–दर्द समझने के साथ ही उनके अंदर छिपी प्रतिभा को भी महसूस किया है। उन्होंने अनुभव किया कि अगर युवाओं को सही दिशा दी जाये तो मंजिल तक पहुंचने में उनको देर नहीं लगेगी। नौजवानों को प्रदेश की तरक्की में भागीदार बनाने के उद्देश्य से "सबको हुनर–सबको काम" को राज्य सरकार ने अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखा है।

युवा अपने पैर पर खड़े हों और उनको अपनी जिन्दगी सम्मानपूर्वक जीने का मौका मिले इसके लिए समाजवादी सरकार ने बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों में भर्ती शुरू की है। औद्योगिक और निजी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कौशल प्रदान किए जाने की आवश्यकता है, इसकी पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने कौशल विकास मिशन का गठन किया है। यह मिशन युवाओं की कौशल क्षमता का विकास करके उन्हें इस योग्य बनाएगा कि नौकरी मिलने में उनके समक्ष कोई बाधा न आए। मिशन में युवक–युवतियों को रोजगारपरक एवं गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे कई प्रशिक्षित युवाओं को बड़ी–बड़ी कम्पनियों में नौकरी भी मिली है। वास्तव में युवाओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी को प्रदेश सरकार ने पूरी ईमानदारी से समझा है। इसी का परिणाम है कि सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और छात्रों को लैपटॉप देने जैसे कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। दरअसल, प्रदेश सरकार जानती है कि मिशन नौजवान को कामयाब कर सूबे की सूरत बदली जा सकती है। सरकार ने महसूस किया है कि समय की मांग सिर्फ शिक्षा नहीं बल्कि आधुनिक और रोजगारपरक शिक्षा है। सच तो यह भी है कि बिना युवाओं को शिक्षित किए समाज में सकारात्मक परिवर्तन की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

कौशल विकास मिशन से होगा कमाल

कौशल विकास मिशन सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। कई निजी संस्थान उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण देने को तैयार हैं। सरकार इस मिशन को लेकर कितना गंभीर है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इस संबंध में शासन स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेयरिंग कमेटी बनाई गई है। मिशन से सभी जिलाधिकारियों को भी जोड़ा गया है। मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आईटीआई की सीटों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। यही नहीं, जरूरी हुआ तो पाठ्यक्रमों में बदलाव भी किया जाएगा।

सूबे के नौजवान चाहें तो इसे आने वाले समय का तोहफा भी मान सकते हैं। सरकार का लक्ष्य राज्य के युवाओं को कौशल निपुण कर रोजगार प्राप्त करने योग्य बनाना है। प्रदेश में उद्योग–धंधों का विकास होने पर स्वभाविक रूप से रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

याद होगा कि जब बेरोजगारी भत्ता देने का श्रीगणेश हो रहा था तो आलोचकों का एक वर्ग यह मान रहा था कि इससे बेरोजगार नौजवानों को निकम्मा बनाने का प्रयास किया जा रहा है और राजकोषीय धन व्यर्थ में लुटाया जा रहा है। सरकार ने ऐसे आलोचकों का मुंह बंद करते हुए प्रदेश में औद्योगिक विकास और विनिवेश का माहौल बनाया है। मुख्यमंत्री की कार्यशैली से आधारहीन आलोचनाएं धीमी होती हुई लगभग दम तोड़ चुकी हैं। युवा मुख्यमंत्री के विजन को अगर समयबद्ध ढंग से अमलीजामा पहनाया जा सका तो इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रदेश से बेरोजगारी समाप्त करने में बहुत हद तक मदद मिलेगी।

वैसे भी बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश में देश के अन्य हिस्सों के मुकाबले सबसे अधिक संख्या में युवा रहते हैं। प्रदेश सरकार का सकारात्मक कदम युवाओं को मजबूत करने के प्रति हमेशा रहता है। युवा के प्रति सरकार की दूरदर्शिता ने उनके सुनहरे भविष्य को उज्जवल किया है।

ताकि हुनरमंद हो युवा

कौशल विकास मिशन योजना का उद्देश्य है कि आने वाले वर्षों में प्रदेश में अधिक से अधिक हुनरमंद नवयुवक एवं नवयुवतियां तैयार होकर अपने लिए आजीविका कमाना शुरू कर सकें। इसीलिए सरकार ने प्रदेश के लाखों नौजवानों को विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण देकर उन्हें कुशल कामगार के रूप में तब्दील करने की योजना को मूर्तरूप प्रदान किया है।

प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित करने हेतु प्रदेश में कौशल विकास मिशन की स्थापना की गयी है, जिसके अन्तर्गत 14 वर्ष से 35 वर्ष तक की आयु के युवाओं को विभिन्न व्यवसायों में दक्षता प्रदान करने के लिये रोजगारपरक निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

जंग बेरोजगारी के खिलाफ

उत्तर प्रदेश की सपा सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देने के साथ ही बेरोजगारी के खिलाफ मुहिम भी छेड़ रखी है। कौशल विकास मिशन के तहत हजारों युवाओं को प्रशिक्षित कर सेवायोजित करने में सहायता दी गई है। अब तक एक लाख से अधिक युवाओं को रोजगार प्रदान किया जा चुका है। इसके साथ ही 2.35 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार का प्रशिक्षण निःशुल्क दिया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में लगभग 1.92 लाख बेरोजगार युवकों को रोजगारपरक निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाया गया। कौशल विकास का प्रशिक्षण लाभार्थियों को 240 से 1130 घन्टे तक प्रदान किया जाता है, जिसमें कोर स्किल के लिए कम से कम 180 घन्टे और साफ्ट स्किल के लिए 60 घन्टे का प्रशिक्षण दिया जाता है। बेरोजगार नवयुवक एवं युवतियों को विकल्प के अनुसार रोजगार प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आन–लाइन आवेदन/पंजीकरण कराने की सुविधा उपलब्ध करायी गयी, जिसमें लगभग 46.12 लाख अभ्यर्थियों को कौशल विकास मिशन द्वारा पंजीकृत किया गया।

प्रदेश के सभी बेरोजगार युवाओं को इस योजना से लाभ मिल सके, इस उद्देश्य से सभी जनपदों में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं। 38 सेक्टरों के 282 पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। मूल पाठ्यक्रम के साथ ही सभी अभ्यर्थियों को अंग्रेजी बोलने और कम्प्यूटर की सामान्य जानकारी देने की व्यवस्था की गई। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं से लाभार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया जा रहा है।

युवा सपनों की आईटी सिटी

प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 1500 करोड रुपये की लागत से आई0टी0 सिटी की स्थापना की जा रही है, जिसे एच0सीए0एल0 ग्रुप द्वारा विकसित किया जा रहा है। आई0टी0 सिटी का कार्य अक्टूबर, 2016 में पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

आईटी सिटी लखनऊ परियोजना सुल्तानपुर रोड, चक गंजरिया फार्म की 100 एकड़ भूमि पर स्थापित की जा रही है। युवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित आधुनिकतम प्रशिक्षण दिये जाने के लिए आईटी सिटी में 10 एकड़ क्षेत्र में एक कौशल विकास केन्द्र की भी स्थापना की जायेगी। यहां प्राथमिक चरण में प्रतिवर्ष 1000 छात्रों को और बाद के वर्षों में हर वर्ष 5000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा तथा उनके लिए छात्रावास की भी व्यवस्था होगी। केन्द्र को 01 नवम्बर 2016 से शुरू किये जाने का लक्ष्य है जिसके लिए एचसीएल द्वारा छात्रों की पंजीयन प्रक्रिया शीघ्र ही आरम्भ की जा रही है।

परियोजना स्थल पर लगभग 450 से अधिक श्रमिक, कारीगर और इंजीनियर निर्माण कार्यों में लगे हैं। लखनऊ में आईटी सिटी का परिचालन आरम्भ हो जाने पर लखनऊ क्षेत्र से आईटी निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। साथ ही लगभग 75000 से अधिक युवाओं को रोजगार प्राप्त होगा। आईटी सिटी के कई सकारात्मक दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। युवाओं को सीधे रोजगार मिलने से दिल्ली और उसके आसपास ही दिखाई देने वाली तरक्की की राह अब यहां भी दिख सकेगी।

आईटी सिटी बन जाने से नौकरी के लिए प्रदेश के युवाओं को नोएडा और गुड़गांव के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आईटी सिटी बनने से यह क्षेत्र दुनिया की नजरों में आ जाएगा और नौकरी के तमाम अवसर मिलेंगे। इसके साथ ही शहरों को उभरते आईटी डेस्टीनेशन के रूप में बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक तकनीक से युक्त आईटी पार्क का निर्माण भी किया जा रहा है।

आईटी पार्क का निर्माण लगभग 15,000 वर्ग मीटर फ्लोर एरिया में किया जाएगा। प्रत्येक विकास प्राधिकरण में एक आईटी पार्क विकसित किया जाना प्रस्तावित है। कुल मिलाकार यूपी को आईटी हब बनाने की पूरी–पूरी तैयारी है।

रोजगार के लिए करार

बेरोजगार युवक को प्रशिक्षण के बाद रोजगार की मुक्तधारा से जोड़ने के लिए विभिन्न औद्योगिक इकाइयों एवं शासकीय विभागों के साथ अनुबंध किया गया है। प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के लिए प्रदेश सरकार ने एक दर्जन के करीब बड़ी कम्पनियों से करार किया है। कौशल विकास योजना में युवाओं को टेक्सटाइल तथा पावरलूम का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसके लिए कौशल विकास मिशन एवं टेक्सटाइल सेक्टर स्किल काउंसिल के बीच एमओयू किया गया है।

प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को आसानी से इस सेक्टर में रोजगार मिल सकेगा। सरकार द्वारा अनेक औद्योगिक इकाइयां जैसे कि रेमण्ड लिमिटेड मुम्बई, फ्यूचर कारपोरेट रिसोर्स लि. मुम्बई, श्री लक्ष्मी काटसिन कानपुर, टीएनएस नोएडा, जी फोर यश गुड्गांव, सुपर हाउस कानपुर, जायकॉम इलेक्ट्रानिक्स सिक्योरिटी सिस्टम मुम्बई, कारवी डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज लि. हैदराबाद आदि के साथ अनुबंध किया गया है, जिसके तहत आगामी सालों में ये कम्पनियां विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान करके लगभग 60 हजार युवाओं को रोजगार दिलाएंगी। इनके अतिरिक्त जावेद हबीब हेयर एण्ड ब्यूटी लि0, ट्रांसपोर्टेशन क्षेत्र की प्रसिद्ध कम्पनी मिड मार्क कारपोरेशन लि, यूएसए की सहायक कम्पनी जनक हेल्थ केयर के साथ भी एमओयू किया गया है। समय–समय पर मिशन द्वारा रोजगार मेलों का आयोजन करके अब तक 1300 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किये जा चुके हैं। इनके अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा लगभग आठ हजार युवाओं को सेवायोजित कराया जा चुका है।

पॉवर एजेंल से मिलेगी पॉवर

वुमेन पॉवर लाइन 1090 के माध्यम से लड़कियों एवं महिलाओं को सशक्त करने का काम भी किया जा रहा है। इसके लिये हाईस्कूल से लेकर ऊपर की कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों को पॉवर एजेंल बनाने का काम किया जा रहा है। इन पॉवर एजेंलों को विशेष पुलिस अधिकारी का दर्जा प्राप्त होगा। इनको पुलिस विभाग द्वारा परिचय पत्र दिया जायेगा।

सराहनीय योगदान देने वाली प्रत्येक पॉवर एजेंल को पुरस्कृत भी किया जायेगा। पॉवर एजेंल परेशान लड़कियों को वुमेन पॉवर लाइन 1090 की जानकारी देंगी। उनके प्रति होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में 1090 को गोपनीय जानकारी देगीं। पीडित लडकी और उसके परिवार का मनोबल बढ़ाना उनका काम होगा। पॉवर एंजेल योजना को गांव–गांव तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे लड़की अपमान सहना बंद करे और अपराध के खिलाफ खुल कर आवाज उठाये।

लड़कियों के अधिकारों एवं सुरक्षा के लिये 'रूबरू' कार्यक्रम

प्रदेश का महिला सम्मान प्रकोष्ठ स्कूल कालेज जाने वाली लडकियों को उनके अधिकारों और सुरक्षा पर काम करने के लिये भी सलाह देने का काम कर रहा है। प्रकोष्ठ ने 'रूबरू' नामक कार्यक्रम चलाया है, जिसके तहत स्कूल–कॉलेज जाकर छात्राओं को सोशल मीडिया, इंटरनेट और उनके अधिकारों के लिए उन्हें जागरूक कर रही है। इसके साथ ही साथ छात्राओं को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग देने का काम भी कर रही है।

रूबरू कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न स्कूल, कॉलेजों में उम्र परिपक्वता की दहलीज पर खड़े छात्र–छात्राओं को उनके अधिकार–कानून की जानकारी, सोशल मीडिया, इंटरनेट के प्रयोग में बरती जाने वाली सावधानियां एवं लैंगिक समानता के विषय में बताया जाता है। आवश्यकतानुसार उनकी काउंसलिंग भी की जाती है। जाने अपना कानून और पाये अपना अधिकार श्रंखला के अंतर्गत जनसाधारण में नारी से संबंधित नियम–कानून जैसे घरेलू हिंसा निवारण अधिनियम, कार्य स्थल पर यौन शोषण, एसिड अटैक इत्यादि के संबंध में सार्वजनिक स्थलों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में प्रचार–प्रसार किया जाता है।

लड़कियों के लिए ऑटो और टैंपो सवारी के सबसे सरल व सहज साधन हैं। इस साधन से बड़ी संख्या में लड़कियां सफर करती हैं। कई बार उनको इन ऑटो और टैंपो चलाने वाले ड्राइवरों के व्यवहार से बड़ी शिकायतें होती हैं। महिला सम्मान प्रकोष्ठ कार्यक्रम 'सारथी' के माध्यम से ड्राइवरों को अच्छा व्यवहार करने की सीख देने का काम कर रहा है। सरकार लैंगिक अपराध के प्रति सभी को संवेदनशील करने के लिए काम कर रही है।

उम्मीदों का प्रदेश. उत्तर प्रदेश.

विकास के प्रदेश में निवेशकों को न्यौता

उत्तर प्रदेश समृद्धि की ओर

निवेशक सम्मेलनों से मिली राह

प्रदेश सरकार द्वारा निवेशकों को आकर्षित करने के लिए समय-समय पर निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है या ऐसे आयोजनों में प्रदेश की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। उद्योगपतियों को प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूपी बिजनेस समिट का आयोजन भी मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की उपस्थिति में किया जा चुका है। उन्नति के पथ पर अग्रसर होने के लिए आगरा समिट में उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में मंथन किया गया।

आगरा समिट में ही श्री अखिलेश यादव ने राज्य में दो नये हवाईअड्डों की स्थापना समेत बुनियादी ढांचा विकास से जुड़ी कई पहलों की घोषणा की। उन्होंने घरेलू और विदेशी निवेशकों से आह्वान किया कि वे राज्य में उपलब्ध निवेश संभावनाओं का फायदा उठाएं।

प्रदेश सरकार की उद्योग फ्रेण्डली नीतियों एवं विश्वस्तरीय बुनियादी सुविधाओं के फलस्वरूप दुनिया की जानी-मानी कम्पनियां उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए आगे आ रही हैं।

देशी-विदेशी निवेशकों के साथ 12 जून, 2014 को "इन्वेस्टर्स कान्क्लेव" का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसमें 20 विभिन्न निवेशकों के साथ कुल 22 सहमति पत्र हस्ताक्षरित हुए, जिसके फलस्वरूप 42,000 करोड़ रुपये का निवेश तथा 1.30 लाख रोजगार के अवसर सृजित होने की आशा जगी। 10 सितम्बर 2015 को मुम्बई में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट में देश के नामी-गिरामी उद्योगपतियों ने उत्तर प्रदेश में 51 हजार करोड़ रूपये के एमओयू हस्ताक्षरित किए। इस निवेश के मूर्त रूप लेने पर लगभग डेढ़ लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकेंगे।

लखनऊ, (राज्य ब्यूरो)। उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार द्वारा सूबे में बुनियादी सुविधाओं के विकास के बाद निवेश लगातार बढ़ रहा है। विकास का यह उत्तम प्रदेश देश-विदेश के निवेशकों के केंद्रबिंदु में है। विपक्षी चाहे जितनी भी आलोचना करें, लेकिन सच तो यह है कि निवेशकों को उत्तर प्रदेश रास आ रहा है। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार का विकासवादी एजेंडा निवेशकों को राज्य में निवेश के प्रति आकर्षित कर रहा है। निवेशक राज्य की योजनाओं में निवेश के लिए सहर्ष राजी हुए हैं। प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए निवेश की हर संभावना को नतीजे में बदलने पर सरकार पूरी मेहनत से लगी हुई है। निवेशकों को प्रदेश में जिस तरह की सुविधाएं चाहिए होंगी, उसके लिए मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की ओर से हर संभव सहायता प्रदान करने का भरोसा निवेशकों को दिलाया है। सच तो यह है कि देश का सबसे बड़ा सबसे अधिक चुनौतियों वाला राज्य उत्तर प्रदेश अब सबसे अधिक संभावनाओं वाला राज्य भी बनता जा रहा है। प्रदेश में सपा सरकार के गठन के बाद से यहां के लोगों की आंखों में वर्षों से पल रहे सपने सच होने लगे हैं। प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने साबित किया है कि उनका विजन सकारात्मक और रचनात्मक है। उनका एकमात्र एजेंडा है विकास, जिसे वे कई बार दोहरा चुके हैं।

राजधानी लखनऊ में मेट्रो ट्रेन का सपना अब सच की पटरी पकड़ चुका है तो आईटी सिटी भी हौले-हौले आकार ले रही है। भौगोलिक बनावट और बहुस्तरीय सघन आबादी के लिहाज से उत्तर प्रदेश दूसरे राज्यों की अपेक्षा अधिक चुनौती पेश करता है। सघन आबादी वाले इस प्रदेश में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचा पाना वास्तव में अपने आप में दुधारु कार्य है। फिर भी प्रदेश सरकार राज्य के सर्वांगीण व समावेशी विकास के लिए पूरी मेहनत और पारदर्शिता से काम कर रही है। सच है कि उत्तर प्रदेश के विकास के बगैर देश के समेकित विकास की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के बहुमत की सपा सरकार ने अपने अब तक के शासनकाल में राज्य में विकास की नई इबादत लिखने की सफल कोशिश की है।

विकास के तय एजेंडे पर काम

उत्तर प्रदेश की वर्तमान समाजवादी सरकार संभवतः पहली ऐसी सरकार है, जिसने पारदर्शी ढंग से पूरे वर्ष के लिए किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की है। प्रदेश के चहुंमुखी विकास की योजनाएं लयबद्ध ढंग से दौड़ती रहें, इसके लिए हर वित्तीय वर्ष के लिए विकास का एजेंडा निर्धारित किया जाता है।

उनके अनुरूप संबंधित विभागों की जिम्मेदारी भी तय की जाती है। वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ही विकास का एजेंडा उपलब्ध करा देने से विभागों के विकास कार्यों की प्राथमिकताएं स्पष्ट रहती हैं। निश्चित रूप से सरकार के इस प्रयास से विकास कार्यों की प्राथमिकताएं तो तय होती है, साथ ही पारदर्शिता भी आती है। इसके साथ ही संबंधित विभागों की जवाबदेही भी तय हो जाती है।

विश्व बैंक व योजना आयोग भी रहा मुरीद

प्रदेश में विकास की धारा को देखते हुए विश्व बैंक ने भी प्रदेश सरकार को मदद का आश्वासन दिया है। विश्व बैंक ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग देने का भरोसा दिलाया। विश्व बैंक के अध्यक्ष डॉ. जिम यांग किम ने खुद मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से मिलकर उ0प्र0 के विकास में सहयोग का भरोसा दिया था। दरअसल विश्व बैंक को भी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के लोग और बेहतर करने में कामयाब होंगे।

विश्व बैंक दुनिया से गरीबी हटाने के लिए दृढ़संकल्प है। उत्तर प्रदेश पर भी विश्व बैंक की नज़र है।

वहीं, सरकार की सक्रियता की तारीफ केंद्रीय योजना आयोग ने भी की है। आयोग ने उत्तर प्रदेश सरकार की विकास योजनाओं, कार्यक्रमों और प्राथमिकताओं की न केवल तारीफ की थी, बल्कि योजना मद की राशि में 20 फीसदी बढ़ोतरी का तोहफा भी दिया था।

- राज्य औद्योगिक विकास निगम यानी यूपीएसआईडीसी की विभिन्न इकाइयों की स्थापना के लिए 44 हजार एकड़ भूमि में लगभग 34 हजार एकड़ भूमि उद्योग स्थापना के लिए आवंटित की गई है।
- सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में प्रदेश में औद्योगिक विकास दर 11.2 प्रतिशत हासिल करने का लक्ष्य रखा है।
- वर्ष 2015-16 में दिसम्बर 2015 तक 33167 उद्यम/उद्योगों की स्थापना हुई, जिनमें रू. 4824.35 करोड़ का निवेश हुआ एवं 254544 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष व 41894 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त हुआ है।

राजधानी भी निवेशकों के लिए स्वर्ग

बात अगर राजधानी की जाए तो विशेष रूप से सुशान्त गोल्फ सिटी, चक गंजरिया एवं अवध विहार क्षेत्र निवेशकों के लिए विशेष आकर्षण का केन्द्र बन रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि यह क्षेत्र आने वाले समय में हजारों करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने जा रहा है। चक गंजरिया में एचसीएल कैम्पस की स्थापना हो रही है, वहीं अमूल डेयरी सहित अन्य प्रतिष्ठान इस क्षेत्र में अपनी इकाइयां स्थापित कर रहे हैं।

चक गंजरिया में विश्वस्तरीय कैंसर संस्थान और सुशान्त गोल्फ सिटी में मेदांता अस्पताल पर भी तेजी से काम चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम एवं अवध विहार परियोजना से इस क्षेत्र के विकास को और अधिक गति मिलेगी।

देशी-विदेशी कंपनियों ने निवेश में दिखाई रुचि

विकास की ओर कदमताल करने वाली प्रदेश सरकार की उन्नत नीतियों के परिणामस्वरूप कंप्यूटर के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी एचसीएल उत्तर प्रदेश में 100 एकड़ में आईटी सिटी स्थापित कर रही है। एचसीएल के नवशेकदम पर आगे बढ़ते हुए एस्सेल समूह, रिलायंस जियो, फोर्टिस सहित 17 अन्य कंपनियों ने प्रदेश में 54606 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए प्रारंभिक समझौता किया है।

इसमें संदेह नहीं है कि इन बड़ी कंपनियों के निवेश से प्रदेश में विकास की राह सुगम होगी और नौजवानों को रोजगार के अवसर भी सुलभ होंगे।

एस्सेल समूह शहरी विकास और बिजली वितरण जैसे क्षेत्रों में प्रदेश में निवेश करके इसकी दशा और दिशा सुधारने में मददगार होगा तो मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस जियो 4जी मोबाइल नेटवर्क का संजाल फैला कर संचार क्रांति में सहायक बनेगी।

कृषि व खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में जेबीएल एग्रो इंडस्ट्रीज और सोनालिका ने कृषि उपकरण और ट्रैक्टर विनिर्माण केंद्र स्थापित करने के लिए प्रदेश में निवेश करने में रुचि दिखाई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में फोर्टिस हेल्थकेयर, एफएमसीजी के क्षेत्र में आईटीसी विभिन्न क्षेत्रों में निवेश कर रही हैं।

ब्रिटेन की कंपनी अल्ट्रा फेयरवुड ग्रुप ने भी यूपी में निवेश करने की इच्छा जताई। इन कंपनियों के आने से न केवल विकास के नए द्वार खुलेंगे, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार की राह भी आसान होगी।

अग्निपरीक्षा में खरे उतरे अखिलेश

बहुमत की सरकार बनाने के बाद भी माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की कुर्सी कांटों भरी होगी। इस कुर्सी पर बैठना सरल नहीं होगा, लेकिन सच कहा जाए तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सरकार अग्निपरीक्षा में खरी उतरी है। युवा मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन और नेतृत्व में वैश्विक और घरेलू निवेशकों को राज्य में निवेश का न्यौता दिया जा रहा है तो दूसरी ओर, प्रदेश के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की रूपरेखा पर भी मंथन हो रहा है।

प्रदेश में उद्योग-धंधों के लिए अनुकूल माहौल सृजित हो और किसानों का चहुंमुखी विकास हो सके, इसके लिए सरकार द्वारा वृहद कार्यनीति तैयार की जा रही है। राज्य में निवेशकों के अनुकूल दोस्ताना वातावरण तैयार करने की तैयारी की जा रही है। अखिलेश सरकार के सामने अवस्थापना का विकास कर औद्योगिक वातावरण में सुधार लाने की चुनौती मुख्य रूप से थी। सरकार ने इस चुनौती को पूरा किया है। चुनौतियों का सामना करते हुए राज्य सरकार ने विकास का सफर तय किया है, जबकि प्रदेश में औद्योगिक माहौल तैयार करना प्रदेश सरकार के लिए सहज नहीं था।

प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिए उद्यमियों एवं निवेशकों को वित्तीय सहायता तथा छूट देकर प्रोत्साहित किया है।

अखिलेश सरकार द्वारा प्रदेश के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ कर औद्योगिक वातावरण विकसित करने के क्रम में सड़क, पेयजल आपूर्ति और शहरी यातायात के क्षेत्र में काफी काम किया जा रहा है। राज्य स्तरीय राजमार्गों को बेहतर बनाने लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई गई हैं। सार्वजनिक-निजी भागीदारी के आधार पर इन योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू किया गया है।

राज्य सरकार के विकास एजेण्डा के अन्तर्गत उच्च कोटि की अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे, आगरा इनर रिंग रोड, गाजियाबाद नार्दर्न पेरिफेरल रोड, प्रदेश के समस्त जनपद मुख्यालयों को चार-लेन मार्ग से जोड़ने की योजना, नैनी (इलाहाबाद) में सरस्वती हाईटेक सिटी तथा लखनऊ से आजमगढ़ के रास्ते बलिया तक प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेस-वे ग्रीन फील्ड परियोजना आदि का कार्य प्रगति पर है।

सरकार ने पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु एन0आर0आई0 विभाग का गठन भी किया है। इस विभाग के माध्यम से अप्रवासी भारतीयों के ज्ञान, कौशल एवं उनकी विश्वव्यापी पहुंच का लाभ राज्य के विकास के लिए लेने का प्रयास किया जा रहा है।

निवेश मित्र से दोस्ती

निवेश मित्र योजना के अन्तर्गत प्रदेश में सभी लघु मध्यम एवं बृहद उद्योगों को लगाने के लिए उद्यमियों को ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है। इस व्यवस्था में मानवीय दखल कम रहता है और इस कारण अधिक पारदर्शी व्यवस्था रहती है। इस व्यवस्था में आवश्यक स्वीकृतियां एवं अनापत्तियां आदि समयबद्ध रूप से उपलब्ध हो जाती हैं। निवेश मित्र-वेब आधारित सिंगल विण्डो सिस्टम के माध्यम से 12 विभागों की स्वीकृतियों के लिये ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य एवं स्टेटस मॉनिटरिंग व शुल्क भुगतान की भी सुविधा प्रदान की गयी है। इसके साथ ही उप्र औद्योगिक शिकायत निवारण प्रणाली पर समस्या ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। जिला, मंडल एवं राज्य स्तर पर उद्योग बन्धु में उद्योगों की स्थापना एवं संचालन को सुगम बनाने के लिए भी उद्यमियों को हर सम्भव सहायता प्रदान की जा रही है। औद्योगिक वातावरण में सुधार एवं उद्यमियों की सुविधा हेतु प्रदेश के समस्त जिला उद्योग केन्द्र में हेल्पडेस्क की स्थापना की गयी है, जिसके माध्यम से उद्यमियों को विभिन्न सूचनायें उपलब्ध कराई जाती हैं। प्रदेश के वर्तमान एवं भावी उद्यमियों को यथासम्भव सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उद्योग बन्धु की त्रि-स्तरीय व्यवस्था (जनपद स्तरीय उद्योग बन्धु, मण्डल स्तरीय उद्योग बन्धु एवं राज्य स्तरीय उद्योग बन्धु की व्यवस्था) को लागू रखते हुए उद्योग बन्धु को पुनर्गठित कर दिया गया है।

मुबारक बेगम को मदद का इंतज़ार

अनंत विजय

आज के दौर के फिल्म संगीत और गाने के प्रेमियों के लिए मुबारक बेगम का नाम भले ही अनजाना हो लेकिन साठ और सत्तर के दशक में मुबारक बेगम के गाए गीत खूब लोकप्रिय हुआ करते थे. मुबारक बेगम ने एक सौ पंद्रह फिल्मों में करीब पौने दो सौ गाने गाए हैं. मुबारक बेगम ने अपना पहला गाना 1949 में फिल्म आइए के लिए गाया था. इनको पार्श्वगायकी का पहला मौका देने वाले थे उस दौर के मशहूर संगीतकार शौकत हैदरी उर्फ नौशाद. मुबारक बेगम का पहला गाना था-मोहे आने लगी अंगड़ाई, आ जा आ जा बलम हरजाई. इस फिल्म में ही मुबारक बेगम ने लता मंगेशकर के साथ एक डूयट भी गाया था- जिया डोले ही जिया डोले ही किसी के ख्याल में. उसके बाद 1961 हमारी याद आएगी का गाना- कभी तन्हाइयों में हमारी याद आएगी, अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली कौंध जाएगी-को लोगों ने काफी पसंद किया था. मुबारक बेगम ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस गीत के बोल उनकी जिंदगी में साकार हो उठेंगे लेकिन ऐसा हो गया है. मुंबई के बीएसईएस अस्पताल के बिस्तर पर गुमनामी में अपना इलाज करवा रही मुबारक बेगम तन्हाइयों में अपनी सफलता के दौर को याद कर रही हैं. उन्हें भी इस बात का इंतजार है कि उनकी जिंदगी में छाए अंधेरे में कोई बिजली कौंधेगी. कोई रौशनी होगी जो

फिल्मों में गायक गायिका से लेकर सबने अब अपनी आर्थिक स्थिति के मद्देनजर अपने को मजबूत बनाने का काम किया और अपनी जिंदगी के पूर्वार्ध की आर्थिक सुरक्षा पक्की कर ली. लेकिन हिंदी साहित्य की स्थिति अब भी जस की तस बनी हुई है. आज भी हिंदी साहित्य रचकर जीविकोपार्जन कर पाना मुश्किल है. शायद ही हिंदी का कोई साहित्यकार हो जो सिर्फ साहित्य सृजन कर अपनी जिंदगी अच्छे से रह सकता है.

उनकी अंधेरी जिंदगी में थोड़ा प्रकाश भर देगी. तेइस साल तक फिल्म इंडस्ट्री में अपनी प्रतिभा के दम पर बनी रहने और हर साल कई-कई हिट गाने गाने के बाद भी आज अस्सी साल की उम्र में मुफलिसी में इलाज के लिए मदद का मुंह जोह रही हैं मुबारक बेगम. उन्नीस सौ तिरसठ में सुपरहिट फिल्म हमराही का गाना- मुझको अपने गले लगा लो-जब मुबारक बेगम ने गाया था तब उस वक्त भी उनकी आवाज को लेकर खूब प्रसिद्धि मिली थी, लेकिन उस गाने के पचपन साल बाद भी अस्पताल के बेड पर मुबारक बेगम सोच रही होंगी कि काश कोई मुझे अपने गले लगा ले यानि मदद का हाथ फैलाए. गले लगाने का सरकार ने वादा किया था, लेकिन वह हो न सका. अस्सी साल की उम्र में तंगहाली में रह रही मुबारक बेगम ने अपने श्रेष्ठ दौर में पैसों को अहमियत नहीं दी. वो कहती हैं उस वक्त फिल्मों में गाने के लिए ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे. एक गाने के तीन चार सौ रुपये मिला करते थे और वो यह भी बताती हैं कि वह गाने के लिए पैसों को लेकर मोलभाव नहीं करती थीं. जो भी जितना देता था रख लेती थीं. सच्चा कलाकार ऐसा ही होता है वो अपनी कला का सौदा नहीं करता है. मुबारक बेगम के दौर के पहले के संगीतकार नौशाद ने वो मुकाम हासिल किया था जो आमतौर पर नायकों को ही हासिल हो पाता था. वह किसी भी फिल्म में संगीत देने के लिए मुंहमांगी रकम लेते थे. उनका जो मन होता था वह मांगते थे और फिल्म निर्माता उतना पैसा देते थे. पचास के दशक में नौशाद एक फिल्म के एक लाख दस हजार रुपये लेते थे, जबकि निर्देशकों को उसका आधा पैसा भी नहीं मिलता था. कई फिल्मों में तो नायकों को भी इतना मेहनताना नहीं मिलता था. बाद में तो शंकर-जयकिशन की जोड़ी आई जो प्रति फिल्म बीस हजार रुपये पर काम करने लगी थी लेकिन तब भी नौशाद की शान और दाम दोनों में कोई कमी नहीं आई. नौशाद के संगीत का यह जलवा था कि उनका नाम देखकर ही फिल्में हिट हो जाती थीं. कहते हैं कि यह नौशाद के नाम का ही असर था कि दर्शकों और श्रोताओं को भरमाने के लिए नक्शब ने शौकत देहलवी का नाम नाशाद रख दिया था. यह वही नाशाद थे जिन्होंने मुबारक बेगम को ब्रेक दिया था. यह अलहदा बात है कि नाशाद कभी भी नौशाद के स्तर तक नहीं पहुंच पाए लेकिन उन्होंने कई बेहतरीन गाने दिए. उन्होंने अपने संगीत में कई तरह के प्रयोग किए. खैर ये अवांतर प्रसंग है.

यह सुनने में अच्छा लगता है कि कला का सौदा नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन जब कलाकरों को वक्त के उबड़-खाबड़ रास्ते पर चलना होता है तो उनको कई बार अफसोस होता है कि काश अपने अच्छे दिनों का सौदा कर लिया होता या अपने फन के लिए उचित पैसे ले लिए होते तो आज यह दिन नहीं देखने होते. हमें पता नहीं कि इन दिनों मुबारक बेगम को इस बात का अफसोस हो रहा है या नहीं कि उन्होंने अपने अच्छे समय में पैसे को लेकर मोलभाव क्यों नहीं किए थे? क्यों नहीं उन्होंने गाने के लिए ज्यादा पैसों की मांग की थी? लेकिन उन्हें इस बात का बेहद अफसोस है कि मदद का ऐलान करने के बावजूद महाराष्ट्र सरकार उनकी मदद के लिए अबतक आगे नहीं आई है. खुद महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री के ऐलान के बावजूद मदद नहीं मिलने से हमारी व्यवस्था की संवेदनहीनता उजागर होती है. मदद तो दूर की बात सरकार का कोई नुमाइंदा मुबारक बेगम का हाल चाल लेने अस्पताल तक नहीं पहुंचा. इन दिनों मुबारक बेगम की मदद उनके साथ फिल्मों में गायकी करने वाली लता मंगेशकर कर रही हैं और बहुधा दवाइयों का खर्चा सलमान खान उठा रहे हैं. लता मंगेशकर पैसों से भी उनकी मदद करती हैं लेकिन वह उनकी बीमारी को देखते हुए नाकाफी है. कुछ दिनों पहले सैकड़ों फिल्मों में काम करने वाले मशहूर अभिनेता एके हंगल की मुफलिसी की खबरें भी आईं थी. तब भी सरकार की संवेदनहीनता पर सवाल उठे थे लेकिन तब से लेकर अबतक कोई बदलाव नहीं आ पाया है. कलाकार को, लेखक को, अभिनेता को तो हमें अपनी विरासत की तरह सहेज कर रखना चाहिए, लेकिन हो यह रहा है कि यह भी विरासत की तरह ही नष्ट होते जा रहे हैं. कलाकारों को सरकार की तरफ से तवज्जो ही नहीं मिल रही है, मदद की बात तो दूर. क्या केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इतनी अच्छी गायिका की उनके बुरे दिनों में मदद करे. क्या संगीत नाटक अकादमी के पास इस बात के लिए पैसे नहीं हैं कि वो मुबारक बेगम के अच्छे इलाज का इंतजाम करवा सके. इन अकादमियों को क्या सिर्फ पुरस्कार, गोष्ठी और सेमिनारों तक सीमित कर दिया जाना चाहिए. इस वजह से काफी समय से एक मांग उठ रही है कि मुफलिसी के वक्त कलाकारों, लेखकों की मदद के लिए एक कोष की स्थापना की जाए और उसमें संबंधित अकादमियों के नुमाइंदों के साथ-साथ उस क्षेत्र की एक-एक मशहूर हस्तियां भी हों. इस कोष में सरकार एक आधार राशि अनुदान के तौर पर दे और उसके बाद इंडस्ट्री और कला प्रेमियों से डोनेशन लेकर इस फंड को बढ़ाने की कोशिश की जानी चाहिए. ताकि वक्त पर जरूरतमंद कलाकारों और लेखकों की मदद की जा सके. हमें याद पड़ता है कि हिंदी के वरिष्ठ कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने भी अपनी जिंदगी के आखिरी साल मुफलिसी में ही गुजारे थे. जब उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जब इस बात का पता चला था तब उन्होंने साहित्य अकादमी के मार्फत निराला जी की मदद करवाई थी. सवाल यही उठता है कि क्यों लेखकों को इस स्थिति का सामना करना पड़ता है. फिल्मों में गायक गायिका से लेकर सबने अब अपनी आर्थिक स्थिति के मद्देनजर अपने को मजबूत बनाने का काम किया और अपनी जिंदगी के पूर्वार्ध की आर्थिक सुरक्षा पक्की कर ली. लेकिन हिंदी साहित्य की स्थिति अब भी जस की तस बनी हुई है. आज भी हिंदी साहित्य रचकर जीविकोपार्जन कर पाना मुश्किल है. शायद ही हिंदी का कोई साहित्यकार हो जो सिर्फ साहित्य सृजन कर अपनी जिंदगी अच्छे से रह सकता है.

साहित्यकारों, संगीतकारों और गायकों की मदद करने के लिए कई निजी संस्थाएं सक्रिय हैं लेकिन उनकी सक्रियता काफी नहीं है. मुंबई में ही एक कार्यक्रम रहमतें के नाम से होता है और उसको आयोजित करने वाली संस्था हर साल कलाकारों की मदद करती है. मदद करने का उनका अपना अनूठा तरीका है. वह कलाकारों का एक निश्चित रकम का बीमा करवाकर उनको देती है, जो मौके पर काम आ सके. इसी तरह से कई निजी कंपनियां कलाकारों की समय-समय पर मदद करती हैं, लेकिन कोई केंद्रीय संस्था नहीं है जो कलाकारों, लेखकों को उनके बुरे वक्त में मदद कर सके. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)

anant.ibn@gmail.com

अशोक

पिछले अंक से आगे

औषधीय प्रयोग मात्रा एवं विधि

वक्षः

श्वास- 65 मिग्रा अशोक बीज चूर्ण को पान के बीड़े में रखकर खिलाने से श्वास रोग में लाभ होता है.

उदर रोग :

वमन- अशोक के फूलों को जल में पीसकर स्तनों पर लेप कर दूध पिलाने से स्तनपाई बालक का वमन रुक जाता है.

रक्तातिसार- अशोक के 3-4 ग्राम फूलों को जल में पीसकर पिलाने से रक्तातिसार में लाभ होता है.

गुदा रोग :

रक्तार्श- अशोक की छाल का क्वाथ बनाकर 15-25 मिली मात्रा में पिलाने से रक्तार्शजन्य रक्तस्राव बन्द हो जाता है.

अशोक की छाल और इसके फूलों को बराबर की मात्रा में लेकर 10 ग्राम मात्रा को रात्रि में एक गिलास पानी में भिगोकर रख दें. सुबह पानी छानकर पी लें. इसी प्रकार सुबह का भिगोया हुआ शाम को पी लें. इससे (खूनी बवासीर) में शीघ्र लाभ मिलता है.

वृक्कवस्ति रोग :

अकरी (पथरी)- अशोक के 1-2 ग्राम बीज को पानी में पीसकर दो चम्मच की मात्रा में पीने से अश्मरीजन्य शूल का शमन होता है.

प्रजननसंस्थान रोग :

प्रदर- अशोक छाल चूर्ण और मिश्री को समभाग खरल कर, 3 ग्राम की मात्रा में लेकर गोदुग्ध के साथ प्रातः शाम सेवन करने से श्वेत-प्रदर में लाभ होता है.

15-25 मिली अशोक छाल क्वाथ को दूध में मिलाकर पातः सायं पिलाने से श्वेत-प्रदर और रक्त-प्रदर में लाभ होता है.

अशोक के 2-3 ग्राम फूलों को जल में पीसकर पीलाने से रक्त प्रदर में लाभ होता है.

मासिकविकार- अशोक छाल का क्वाथ बनाकर 20-30 मिली मात्रा में पिलाने से मासिक विकारों का शमन होता है.

स्वप्नदोष- 20 ग्राम अशोक की छाल

को यवकुट कर 250 मिली जल में पकाएं, 30 मिली शेष रहने पर इसमें 6 ग्राम शहद मिलाकर सुबह-शाम सेवन करने से लाभ होता है.

6-12 ग्राम अशोक घृत को गुनगुने दूध अथवा जल के साथ सेवन करने से सभी प्रकार के प्रदर रोग, कुक्षिशूल, कटिशूल, योनिशूल, मंदाग्नि, अरुचि, पाण्डु, श्वास, कास आदि रोगों का शमन होता है तथा बल, वर्ण व आयु की वृद्धि होती है.

20-25 मिली अशोकारिष्ट को प्रतिदिन भोजन के बाद सेवन करने से रक्तप्रदर, ज्वर, रक्तपित्त, रक्तार्श, मंदाग्नि, अरोचक, प्रमेह, शोथ आदि रोगों में अतिशय लाभ होता है.

अस्थिसंधि रोग :

अस्थिभंग- 6 ग्राम अशोक छाल चूर्ण को दूध के साथ प्रातः सायं सेवन करने से तथा इसी का प्रलेप करने से टूटी हुई हड्डी जुड़ जाती है और वेदना का शमन होता है.

वातव्याधि- वातरोग में स्नेहविरेचनार्थ अशोकघृत का प्रयोग हितकर है.

त्वचा रोगः

त्वचाविकार- अशोक छाल स्वरस में सरसों को पीसकर छाया में सुखा लें, तत्पश्चात् जब उबटन लगाना हो तब सरसों को इसकी छाल के स्वरस में ही पीसकर त्वचा पर लगाएं. इससे त्वचा का रंग निखरता है.

मुहांसे- अशोक से निर्मित छाल क्वाथ को उबालकर गाढ़ा होने पर इसे ठण्डा करके, इसमें बराबर की मात्रा में सरसों का तैल मिला लें. इसे मुहांसों, फोड़ों तथा फुन्सियों पर लगाएं. नियमित प्रयोग करने से लाभ होगा.

व्रण- घृत, प्रियंगु, अशोक रोहिणी की त्वक्, त्रिफला, धातकी, लोध्र तथा सर्जरस को समान मात्रा में लेकर, सूक्ष्म चूर्ण कर, व्रण पर छिड़कने से शीघ्र व्रण का रोपण होता है.

सर्वशरीर रोग :

बुद्धिवर्धक- अशोक की छाल तथा ब्राह्मी चूर्ण को बराबर मात्रा में मिलाकर एक-एक चम्मच सुबह-शाम, एक-कप दूध के साथ नियमित रूप से कुछ माह तक सेवन करने से बुद्धि तीव्र होती है.

सर्वांग शूल- अशोक का क्वाथ बनाकर 10-20 मिली मात्रा में पीने से वेदना का शमन होता है.

प्रयोज्यांग : *त्वक् पत्र, पुष्प तथा बीज.*

मात्रा : *त्वक् क्वाथ 50 मिली. बीज चूर्ण 2-4 ग्राम. पुष्प चूर्ण 1-3 ग्राम.*

नोट : *काष्ठदारु की प्रायः अशोक वृक्ष के रूप में पहचान की जाती है, जो गलत है; वास्तविक अशोक य सीता अशोक होता है, जिसमें सिंदूरी या लाल वर्ण के पुष्प आते हैं तथा काष्ठदारु में पीताभ-हरित वर्ण के पुष्प आते हैं. काष्ठदारु वृक्ष की लम्बाई (15-20 मी तक) भी वास्तविक अशोक (6-9 मी तक) से अधिक होती है.* ■

आचार्य बालकृष्ण

साईं वंदना

सद्गुरु तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास करना ज़रूरी

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

आज के युग में इतने गुरु हैं, तो कैसे पता चले कि हमें सही श्री गुरु मिल गए हैं?

गुरु कई प्रकार के हैं- पिता-माता प्रथम गुरु, शिक्षा गुरु, मंत्र गुरु, कुल गुरु आदि. हर व्यक्ति कहीं न कहीं गुरु खोजने का प्रयास करता है-करना भी चाहिये. गुरु गीता में भी कहा गया है कि जैसे भंवरा फूल से फूल तक जाता है, उसी प्रकार गुरु से गुरु तक जाना चाहिए. पर हर गुरु सद्गुरु नहीं है. सद्गुरु तो वह हैं जो आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं और जिनमें हर परिस्थिति में भक्त की रक्षा करने की सामर्थ्य हो. सद्गुरु पृथ्वी पर बहुत कम होते हैं. एक बार सद्गुरु तक पहुंचने के बाद गुरु खोजने की आवश्यकता नहीं रहती. सद्गुरु के पास पहुंचने तक शिष्य ढूंढ़ता रहेगा कि खरा सोना कहां है, क्योंकि इस दुनिया में जैसे सद्गुरु हैं, वैसे ही असद्गुरु भी हैं. यह तो हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करके देखना पड़ेगा कि गुरु सद्गुरु हैं या नहीं. फिर जिसको सद्गुरु तक पहुंचने की इच्छा है, उसे निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए. एक न एक दिन वह सद्गुरु की दृष्टि अपनी ओर आकर्षित कर लेगा. तत्पश्चात् किसी न किसी माध्यम से वह स्वयं ही सद्गुरु तक पहुंच जायेगा.

गुरु-दीक्षा

क्या गुरु से दीक्षा लेना आवश्यक है?

है. पर दीक्षा का रूप क्या होना चाहिए, इसमें विभिन्नता है. किसी मत के अनुसार गुरु द्वारा कान में मंत्र देना, नाम देना या बीज-अक्षर देना दीक्षा है. किसी पूजा-पाठ या साधना-पद्धति से भी दीक्षा देने की परंपरा है. गुरु तभी दीक्षा देते हैं, जब वे भक्त या शिष्य को भक्ति-मार्ग पर विशेष रूप से लेना चाहते हैं. मैं समझता हूं कि यह भावनात्मक सम्बन्ध है, वह चाहे औपचारिक रूप से हो या अनौपचारिक रूप से. गुरु के प्रति जब श्रद्धा प्रगाढ़ हो जाती है, तब उनका नाम ही दीक्षा-मंत्र हो जाता है.

गुरु-स्मरण का महत्व

गुरु के स्मरण को इतना महत्व क्यों दिया गया है?

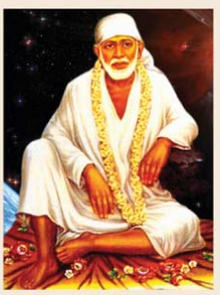

गुरु की आलोक-रश्मि सबमें है. उनका स्मरण करने से व्यक्ति उनके प्रभा-मण्डल से जुड़ता है. उनका स्मरण करते ही वह स्वतः उनकी भाव-तरंग से जुड़ जाता है. गुरु का भाव भक्त को आवेशित करता है और उस समय मन को सांसारिक संकल्प, जो कि चित्त को अस्थिर करते हैं, नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि गुरु का प्रभा-मण्डल बहुत शक्तिशाली होता है. बाबा ने कहा था कि-

- ...जो कोई अनन्य भाव से मेरी शरण आता है, जो श्रद्धा पूर्वक मेरा पूजन, निरन्तर स्मरण और मेरा ही ध्यान करता है, उसको मैं मुक्ति प्रदान कर देता हूं.
- जो नित्य प्रति मेरा नाम स्मरण और पूजन कर मेरी कथाओं और लीलाओं का प्रेमपूर्वक मनन करते हैं, ऐसे भक्तों में सांसारिक वासनाएं और अज्ञान-रूपी प्रवृत्तियां कैसे ठहर सकती हैं?
- जब और जहां भी तुम मेरा स्मरण करोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

साईं भक्तों! आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

तो इस बार ओलम्पिक में पदक जीतेंगे पेस

तमाम विवादों के बाद लंदन ओलम्पिक में पेस का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं था. अब भारतीय खेल प्रेमियों को उम्मीद है कि रियो में पदक दिला सकते हैं लिएंडर पेस. अब यह देखना रोचक होगा कि पेस इस बार ओलम्पिक में किस जोड़ीदार के साथ उतरते हैं.

सैय्यद मोहम्मद अब्बास

भारतीय टेनिस जगत में लिएंडर पेस एक ऐसा नाम है जो लगातार कामयाबी की नई इबारतें लिख रहा है. 42 साल की उम्र में लिएंडर पेस कोर्ट पर 24 साल के जवान से ज्यादा फुर्तीले दिखते हैं. विश्व टेनिस में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी होने के बावजूद पेस ने फ्रेंच ओपन में शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए मार्टिना हिंगिस के साथ मिलकर मिश्रित युगल का खिताब अपने नाम किया. भारतीय खेल जगत में लिएंडर पेस का कद लगातार बढ़ता जा रहा है. क्रिकेट में जो मुकाम रिकॉर्ड पुरुष सचिन को हासिल है वही दर्जा टेनिस में लिएंडर पेस को है.

तमाम उतार-चढ़ाव के बावजूद पेस भारतीय टेनिस के सितारे बने हुए हैं. वक्त और हालात कभी एक जैसे नहीं रहते हैं किन्तु लिएंडर पेस ने तमाम बाधाओं को सफलतापूर्वक पार करते हुए भारतीय तिरंगे को बुलन्द किया है. ऐसा माना जाता है कि किसी भी खेल में खिलाड़ी 18 से 30 साल की आयु वाले वर्ग में करियर के सर्वश्रेष्ठ दौर में होता है लेकिन इसके उलट पेस के साथ ऐसा नहीं है. बढ़ती उम्र के बावजूद वह लगातार स्वर्णिम इतिहास रच रहे हैं. भारतीय टेनिस को अपने मजबूत कन्धे पर उठाने वाले पेस ने पिछले चार दशक से विश्व टेनिस पटल पर अपनी अलग पहचान बनाई है. इन चार दशकों में खिलाड़ी आते और जाते रहे, लेकिन पेस के कदम जमे रहे. आलम यह है कि ओलम्पिक में अब भारत को टेनिस में भी पदक मिलने की उम्मीद परवान चढ़ने लगी है. पेस देश ही नहीं बल्कि विश्व के अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जो छह ओलम्पिक खेल चुके हैं और सातवीं की तैयारी में हैं. रियो ओलम्पिक में पदक जीतकर नया इतिहास रचने को बेताब लिएंडर पर देश की निगाहें टिकी हुई हैं, वे देश की जनता के लिए आशा की एक किरण हैं. ऐसे में वह रियो में पदक जीतकर अपने करियर में एक और इतिहास जोड़ सकते हैं.

लिएंडर पेस के परिवार की बात की जाए तो उनका परिवार खेल का शौकीन रहा है. उनके पिता वेस पेस अंतरराष्ट्रीय स्तर के हॉकी खिलाड़ी थे. 1972 के म्युनिख ओलम्पिक में भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता था, उस जीत में उनके पिता वेस पेस का अहम रोल था. दूसरी ओर उनकी मां जेनिफर पेस बास्केटबॉल की अंतरराष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी रही हैं. इन दोनों के उलट पेस ने टेनिस की दुनिया में कदम रखा. बहुत कम लोग जानते हैं कि लिएंडर पेस 19वीं सदी के महान कवि माइकल मधुसूदन दत्त के वंशज हैं. कोलकाता में जन्मे पेस ने शुरुआती दौर में ही टेनिस की राह पकड़ ली थी. 1985 में ही पेस ने भारत की शीर्ष टेनिस प्रशिक्षण अकादमियों में से एक ब्रिटानिया अमृतराज टेनिस अकादमी चेन्नई में टेनिस का गुर सीखना शुरू किया था. माना जाता है कि यहीं से पेस ने अपने खेल को गति देनी शुरू कर दी थी. 90 के दशक में पेस का सितारा चमकने के लिए बेताब था. इसकी पहली झलक जूनियर स्तर पर देखने को मिली. जूनियर यूएस ओपन के साथ विम्बलडन का खिताब जीतकर पेस ने साबित कर दिया कि वे लम्बी रेस के घोड़े हैं.

विश्व टेनिस जगत में पेस ने कई जमाने के खिलाड़ियों को अपने सामने खेलते देखा है. उन्होंने जॉन मैक्केनरो से लेकर नडाल तक का दौर देखा है. इतना ही नहीं पेस ने अगासी से लेकर पीट सम्प्रास और अब रोजर फेडरर तथा जोकोविच तक के दौर देखे. इस शानदार दौर में पेस ने युगल वर्ग में भारतीय परचम लहराया. उन्होंने अपने करियर में 16 ग्रैण्ड स्लैम खिताब जीते हैं. इस तरह से पेस ने आठ-आठ क्रमशः युगल और मिश्रित डबल्स खिताब अपने नाम किए हैं. पेस को भले डबल्स का माहिर खिलाड़ी माना जाता हो लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब वह एकल में जौहर दिखाते थे. पेस ने 1996 में अटलांटा ओलम्पिक में इतिहास रचते हुए कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम रौशन किया था. ओलम्पिक में यह दूसरा मौका था जब किसी भारतीय ने टेनिस में पदक जीता था. पेस से पहले केडी जाधव ने 1952 के ओलम्पिक में कांस्य पदक जीता था. इसके बाद पेस ने डबल्स में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया. जैसे-जैसे टेनिस में बदलाव हुए वैसे-वैसे पेस ने जोड़ी बदली. लिएंडर पेस ने अब तक 100 से ज्यादा खिलाड़ियों के साथ अपनी जोड़ी बनाई. उनकी सबसे कामयाब जोड़ी महेश भूपति के साथ बनी, हालांकि बाद में यह जोड़ी टूट गई. यह वह दौर था जब टेनिस जगत में पेस-भूपति की जोड़ी के सामने कोई नहीं टिकता था. दोनों खिलाड़ियों ने रिकॉर्डों की झड़ी लगा दी थी. दोनों ने मिलकर लगातार 24 डेविस कप मैच अपने नाम किए. पेस अगर एटीपी युगल में मौजूदा सत्र में 11 और मैच जीतने में कामयाब रहते हैं तो वह अमेरिका के शेखुड स्टीवर्ट को पछाड़कर सबसे अधिक युगल जीत दर्ज करने वाले खिलाड़ियों की सूची में छठे स्थान पर पहुंच जाएंगे. स्टीवर्ट 728 जीत के साथ छठे स्थान पर हैं जबकि 17 ग्रैंडस्लैम खिताब जीतने वाले पेस के नाम पर 718 जीत दर्ज हैं.

कुल मिलाकर रियो ओलम्पिक में अगर पेस इसी तरह से खेलते रहे तो भारत को इस बार पदक दिला सकते हैं. यह तभी संभव होगा जब उनको सही जोड़ीदार मिले. पिछले ओलम्पिक में पेस के जोड़ीदार को लेकर खूब किचकिच हुई थी. हालांकि पेस को अगर रियो में जलवा दिखाना है तो उन्हें मिश्रित युगल में सानिया मिर्जा के साथ खेलने का मोह छोड़ना होगा. हालांकि पिछले 18 महीने में पेस ने इस वर्ग में गजब का प्रदर्शन किया है. पेस को अगर रियो ओलम्पिक का टिकट हासिल करना है तो उन्हें सिर्फ पुरुष युगल से संतोष करना होगा क्योंकि इस बार नम्बर वन सानिया भी अपना जोड़ीदार खुद चुनेंगी और ऐसा कहा जा रहा है कि सानिया पेस के मुकाबले बोपन्ना के साथ ज्यादा सहज हैं. दूसरी ओर पुरुष युगल में भी अब रोहन बोपन्ना पर निर्भर करेगा कि वह रियो में किसे अपना जोड़ीदार बनाते हैं. सीधे प्रवेश पाने के कारण बोपन्ना को अपना जोड़ीदार चुनने का अधिकार मिलेगा. वैसे कोशिशें चल रही हैं कि बोपन्ना को पेस के जोड़ीदार के रूप में चुनने के लिए मनाया जाए. तमाम विवादों के बाद लंदन ओलम्पिक में पेस का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं था. अब भारतीय खेल प्रेमियों को उम्मीद है कि रियो में पदक दिला सकते हैं पेस. अब यह देखना रोचक होगा कि पेस इस बार ओलम्पिक में किस जोड़ीदार के साथ उतरते हैं. ■

डिस्कस थ्रो में सीमा से पदक की उम्मीद

ओलम्पिक में पदक जीतने का सपना हर खिलाड़ी का होता है. विश्व के कई देशों के तमाम खिलाड़ी रियो ओलम्पिक की खातिर लगातार पसीना बहा रहे हैं. ओलम्पिक में कोटा हासिल करने वालों की सूची लगातार बढ़ रही है, पर कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो देश के लिए पदक जीत सकते थे, लेकिन वे ओलम्पिक में जाते-जाते रह गए. उनमें चाहे मैरीकॉम हों या फिर सरिता. दोनों का मुक्का बेमिसाल है, पर वे ओलम्पिक का सफर तय करने में नाकाम रहीं. सरिता और मैरीकॉम ओलम्पिक में कोटा हासिल करने में नाकाम रहीं. हालांकि मैरीकॉम के लिए ओलम्पिक के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं. उन्हें वाइल्ड कार्ड के जरिए ओलम्पिक टीम का हिस्सा बनाया जा सकता है. वहीं भारत के स्टार पहलवान सुशील कुमार का भी ओलम्पिक में हिस्सा लेने का सपना टूट गया. दिल्ली हाईकोर्ट ने सुशील कुमार की याचिका ख़ारिज कर दी है. एक ओर महिला मुक्केबाजी से खुशखबरी नहीं आ रही थी तो दूसरी ओर डिस्कस थ्रो से भारत की स्टार खिलाड़ी सीमा पुनिया ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन करते हुए कैलिफोर्निया में पेट यंग थ्रोअर क्लासिक इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर ओलम्पिक के लिए क्वालीफाई कर लिया.

जैसे-जैसे ओलम्पिक का वक्त करीब आ रहा है वैसे-वैसे इसमें भाग लेने वाले खिलाड़ियों की तस्वीर भी साफ होती जा रही है. कुश्ती, बैडमिन्टन, हॉकी और तीरंदाजी जैसे खेलों में भारतीय दल लगभग तय हो चुके हैं. डिस्कस थ्रो में अभी सीमा पुनिया का नाम सामने आया है, जबकि भारत के शीर्ष डिस्कस थ्रोअर विकास गौड़ा ने भी रियो ओलम्पिक का टिकट हासिल किया है. डिस्कस थ्रो में भारतीय खिलाड़ी भी पदक जीतने के तगड़े दावेदार हैं. सीमा और विकास लंबे समय से ओलम्पिक की तैयारी में जुटे हैं. सीमा का हाल का फॉर्म शानदार रहा है. सीमा के प्रदर्शन पर गौर किया जाए तो इतना साफ है कि वह ओलम्पिक में इतिहास रच सकती हैं. उन्होंने क्वालीफाइंग मुकाबले में 62.62 मीटर डिस्कस फेंका जबकि ओलम्पिक मार्क 61 मीटर था. सीमा अब तक 10 बार 61 मीटर से ज्यादा का थ्रो फेंक चुकी हैं. इसी शानदार कामयाबी के बाद उन्हें ओलम्पिक में जगह मिली. इससे पहले उन्होंने 2004 और 2012 ओलम्पिक में भाग लिया था लेकिन दोनों ही अवसरों पर वह क्वालिफिकेशन राउंड से आगे बढ़ने में असफल रही थीं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली सीमा भारत की 19वीं ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं, जिन्होंने रियो ओलम्पिक के लिए पात्रता हासिल की है. सीमा के करियर पर नजर दौड़ाई जाए तो इतना साफ है कि ओलम्पिक में उन्होंने भले ही कुछ खास नहीं किया हो, लेकिन अन्य प्रतियोगिताओं में वह पदकों की झड़ी लगाती रही हैं. उन्होंने 2014 ग्लास्गो राष्ट्रमंडल खेलों में 61.61 मीटर डिस्कस फेंक कर रजत पदक हासिल किया था. सीमा पुनिया का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 64.84 मीटर का है जो उन्होंने 2004 में किया था. उन्होंने 2006 मेलबर्न राष्ट्रमंडल खेलों में रजत के अलावा 2010 दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य अपने नाम किया था. वे करिअर में 10 बार 61 मीटर से ऊपर का प्रयास कर चुकी हैं. उन्होंने वर्ष 2015 में इंचियोन में आयोजित एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक हासिल किया.

रियो ओलम्पिक के लिए सीमा पुनिया अमेरिका में रहकर प्रैक्टिस कर रही हैं. 27 जुलाई 1983 को हरियाणा के सोनीपत जिले के मुरथल शहर के गांव खेवड़ा में जन्मी 32 वर्षीय एथलीट पुनिया अब ओलम्पिक में भारत के लिए पदक जीतना चाहती हैं. सीमा मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली हैं. उनका विवाह मेरठ के रहने वाले अंकुश पुनिया से हुआ है. उनके पति अंकुश भी राष्ट्रीय स्तर के डिस्कस थ्रो के खिलाड़ी हैं. ऐसे में वह सीमा पुनिया के कोच के रूप में उनकी सफलता में अहम रोल अदा कर रहे हैं. कुल मिलाकर रियो के खेल में सीमा से पदक की उम्मीद की जा सकती है. ■

गोलमाल करने की फ़िराक़ में अजय-रोहित

हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के ब्लॉकबस्टर निर्देशक रोहित शेट्टी की. अजय देवगन और रोहित शेट्टी की अगली फिल्म का इंतजार फैंस बेसब्री से कर रहे हैं. अजय देवगन के फैंस के लिए एक जबरदस्त खुशख़बरी है. दरअसल रोहित शेट्टी अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स से पहले गोलमाल-4 पर काम शुरू करना चाहते हैं. सूत्रों की मानें तो शाहरूख खान के साथ दिलवाले के बाद रोहित शेट्टी का मन थोड़ा उखड़ चुका है. इतना ही नहीं, बल्कि रोहित और शाहरूख के बीच खटपट की ख़बरें भी गर्म हैं. लिहाजा, वह अपनी सुपरहिट सीरिज गोलमाल पर काम करना चाहते हैं.

दरअसल, फिल्म *बाजीराव मस्तानी* के साथ *दिलवाले* रिलीज़ करने को रोहित पहले राजी नहीं थे. लेकिन शाहरूख ने ही उन्हें मनाया और फिर फिल्म का क्या हाल हुआ, यह सभी जानते हैं. ऐसे में रोहित शेट्टी ने वापस अजय देवगन से हाथ मिलाया है. रोहित गोलमाल-4 को पिछली फिल्मों से भी ज्यादा मजेदार और बड़ा बनाना चाहते हैं. निर्देशक ने कहा कि फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम चल रहा है. मैं 6 महीने के बाद गोलमाल-4 पर काम शुरू कर दूंगा. उम्मीद है कि इस साल के अंत तक फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाए.■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

इरफ़ान के साथ काम करेगी ज़रीन खान

पहले इस फिल्म में इरफ़ान खान के साथ कंगना रनौत काम करने वाली थी, लेकिन अब कंगना की जगह ज़रीन खान काम करने जा रही है.

बॉलीवुड अभिनेत्री ज़रीन खान अभिनेता इरफ़ान खान के साथ काम करने जा रही हैं. बॉलीवुड निर्देशक साईं कबीर डिवाइन *लवर्स* नामक फिल्म बनाने जा रहे हैं. पहले इस फिल्म में इरफ़ान खान के साथ कंगना रनौत काम करने वाली थी, लेकिन अब कंगना की जगह ज़रीन खान काम करने जा रही है. साईं कबीर ने कहा कि हम पठानी रूप वाली एक लड़की ढूंढ रहे थे और ज़रीन खान इसके लिए एकदम सही हैं. यह फिल्म काफी एडवेंचर कॉमेडी है. इसकी शूटिंग सितंबर में शुरू होगी.■

"पुरानी पीढ़ी के साथ-साथ नई पीढ़ी भी उनकी आवाज़ की दीवानी है."

किशोर कुमार के बारे में कुछ मज़ेदार जानकारियां

बहुमुखी प्रतिभा के धनी गायक, संगीतकार, अभिनेता, निर्माता, लेखक जैसे किशोर कुमार के कई रूप हमें देखने को मिले. किशोर ने जिस तरह से फिल्म संगीत जगत में अपना स्थान बनाया वह तारीफ़ के काबिल है. अपनी मधुर आवाज़ में गाए गीतों के जरिए किशोर कुमार आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं. पुरानी पीढ़ी के साथ-साथ नई पीढ़ी भी उनकी आवाज़ की दीवानी है. उनके गीत आज भी लोगों की जुबां पर कायम हैं. किशोर जितने उम्दा कलाकार थे, उतने ही रोचक इंसान. वे कब क्या कर बैठें, यह कोई नहीं जानता था. उनके कई किस्से बॉलीवुड में प्रचलित हैं, उनके किस्सों की जानकारी भी कम ही लोगों को होगी. आइये जानते हैं किशोर कुमार से जुड़ी कुछ यादगार कहानियां.

1 किशोर कुमार ने हिंदी सिनेमा के तीन नायकों को महानायक का दर्जा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है. उनकी आवाज़ के जादू से देवानंद सदाबहार हीरो कहलाए. राजेश खन्ना को सुपर सितारा कहा जाने लगा और अमिताभ बच्चन महानायक हो गए.

2 बारह साल की उम्र तक किशोर ने गीत-संगीत में महारत हासिल कर ली. वह रेडियो पर गाने सुनकर उनकी धुन पर थिरकते थे. फिल्मी गानों की किताब जमा कर उन्हें कंठस्थ कर गाते थे. घर आने वाले मेहमानों को अभिनय सहित गाने सुनाते और मनोरंजन करके कुछ इनाम भी मांग लेते थे.

3 एक दिन अशोक कुमार के घर अचानक संगीतकार सचिन देव बर्मन पहुंच गए. बैठक में उन्होंने गाने की आवाज़ सुनी तो दादा मुनि से पूछा, कौन गा रहा है? अशोक कुमार ने जवाब दिया-मेरा छोटा भाई है. जब तक गाना नहीं गाता, उसका नहाना पूरा नहीं होता. सचिन-दा ने बाद में किशोर कुमार को जीनियस गायक बना दिया.

4 फिल्म *प्यार किए जा* में कॉमेडियन महमूद ने किशोर कुमार, शशि कपूर और ओमप्रकाश से ज्यादा पैसे वसूले थे. किशोर को यह बात अखर गई और इसका बदला उन्होंने महमूद से फिल्म *पड़ोसन* में लिया वो भी डबल पैसा लेकर.

5 किशोर कुमार ने जब-जब स्टेज शो किए, हमेशा हाथ जोड़कर सबसे पहले संबोधन करते थे- मेरे दादा-दादियों. मेरे नाना-नानियों. मेरे भाईयों-बहनों, तुम सबको खंडवे वाले किशोर कुमार का राम-राम. नमस्कार.

6 किशोर ने अपनी दूसरी बीवी मधुबाला से शादी के बाद मजाक में कहा था- मैं दर्जनभर बच्चे पैदा कर खंडवा की सड़कों पर उनके साथ घूमना चाहता हूं.

7 किशोर कुमार का बचपन तो खंडवा में बीता, लेकिन जब वह किशोर हुए तो इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ने आए. हर सोमवार सुबह खंडवा से मीटरगेज की छुक-छुक रेलगाड़ी में इंदौर आते और शनिवार शाम लौट जाते. सफर में वे हर स्टेशन पर डिब्बा बदल लेते और मुसाफिरों को नए-नए गाने सुनाकर उनका मनोरंजन करते थे.

8 किशोर जिंदगीभर कस्बाई चरित्र के भोले मानस बने रहे. मुंबई की भीड़-भाड़, पार्टियां और ग्लैमर चेहरों में वह कभी शामिल नहीं हो पाए. उनकी आखिरी इच्छा थी कि खंडवा में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाए. उनकी इस इच्छा को पूरा किया गया.

9 अटपटी बातों को अपने चटपटे अंदाज में कहना किशोर कुमार का फितूर था. ख़ासकर गीतों की पंक्ति को दाएं से बाएं गाने में उन्होंने महारत हासिल कर ली थी. उनसे नाम पूछने पर वे कहते थे- रशोकि रमाकु (किशोर कुमार).■

धमाल मचाने को तैयार जैकलीन

श्रीलंकन ब्यूटी जैकलीन फर्नांडिस *झलक दिखला जा* के जरिए टीवी की दुनिया में कदम रखने जा रही है. *झलक दिखला जा* के नए सीजन में करण जौहर और गणेश हेगड़े के साथ जैकलीन भी शो को जज करती हुई नज़र आएगी.

टीवी के मशहूर रियलिटी डांस शो *झलक दिखला जा* जल्द ही टीवी पर अपने अगले सीजन के साथ शुरू होने वाला है. इसी के साथ *झलक दिखला जा* के जरिए टीवी की दुनिया में कदम रखने जा रही है श्रीलंकन ब्यूटी जैकलीन फर्नांडिस. *झलक दिखला जा* के नए सीजन में करण जौहर और गणेश हेगड़े के साथ जैकलीन भी शो को जज करती हुई नज़र आएगी. पिछले साल ही माधुरी दीक्षित ने शो को छोड़ा था, जिसके बाद शाहिद कपूर को उनकी जगह शो का जज बनया गया था. लेकिन इस वर्ष शाहिद ने भी इस शो से किनारा कर लिया. जैकलीन ने बीते 3 जून को शो के लिए प्रोमो भी शूट कर लिया है. दरअसल, जैकलीन ने प्रोमो शूट के बाद अपनी अगली फिल्म *नॉट बैंग बैंग* की शूटिंग के लिए मियामी चली गई हैं. इन दिनों जैकलीन की झोली में कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसके जरिए वो आगे धमाल मचा सकती हैं. ■

जैकलीन ने बीते 3 जून को शो के लिए प्रोमो भी शूट कर लिया है. दरअसल, जैकलीन ने प्रोमो शूट के बाद अपनी अगली फिल्म *नॉट बैंग बैंग* की शूटिंग के लिए मियामी चली गई है.

ढिशूम

रोहित धवन निर्देशित ढिशूम में जैकलीन एक रॉ एजेंट की भूमिका में नज़र आने वाली है. फिल्म में उनके अपोजिट वरुण धवन और जॉन अब्राहम नज़र आएंगें. फिल्म 29 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.

फ्लाइंग जट्ट

रेमो डिसूजा निर्देशित फिल्म फ्लाइंग जट्ट एक साइंटिफिक फिक्शन पर आधारित है. इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ सुपरहीरो की भूमिका में हैं, साथ ही जैकलीन फिल्म में सुपर हीरो संग इश्क के पेंच लड़ाते हुए नज़र आएंगी.

नॉट बैंग-बंग 2

ब्लॉकबस्टर फिल्म बैंग-बंग का सीकवल नॉट बैंग-बैंग 2 में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ जैकलीन फर्नांडिस मुख्य भूमिका में नज़र आएगी. फिल्म की शूटिंग मिआमी सहित मलेशिया में होगी. इससे पहले फिल्म बैंग-बैंग में ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ धूम मचा चुके हैं.

हॉउसफुल-3

इससे पहले 3 जून को रिलीज़ हुइ जैकलीन की हॉउसफुल-3 ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा करोबार करते हुए 3 से 4 दिनों में वर्ल्ड-वाइल्ड 100 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है. साथ ही फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है.